17th Indian Cooperative Congress
17वाँ भारतीय सहकारी महासम्मेलन

रिपोर्ट एवं सिफारिशें
REPORT & RECOMMENDATIONS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रान्ति मार्ग,
3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
नई दिल्ली – 110 0 16
New Delhi - 110016

अंतर्वस्तु

पृष्ठभूमि 1

उद्घाटन सत्र 3

तकनीकी सत्र: 1 8

अनुकूल सहकारी कानून एवं नीतिगत सुधार

तकनीकी सत्र: 2 10

सहकारी आंदोलन को मजबूत करने हेतु क्रॉस सेक्टोरल सहयोग

तकनीकी सत्र: 3 14

सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य का सुदृढीकरण

तकनीकी सत्र: 4 19

प्रतिस्पर्धी सहकारी व्यावसायिक उद्यमों हेतु इज ऑफ डूइंग बिज़नेस (व्यवसाय करने में आसानी)

तकनीकी सत्र: 5 23

सहकारी शासन हेतु नवाचार एवं प्रौद्योगिकी

तकनीकी सत्र: 6 27

सहकारी समितियों के माध्यम से लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेश को बढ़ावा

तकनीकी सत्र: 7 31

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली का महत्व

समापन समारोह 36

अनुलग्नक 1 : कार्यक्रम अनुसूची.. 41

अनुलग्नक 2 : मॉडरेटर और प्रतिवेदकों की सूची 43

WHAT'S INSIDE

Background 1

Inaugural Session 3

Technical Session 1: Conducive Cooperative Legislation and Policy Reforms 8

Technical Session 2: Cross-sectoral Collaboration for Strengthening Cooperative Movement 10

Technical Session 3: Strengthening Cooperative Education, Training, and Research 14

Technical Session 4: Ease of Doing Business for Competitive Cooperative Business Enterprises 19

Technical Session 5: Innovation and Technology for Cooperative Governance 23

Technical Session 6: Promoting Gender Equality and Social Inclusion through Cooperatives 27

Technical Session 7: Importance of Cooperative Credit System in the Indian Economy 31

Valedictory Function 36

Annexure – 1: Programme Schedule 41

Annexure - 2: List of Moderators and Rapporteurs 43

पृष्ठभूमि

सहकारी समितियों ने इतिहास में समुदायों की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थापना के बाद वर्ष 1904 से सहकारी समितियाँ "सेवा और कल्याण उन्मुख संस्थाओं" से प्रगति कर में भारत की आजादी के बाद "सामाजिक-आर्थिक संस्थाएँ" बन गई हैं। सहकारी आंदोलन का उद्देश्य सदस्यों हेतु रोजगार पैदा करना, आय बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना हैं।

सहकारी समितियों ने देश में कृषि वित्तपोषण, उर्वरक उत्पादन एवं वितरण, चीनी और दूध उत्पादन तथा विपणन, गेहूं और धान की खरीद सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय के साथ ही सहकारी आंदोलन का स्वरूप बदला एवं विकास के अन्य क्षेत्रों की ओर भी अग्रसर हुआ। सहकारी आंदोलन के पुनरुत्थान और इसे मजबूत करने के लिए कई समितियों का गठन और नीतियों का निर्माण किया गया जिनका उद्देश्य सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर और स्वायत्त बनाना था।

21वीं सदी में भारत के बदलते व्यापारिक परिदृश्य और आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण के बढ़ने के साथ सहकारी समितियों को सामाजिक-आर्थिक संस्थाओं के रूप में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के एजेंडे के अनुरूप है।

सहकारिता आधारित आर्थिक विकास की क्षमता को पहचानते हुए प्रधानमंत्री जी ने सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने हेतु जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। सहकारिता मंत्रालय ने स्थापना के बाद से सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी और देश भर में उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), सहकारिता मंत्रालय की प्राथमिक "कार्यान्वयन एजेंसी" के रूप में सहकारी आंदोलन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा हैं और विकसित कर रहा है। वर्तमान में क्रेडिट, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि प्रसंस्करण, आवास और कई अन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

हालाँकि सहकारी उद्यमों की शक्ति और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं जिन्हें व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए। इन चुनौतियों में क्षेत्रीय असमानताएं, जटिल नियामक ढांचे, शासन और नेतृत्व में बाधाएं, कुशल पेशेवर प्रबंधन की कमी, पारदर्शिता की अनिवार्यता, मजबूत प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि की आवश्यकता जैसे कई कारक शामिल हैं। प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, संरचनात्मक बदलाव और विभिन्न सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना भी प्रमुख कारक हैं।

इन मुद्दों के समाधान और सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एनसीयूआई नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनों और प्रत्येक तीन से पांच साल के अंतराल पर सहकारी महासम्मेलनों की व्यवस्था करता है। यह मंच सहकारी समितियों से संबंधित मामलों पर गहन चर्चा और संवाद के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के कारण 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन दस साल के अंतराल पर किया गया। इस महासम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य सहकारी आंदोलन के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य देश के नए सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अभूतपूर्व पहलों के बारें में अवगत कराना भी है।

BACKGROUND

Throughout history, cooperatives have played a crucial role in addressing the socio-economic and cultural needs of communities. Since their inception in 1904, cooperatives have evolved from "Services and Welfare Oriented Entities" to becoming "Socio-Economic Entities" after India's independence. The cooperative movement aimed to generate employment, enhance income, and improve the standard of living of its members. Cooperatives have made significant contributions to various sectors in India, including agricultural financing, fertilizer distribution and production, sugar and milk production and marketing, and procurement of wheat and paddy. Over the time, moving away from its original goals the cooperative movement shifted its focus and transformed. To revive and strengthen the cooperative movement, several committees were formed, and policies were introduced, aimed to make cooperatives self-reliant and autonomous.

In the 21st century, with India's changing business landscape and the rise of modernization and commercialization, there is a need to reposition cooperatives as Socio-Economic Entities. This transformation aligns with the vision of "AtmaNirbhar Bharat" and the agenda of Sustainable Development Goals (SDGs).

Recognizing the potential of cooperation-led economic growth, the Prime Minister of India established the Ministry of Cooperation to provide a dedicated administrative, legal, and policy framework for bolstering the cooperative movement. Since its establishment in July 2021, the Ministry of Cooperation has taken various steps to facilitate ease of doing business for cooperatives and expand their reach across the nation.

The National Cooperative Union of India (NCUI), as the primary "Implementing Agency" of the Ministry of Cooperation, has been actively promoting and developing the cooperative movement. Ensuring equity in spread and outreach is a priority, and there is vast potential for promoting cooperatives in sectors like credit, dairy, fishery, agricultural processing, housing, and many more.

However, in order to ensure the vitality and sustained growth of cooperative enterprises, there are several critical issues that must be addressed comprehensively. These challenges encompass a range of factors such as regional and sectoral disparities, intricate regulatory frameworks, hurdles in governance and leadership, absence of skilled professional management, the imperative for transparency and the establishment of integrity, the need for robust training and capacity enhancement, adoption of relevant technologies, structural overhauls, and fostering collaboration among different cooperatives.

To engage with these issues and drive the cooperative movement forward, the NCUI regularly arranges zonal conferences and cooperative congresses at intervals of three to five years. These platforms serve as venues for in-depth discussions and dialogues on matters pertaining to cooperatives. It is noteworthy that, due to the impact of the COVID pandemic, there was a ten-year gap before the scheduling of the 17th Indian Cooperative Congress. The primary objective of this congress is to facilitate meticulous deliberations and exchanges focused on the challenges facing the cooperative movement. Additionally, it aims to highlight the groundbreaking initiatives introduced by the new Ministry of Cooperation, Govt. of India.

17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन

दिनांक 01 और 02 जुलाई, 2023 को आयोजित 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन ने सहकार की भावना के माध्यम से एक समृद्ध और जीवंत राष्ट्र के लिए एकजुट होने, विचार-विमर्श करने और दिशा तय करने हेतु पूरे भारत में सहकारी समितियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया हैं। इस महासम्मेलन का मुख्य विषय "अमृत काल: जीवंत भारत हेतु सहकार से समृद्धि" था, जिसमें सामूहिक विकास और एक मजबूत अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी (अनुलग्नक 1: कार्यक्रम अनुसूची)।

इस महासम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को प्रभावशाली, दक्ष और समावेशिता के एक नए युग में ले जाने के लिए नवीन रणनीतियों का पता लगाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना हैं। सम्मेलन के विषय का चयन सहकारी क्षेत्र को नई गतिशीलता प्रदान करना हैं जिससे कि यह देश की विकास यात्रा की आधारशिला बन सके।

इस महासम्मेलन में सात तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे जिनमें से प्रत्येक में सहकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण पहलू को

संबोधित किया गया। सभी सात सत्र इस प्रकार थे:-

1. अनुकूल सहकारी कानून एवं नीतिगत सुधार
2. सहकारी आंदोलन को मजबूत करने हेतु क्रॉस सेक्टोरल सहयोग
3. सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य का सुदृढीकरण
4. प्रतिस्पर्धी सहकारी व्यावसायिक उद्यमों हेतु इज ऑफ डूइंग बिज़नेस (व्यवसाय करने में आसानी)
5. सहकारी शासन हेतु नवाचार एवं प्रौद्योगिकी
6. सहकारी समितियों के माध्यम से लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना
7. भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली का महत्व

उपरोक्त सभी सात सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विचारक एक साथ एक मंच पर आसीन हुए और उनके मध्य सार्थक संवाद हुआ, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया गया तथा सहकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए योग्य कार्यवाही और आवश्यक अनुशंसाओं की भी पहचान की गई।

सत्र के कार्यक्रम के समृद्ध और व्यापक एजेंडे का उद्देश्य समकालीन समय में सहकारी समितियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना एवं अवसरों का पता लगाना हैं। सभी तकनीकी सत्रों को इस तरह डिजाइन किया गया जिसमें प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तनों को अपनाने से लेकर, युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर के नवाचारों को बढ़ाने तक के संपूर्ण दायरे को समाहित किया गया।

भारतीय सहकारी महासम्मेलन के 17वें संस्करण का सफल आयोजन सहकारिता के स्थायित्व की भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ एक समावेशी, समृद्ध और जीवंत भारत को आकार देने में सामूहिक प्रयासों की क्षमता का प्रदर्शन करता हैं। इस कार्यक्रम में हुई रणनीतिक, अंतर-क्षेत्रीय चर्चाओं और सहकारिता संबंधित नवीनतम जानकारियों के साझाकरण ने सहकारी समितियों के लिए नवाचार, लचीलेपन और साझा समृद्धि के साथ 21वीं सदी के जटिल परिदृश्य को समझने के लिए एक मजबूत नींव रखी।

मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (नैफेड) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया और इस महासम्मेलन को इनके द्वारा प्रायोजित भी किया गया।

17th Indian Cooperative Congress (ICC)

The 17th Indian Cooperative Congress, held on the 1st and 2nd of July 2023, served as a pivotal platform for cooperatives across India to converge, deliberate, and chart the course for a prosperous and vibrant nation through the spirit of collaboration. The event was meticulously organized with the theme “Amrit Kaal: Prosperity through Cooperation for a Vibrant India,” encapsulating the essence of collective growth and the potential of cooperation in shaping a robust economy (Annexure – 1: Programme Schedule).

With its roots deeply ingrained in India’s cooperative heritage, the congress aimed to explore innovative strategies and leverage technology to propel the cooperative movement into a new era of effectiveness, efficiency, and inclusivity. The choice of theme resonated with the aspiration to infuse the cooperative sector with renewed dynamism, making it a cornerstone of India’s development journey.

The congress comprised seven meticulously curated technical sessions, each addressing a critical facet of cooperative movement. The sessions were as follows:

1. Conducive Cooperative Legislation and Policy Reforms
2. Cross-sectoral Collaboration for Strengthening Cooperative Movement
3. Strengthening Cooperative Education, Training, and Research
4. Ease of Doing Business for Competitive Cooperative Business Enterprises
5. Innovation and Technology for Cooperative Governance
6. Promoting Gender Equality and Social Inclusion through Cooperatives
7. Importance of Cooperative Credit System in the Indian Economy

These sessions brought together distinguished experts, thought leaders, and practitioners from diverse fields, fostering meaningful dialogues, sharing best practices, and identifying actionable recommendations to bolster the cooperative ecosystem.

The event’s rich and comprehensive agenda aimed to address multifaceted challenges and opportunities faced by cooperatives in contemporary times. From embracing technology-driven transformations to fostering youth participation and amplifying grassroots innovations, the sessions were designed to encapsulate the entire gamut of cooperative excellence.

As the Indian Cooperative Congress convened its 17th edition, it stood as a testament to the enduring spirit of cooperation, showcasing the potential of collective endeavors in shaping an inclusive, prosperous, and vibrant India. The event’s strategic discussions, cross-sectoral interactions, and knowledge sharing laid a robust foundation for cooperatives to navigate the complex landscape of the 21st Century with innovation, resilience, and shared prosperity.

The 17th ICC was marked by the pivotal support and sponsorship provided by three esteemed entities, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), and Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO).

17वें महासम्मेलन के अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों की झलक।

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन में विविध सहकारी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3500 से अधिक प्रतिभागी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति एवं इस दौरान किए गए गहन विचार-विमर्श ने सम्मेलन को जीवंत बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया।

इस महासम्मेलन में सहकारिता के सभी स्तरों को एक सूत्र में पिरोया गया, जिसमें सहकारी आंदोलन के विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया। 17वें महासम्मेलन में न केवल कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों वरन् दो करोड़ से अधिक प्रतिभागियों की ऑनलाइन उपस्थिति ने सभी भौगोलिक सीमाओं को पार किया। इस लाइव ऑनलाइन प्रसारण ने वास्तव में बड़े पैमाने पर ज्ञान प्रसार, सहयोग और प्रेरणा के लिए एक गतिशील मंच के रूप में सम्मेलन की भूमिका को रेखांकित किया।

महासम्मेलन में सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो सहकारी नीतियों पर सरकारी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। विभिन्न देशों के सहकारिता से जुड़े प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इसमे एक अंतरराष्ट्रीय आयाम जोड़ा जिससे काफी कुछ सीखने को मिला और सहकारिता को भी बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों, बहु-राज्य सहकारी समितियों, राज्य और जिला स्तर के संघों और प्राथमिक सहकारी समितियों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशक मंडल और सदस्य गणो ने संपूर्ण सहकारी परिदृश्य का व्यापक प्रतिनिधित्व किया।

सहकारिता व विविध क्षेत्रों से पधारे प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने सभी सात तकनीकी सत्रों में की गई चर्चा को और भी अधिक समृद्ध बनाया। यह सभी सत्र विचारों, अनुभवों और चुनौतियों का आदान-प्रदान करने और भारत में सहकारी समितियों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित थे। विविध क्षेत्रों से पधारे प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने व्यापक संवाद और सहयोग के मंच के रूप में सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया।

17वें महासम्मेलन के सफल आयोजन ने न केवल सहकारिता की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला बल्कि देश में सहकारी समितियों के भविष्य को आकार देने में सामूहिक भागीदारी के बल का भी प्रदर्शन किया। विभिन्न देशों एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने सहकारी आंदोलन की शक्ति और परिवर्तन की क्षमता के एक गतिशील प्रतिबिंब के रूप में कार्य किया।

उद्घाटन

17वें महासम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम 01 जुलाई, 2023 को सुबह 11 बजे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह- कन्वेंशन सेंटर (IECC), प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुआ। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने की। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथियों में श्री बी.एल वर्मा, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्रालय, डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत (आईसीए-एपी) एवं कृभको उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सचिव, अतिरिक्त सचिव और केन्द्रीय पंजीयक सहकारी समिति, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार सहित उच्च पदस्थ अधिकारी भी उपस्थित थे। भारत के विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्री, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस आयोजन का उद्देश्य मुख्य रूप से सहकारी समितियों के भविष्य और सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर रचनात्मक चर्चा के लिए माहौल तैयार करना था।

17वें सहकारी महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथिगण ।

A glimpse of dignitaries on the occasion

The success and impact of the 17th ICC were greatly amplified by the diverse and engaged audience, which included more than 3500 participants representing a wide spectrum of cooperative stakeholders. The event was graced by the presence of distinguished individuals, contributing to the congress' vibrancy and depth of discussions.

The event showcased a microcosm of the cooperative ecosystem, bringing together representatives from various strata of the cooperative movement. The 17th ICC not only resonated within the physical walls of the event venuebut also transcended geographical boundaries through its online mode, with an astounding attendance of over 2 crore participants. This virtual outreach underscored the congress's role as a dynamic platform for knowledge dissemination, collaboration, and inspiration, on a truly massive scale.

The audience comprised representatives of the Ministry of Cooperation officials, providing governmental insights and perspectives on cooperative policies. The presence of fraternal delegates added an international dimension, fostering cross-border learning and collaboration. The congregation of chairpersons, managing directors, board of directors and members from national-level cooperative federations, multi-state cooperatives, state and district level federations, and primary cooperatives ensured a comprehensive representation of the cooperative landscape.

The active participation of such a diverse audience enriched the discussions across the seven technical sessions. The exchange of ideas, experiences, and challenges was underpinned by a shared commitment to fostering the growth and development of cooperatives in India. The presence of this multifaceted audience underscored the congress's significance as a platform for comprehensive dialogue and collaboration.

The event not only highlighted the power of cooperation but also demonstrated the strength of collective engagement in shaping the future of cooperatives in India. The diverse audience, including fraternal delegates, served as a dynamic reflection of the cooperative movement's vitality and potential for transformation.

Inaugural Session

The inaugural program took place on 1st July 2023 at 11 AM in the plenary hall of the International Exhibitioncum Convention Centre (IECC), Pragati Maidan, New Delhi. The esteemed event was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji and was presided over by Shri Amit Shah Ji, the Union Home and Cooperation Minister, Government of India. Among the distinguished attendees were also Shri B L Verma, the Hon'ble Minister of State for Cooperation, Ministry of Cooperation, and Dr. Chandrapal Singh Yadav, President, International Cooperative Alliance - Asia Pacific (ICA-AP). The event witnessed the presence of high-ranking officials including the Secretary and Additional Secretary & CRCS, Ministry of Cooperation, Govt. of India, Cooperation Ministers various States as well as senior officers and staff members of the Ministry. Additionally, the Registrar of Cooperative Societies and various state functionaries graced the occasion with their presence. The event aimed to mark the beginning of the 17th Indian Cooperative Congress 7 and set the tone for constructive discussions on the future of cooperatives and the initiatives undertaken by the Ministry of Cooperation.

Chief Guests and other guests on dais on the occasion of 17th ICC inauguration session.

सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में नाट्य "धरती कहे पुकार के" के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति।

उद्घाटन समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कलाकारों की प्रस्तुति को देखते हुए।

श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष भा०रा०स०संघ एवं इफको और डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, आईसीए-एपी एवं कृभको उद्घाटन समारोह पर श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए।

उद्घाटन समारोह के दौरान एक नाट्य प्रस्तुति "धरती कहे पुकार के" का मंचन किया गया जिसमें दो युवा छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति दी। नाट्य मुख्यतः पारंपरिक रसायन-आधारित खेती के स्थान पर प्राकृतिक और जैविक खेती प्रथाओं को अपनाने के महत्व के बारें में थी। इस प्रस्तुति ने न केवल कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार किया बल्कि प्रभावी ढंग से सतत कृषि का संदेश भी दिया। "धरती कहे पुकार के" नाट्य के कलाकारों ने पर्यावरण के अनुकूल कृषि तकनीकों की ओर बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया जो मिट्टी और उपभोक्ताओं दोनों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है। कार्यक्रम के आरंभ में ही इस मार्मिक अभिनय ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि सहकारी आंदोलन के व्यापक कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल एवं पारिस्थितिक रूप से संतुलित भविष्य के पोषण के प्रति साझा जिम्मेदारी को भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया।

*An Artist performs in the inaugural ceremony on the theme of **"Dharti Kahe Pukar Ke"***

The inauguration program commenced with a captivating performance by two young girl students. Their presentation centered on the theme of **"Dharti Kahe Pukar Ke,"** which resonated with the significance of embracing natural and organic farming practices over conventional chemical-based methods. The performance not only set the tone for the event but also effectively conveyed the message of sustainable agriculture. By emphasizing the call of the earth Dharti Kahe Pukar Ke, the students underscored the urgent need to shift towards environmentally friendly farming techniques that prioritize the health of both the soil and the consumers. This poignant opening act not only captured the audience's attention but also eloquently symbolized the broader mission of the cooperative movement and the shared responsibility towards nurturing a healthier, more ecologically balanced future.

Distinguished guests observed the performance of an Artist in the inaugural ceremony of 17th Indian Cooperative Congress

Shri Dileep Sanghani, President NCUI and Chairman, IFFCO and Dr. Chandrapal Singh Yadav, President, ICA-AP and Chairman, KRIBHCO giving a memento to Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on the inauguration ceremony of the 17th Indian Cooperative Congress

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के अवसर पर श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, भा०रा०सह०संघ संबोधित करते हुए।

श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष भा०रा०सह०संघ ने इस शुभ अवसर पर सभी प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों, सम्मानित अतिथियों और साथी सहयोगियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

उन्होंने इस आयोजन का उद्घाटन करने और सहकारी क्षेत्र के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री संघाणी ने सहकारी आंदोलन के महत्व को पहचानने और सहकारी क्षेत्र को समर्पित एक नया मंत्रालय स्थापित करने के ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को सौंपने के निर्णय की भी सराहना की जिन्होंने सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देने में संपूर्ण समर्पण और सुदृढ़ नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त सहकारिता के भविष्य को एक नया आयाम देने हेतु माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत (आईसीए-एपी) एवं कृभको अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव की भूमिका और प्रभावशाली नेतृत्व का भी उल्लेख किया।

श्री संघाणी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सहकारी समितियों के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना सहकारी तंत्र को मजबूत करने और देश भर में लाखों सहकारी सदस्यों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह कदम सहकारी आंदोलन को मजबूत एवं समृद्ध करेगा तथा समावेशी भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।

श्री संघाणी ने आशा व्यक्त की कि माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि और प्रगति होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह का मजबूत सरकारी समर्थन, सहकारी समितियों को नई चुनौतियों का सामना करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में और भी अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि महासम्मेलन का मूल विषय "अमृत कालः जीवंत भारत हेतु सहकार से समृद्धि, सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सहकार के सार का प्रतीक है। उन्होंने भविष्य में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए सहकारी समितियों के बीच रचनात्मक चर्चा और ज्ञान के आदान-प्रदान की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित सात तकनीकी सत्रों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया जो जीवंत भारत के लिए सहकार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होंगे।

श्री अमित शाह, माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, सम्मेलन के अवसर पर बोलते हुए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भा०रा०सह०संघ अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी और 17वीं भारतीय सहकारी महासम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों की हार्दिक सराहना के साथ की। देश भर में कृषि ऋण वितरण (29%), उर्वरक (25%), चीनी (35%), और गेहूं उत्पादन (13%) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण योगदान की पुरजोर सराहना की। इसके अलावा उन्होने सामाजिक-आर्थिक विकास, ऋण, आवास और मत्स्य पालन में सहकारी समितियों के प्रभाव को रेखांकित करते हुए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

इस अवसर पर उन्होंने सहकारिता मंत्रालय द्वारा बीते दो साल में की गई प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सहकारी गतिविधियों के केंद्रीय केंद्र में बदलने की रणनीतिक दृष्टि पर जोर दिया। आगे उन्होंने कहा कि पैक्स को सहकारी कार्यों हेतु केन्द्रीय बिन्दु स्थापित कर मंत्रालय का लक्ष्य ग्रामीण विकास और आवश्यक सेवा प्रदाताओं के सुविधा प्रदाता के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत करना है।

Shri Dileep Sanghani, President, NCUI addressing on the occasion of 17th Indian Cooperative Congress

Shri Dileep Sanghani, President, NCUI extended a warm welcome to all distinguished delegates, esteemed guests, and fellow cooperators, who gathered on this auspicious occasion.

He expressed gratitude to the Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi for inaugurating the event, and for his unwavering support towards the cooperative sector. Shri Sanghani specifically thanked the Hon'ble Prime Minister for recognizing the importance of the cooperative movement and taking a historic step by establishing a new Ministry dedicated to the cooperative sector. He also appreciated the decision to entrust the charge of this crucial Ministry to the Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah, who has displayed immense dedication and leadership in promoting cooperative endeavors. Moreover, the presence of the Hon'ble Minister of State for Cooperation Shri B. L. Verma and the International Cooperative Alliance – Asia Pacific (ICA-AP) President Dr. Chandrapal Singh Yadav, further emphasizes the importance of cooperatives in shaping our nation's future.

Shri Sanghani highlighted that the establishment of a dedicated Ministry for cooperatives signifies the government's commitment to strengthening the cooperative ecosystem and empowering millions of cooperative members across the country. This development, he stated, would further bolster the cooperative movement and pave the way for a more prosperous and inclusive India.

Shri Sanghani expressed his optimism that under the leadership of the Hon'ble Home and Cooperation Minister, the cooperative sector would witness remarkable growth and progress. He emphasized that such strong government support would encourage cooperators to take on new challenges and contribute even more effectively towards the socio-economic development of the nation.

The President, NCUI highlighted that the theme "Amrit Kaal: Prosperity through Cooperation for a Vibrant India" symbolized the essence of cooperation in fostering socio-economic development and empowerment. He underscored the need for constructive discussions and knowledge exchange among the cooperators to identify challenges and opportunities that lie ahead. He urged all participants to engage actively in the seven technical sessions planned during the congress, which focused on critical aspects of cooperation for a vibrant India.

Shri Amit Shah, Hon'ble Home and Cooperation Minister for Cooperation, Govt. of India commenced his address with sincere appreciation to the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, Shri. Dileep Sanghani, President NCUI,and all present at the 17th Indian Cooperative Congress. He lauded the significant contributions of cooperatives in various sectors, such as agricultural credit distribution (29%), fertilizer (25%), sugar (35%), and wheat production (13%). Furthermore, the Minister emphasized the crucial role of cooperatives in credit, housing, and fisheries, underscoring their impact on socio-economic development.

The Minister also took the opportunity to highlight the key initiatives undertaken by the Ministry of Cooperation during its two-year journey. He emphasized the strategic vision to transform Primary Agricultural Credit Societies (PACS) into central hubs of cooperative activities. By positioning PACS at the core of cooperative operations, the Ministry aims to strengthen their role as facilitators of rural development and essential service providers.

Shri Amit Shah, Hon'ble Home and Cooperation Minister for Cooperation speaking on the occasion of 17th Indian Cooperative Congress

पैक्स पर चर्चा करते हुए उन्होंने उनके कामकाज में एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों को भेजी गई सलाह पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 26 राज्यों ने पहले ही मॉडल उपनियमों को स्वीकार कर लिया है जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि 85% पैक्स समान दिशानिर्देशों के तहत काम करेंगे, उनके संचालन को सुव्यवस्थित किया जाएगा और ग्रामीण सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा।

आगे उन्होने खुदरा दुकानों को बढ़ाने की पहल और खाद्य भंडारण योजना की सफल मंजूरी को साझा किया जिसे यदि लागू किया गया तो खाद्य भंडारण प्रणाली में सहकारी क्षेत्र की इक्विटी पांच वर्षों के भीतर 35 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

सहकारी क्षेत्र को समर्पित अलग से एक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के लिए माननीय प्रधानमंत्री के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा सहकारी वृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को गति देता है बल्कि राष्ट्र के सहकारी ताने-बाने को भी मजबूत करता है।

अंत में सहकारिता मंत्री ने बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन के बारे में बात की, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को अन्य कई क्षेत्रों के अनुकूल बनाना है और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने देश की सहकारी समितियों के एक व्यापक डेटाबेस के विकास पर भी चर्चा की जिसका काम लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जिससे बेहतर पहुंच और योजना बनाने में सुविधा होगी।

इसके अतिरिक्त उन्होंने एक समृद्ध और समावेशी सहकारी क्षेत्र को आकार देने में आत्म-अनुशासन के माध्यम से पारदर्शिता और अनुकूलनशीलता के महत्व को दोहराया एवं उसकी भूमिका पर बल दिया। अंत में उनके द्वारा आशा व्यक्त की गई कि सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों एवं सहकारिता की शक्ति के माध्यम से देश को और आगे जाने में सफलता मिलेगी।

"एनसीयूआई हाट" और "सीईएएस एलएमएस पोर्टल" का शुभारंभ

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की शोभा बढ़ाई और उन्होंने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भा०रा०सह०संघ की महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। पहला "एनसीयूआई हाट", ई-कॉमर्स पोर्टल जो देश भर में विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित उत्पादों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करने और विपणन करने के लिए समर्पित है। यह डिजिटल बाज़ार न केवल सहकारी उत्पादों की पहुंच का विस्तार करेगा बल्कि मुख्यधारा के बाजारों में उनके एकीकरण को भी बढ़ावा देगा, जिससे आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री "ई-कॉमर्स पोर्टल" और "सीईएएस पोर्टल" का लॉन्च करते हुए।

दूसरा प्लेटफॉर्म "सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा (सीईएएस) पोर्टल", अत्याधुनिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) से सुसज्जित है। इस पोर्टल का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना और सहकारी समितियों को शैक्षिक संसाधन प्रदान करना, ज्ञान देना और सर्वोत्तम पद्धतियों प्रथाओं का प्रसार सुनिश्चित करना है। "एलएमएस कौशल विकास", क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा जो सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सशक्त बनाएगा।

"एनसीयूआई हाट" के माध्यम से सहकारी समितियों को उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी जिससे बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा और उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस कदम से लाखों सहकारी सदस्यों और कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत सरकार के "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" के विचार को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा पोर्टल (सीईएएस) एलएमएस के साथ एक ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा जो सहकारी समुदाय के भीतर निरंतर सीखने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ाएगा। यह ज्ञान के अंतर को पाटेगा और नवीनतम तकनीकी जानकारी के साथ सहकारी समितियों को सशक्त बनाएगा। इसके अतिरिक्त समसामयिक चुनौतियों से निपटने और नए अवसरों का पता लगाने के लिए भी सक्षम बनाएगा।

इन दोनों पोर्टलों को लॉन्च करने के बाद सहकारिता मंत्रालय और एनसीयूआई की नई पहलों को प्रदर्शित करते हुए एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए ठोस प्रयासों को दर्शाया गया। सम्मेलन में बैठे हुए प्रतिनिधि फिल्म से काफी प्रेरित हुए। उन्होंने सहकारी आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सहकार तथा सहभागिता की अटूट भावना की पुष्टि की।

Discussing PACS, the Minister highlighted the advisory sent to all states, promoting uniformity in their functioning. He reported that 26 states had already accepted the Model Bye-laws, ensuring that 85% of PACS would operate under the same guidelines, streamlining their operations and augmenting rural facilities.

The Minister shared initiatives to enhance retail outlets and the successful approval of the Khadyan Bhandaran Yojana, which, if implemented, would elevate the cooperative sector's equity in the food storage system to 35% within five years.

Expressing profound gratitude to the Hon'ble Prime Minister for establishing a separate Mantralaya dedicated to the cooperative sector, the Minister reinforced the government's commitment to nurturing cooperative growth and development. He enthusiastically encouraged the active inclusion of youth and women in cooperatives, as it not only accelerates their personal growth but also strengthens the cooperative fabric of the nation.

Towards the end, the Minister spoke about the amendment of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, aimed at making cooperatives more versatile and adaptable to multiple sectors, thus fostering holistic development. He also discussed the development of a comprehensive database of the country's cooperatives, nearing 90% completion, which would facilitate better accessibility and planning.

In conclusion, the Minister reiterated the significance of transparency and adaptability through self-discipline, stressing their role in shaping a prosperous and inclusive cooperative sector. With the collective efforts of all stakeholders, he expressed optimism in driving India towards a brighter future through the power of cooperation.

Launching of the "NCUI Haat" and "CEAS – LMS Portal"

The Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, graced the 17th Indian Cooperative Congress with his esteemed presence, and in an auspicious moment, he launched two groundbreaking initiatives to strengthen the cooperative sector. The first platform, "NCUI Haat", is an e-commerce portal dedicated to showcasing and marketing the diverse range of products produced by various cooperatives across the nation. This digital marketplace will not only expand the reach of cooperative products but also promote their integration into mainstream markets, fostering economic growth and self-sustainability.

Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India launching the e- commerce portal and Cooperative Extension and Advisory Services (CEAS) Portal.

The second platform, the Cooperative Extension and Advisory Services (**CEAS**) **Portal**, comes equipped with a state-of-the-art Learning Management System **(LMS).** This portal aims to create mass awareness and provide educational resources to cooperators, ensuring the dissemination of knowledge and best practices. The LMS will serve as a hub for skill development, capacity building, and training, empowering cooperators to embrace modern techniques and technologies.

Through the "NCUI Haat," cooperatives will gain direct access to consumers, thereby eliminating intermediaries and ensuring fair prices for both producers and consumers. This step is expected to boost the livelihoods of millions of cooperative members and artisans, promoting the ethos of "Vocal for Local" and "Atmanirbhar Bharat."

Furthermore, the Cooperative Extension and Advisory Services Portal with its LMS will serve as a knowledge hub, nurturing a culture of continuous learning and innovation within the cooperative community. It will bridge the knowledge gap, empower cooperators with the latest technical know-how, and equip them to address contemporary challenges and explore new opportunities.

After launching these two portals, a captivating film was screened, showcasing the new initiatives of the Ministry of Cooperation and NCUI. The film depicted the concerted efforts undertaken to empower cooperatives, promote rural entrepreneurship, and foster inclusive growth. The audience was deeply inspired by the film, reaffirming their commitment to the cooperative movement and its unwavering spirit of cooperation and collaboration.

श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के अवसर पर संबोधित करते हुए।

श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में एक विकसित दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सरकार और सहकारी समितियों ("सहकार") के बीच महत्वपूर्ण सहयोग करते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि "सरकार और सहकार" मिलकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को दोगुनी ताकत प्रदान करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रगति की दिशा में इस यात्रा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है जहां "सबका प्रयास" इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाता है। सहकार और सामूहिक संकल्प की भावना एक समावेशी और समृद्ध भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारी क्षेत्र की प्रगति आंतरिक रूप से भारत की विकास कहानी से जुडी हुई है। सहकारी समितियाँ सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान और समुदायों को सशक्त बनाने के आवश्यक एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। उन्होंने दूध उत्पादन में भारत की अग्रणी स्थिति और इस उपलब्धि में डेयरी सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक के रूप में भारत की प्रमुखता पर प्रकाश डाला और इस सफलता का श्रेय सहकारी चीनी मिलों के ठोस प्रयासों को दिया।

सहकारी समितियों हेतु एक अलग मंत्रालय स्थापित करने पर उन्होंने गर्व व्यक्त किया। उन्होंने सहकारी समितियों के लिए कर के बोझ में कमी की सराहना की जो कि उनके विकास और स्थिरता का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं।

किसानों की महत्वपूर्ण भागीदारी को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पिछले नौ वर्षों में उठाए गए उपायों की रूपरेखा दी। उन्होंने करोड़ों किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि लाभ के वर्तमान प्रत्यक्ष हस्तांतरण के साथ पिछले न्यूनतम समर्थन की तुलना की जो अक्सर बिचौलियों द्वारा ले लिया जाता था। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में इस पहल के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपये का पारदर्शी हस्तांतरण हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसे प्रासंगिक बताते हुए कहा कि यह राशि 2014 से पहले के पांच वर्षों के कुल कृषि बजट से अधिक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस एकल योजना के लिए उस बजट से तीन गुना अधिक आवंटित किया गया था।

प्रधानमंत्री ने किसानों पर बढ़ती वैश्विक उर्वरक कीमतों के प्रभाव को कम करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने उर्वरक की लागत में भारी असमानताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जहां एक भारतीय किसान के लिए यूरिया की एक बोरी की कीमत लगभग 270 रुपये है, वहीं उसी बोरी की कीमत बांग्लादेश में 720 रुपये, पाकिस्तान में 800 रुपये, चीन में 2100 रुपये और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 3000 रुपये है। किसानों के जीवन में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका उदाहरण इन विरोधाभासों से मिलता है। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने उर्वरक सब्सिडी पर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया हैं।

किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का उल्लेख किया और पिछले 9 वर्षों में किसानों को 15 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया। उन्होंने बताया कि कृषि और किसानों पर सरकार का वार्षिक खर्च 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है जो किसानों को सालाना लगभग 50 हजार रुपये का समर्थन देने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है।

किसान-केंद्रित दृष्टिकोण को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए 3.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज और 315 रुपये प्रति क्विंटल के उचित मूल्य का उल्लेख किया जिससे किसानों और चीनी मिल श्रमिकों दोनों को लाभ हुआ हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने परिवर्तनकारी "अमृत काल" के दौरान ग्रामीण और किसान विकास में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार और सहकारी समितियां मिलकर विकसित भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री ने कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और डिजिटल प्रणालियों के प्रयोग को सहकारिता की सफलता से जोड़ा और ऊपरी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म करने में उनके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सहकारी क्षेत्र से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने डिजिटल लेनदेन के लिए भारत की वैश्विक मान्यता को रेखांकित किया और सहकारी समितियों और बैंकों को इस क्षेत्र में नेतृत्व करने व बाजार में पारदर्शिता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने 60,000 से अधिक प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों (पैक्स) के चल रहे कम्प्यूटरीकरण पर प्रकाश डाला जिसका लक्ष्य उन्हें पारदर्शिता के मॉडल के रूप में स्थापित करना है। सहकारी समितियों से उपलब्ध प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का आग्रह किया और इस बात पर भी जोर दिया कि कोर बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन को अपनाने से राष्ट्र को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister addressing on the occasion of 17th Indian Cooperative Congress

Hon'ble Shri Narendra Modi, Prime Minister of India commenced his Inaugural Address at the 17th Indian Cooperative Congress, emphasizing the crucial collaboration between the government ("Sarkar") and cooperatives ("Sahakar") to fulfill the vision of a developed and self-reliant India. He reaffirmed that together, "Sarkar and Sahakar" would provide double strength to the dream of a "Viksit" and "Aatmanirbhar Bharat." He articulated that this journey towards progress requires collective efforts, where "Sabka Prayas" plays a transformative role in achieving these goals. The spirit of cooperation, collaboration, and collective determination will pave the way for an inclusive and prosperous India.

Shri Modi expressed his unwavering belief that the cooperative sector's progress is intrinsically linked to India's development story. Cooperatives act as essential agents of socio-economic change, uplifting rural economies and empowering communities. He acknowledged India's leading position in milk production and the significant contribution of dairy cooperatives to this achievement. Moreover, he highlighted India's prominence as one of the largest sugar-producing countries, attributing this success to the concerted efforts of cooperative sugar mills.

The Prime Minister expressed his pride in establishing a separate Mantralaya for cooperatives, emphasizing the benefits of this dedicated focus on the sector. He commended the reduction in tax burdens for cooperatives, reflecting the government's commitment to supporting their growth and sustainability.

Recognizing the significant farmer turnout, the Prime Minister outlined measures taken over the last nine years for farmers' welfare. He contrasted the past minimal support, often eroded by intermediaries, with the current direct transfer of Kisan Samman Nidhi benefits to crores of farmers' accounts. He shared that over the past four years, a transparent transfer of 2.5 lakh crore rupees had occurred under this initiative. The Prime Minister contextualized this by noting that this amount surpasses the total agricultural budget of five years before 2014, emphasizing that over three times that budget had been allocated to this single scheme.

The Prime Minister further discussed strategies to alleviate the impact of rising global fertilizer prices on farmers. He highlighted the stark disparities in fertilizer costs: while a bag of urea costs around Rs 270 for an Indian farmer, the same bag is priced at Rs 720 in Bangladesh, Rs 800 in Pakistan, Rs 2100 in China, and Rs 3000 in the USA. The Prime Minister emphasized the need for significant efforts to transform farmers' lives, exemplified by these contrasts. He revealed that over the past 9 years, the government had expended more than Rs 10 lakh crore solely on fertilizer subsidies.

Underscoring the government's commitment to ensuring fair prices for farmers' produce, the Prime Minister noted increased Minimum Support Prices (MSP) and disbursed over 15 lakh crores to farmers in the last 9 years. He conveyed that the government's annual expenditure on agriculture and farmers exceeds 6.5 lakh crores, reflecting its dedication to supporting farmers with around 50 thousand rupees annually.

Continuing the farmer-centric approach, the Prime Minister mentioned a recent package of Rs 3.7 lakh crore and a fair price of Rs 315 per quintal for sugarcane farmers, benefiting both farmers and sugar mill workers.

The Prime Minister emphasized the pivotal role of the cooperative sector in rural and farmer growth during the transformative "Amrit Kaal." He stressed that the government and cooperatives together would bolster the vision of a developed India. The Prime Minister linked transparency and digital systems to cooperation's success, underscoring their importance in eradicating corruption and nepotism from the upper echelons. He urged the cooperative sector to adopt digital systems to ensure transparency and corruption-free governance, thus becoming a model of good practice.

The Prime Minister underscored India's global recognition for digital transactions and encouraged cooperative societies and banks to lead in this area, enhancing market transparency, efficiency, and competition.

He highlighted the ongoing computerization of over 60,000 Primary Level Cooperative Societies (PACS), aiming to establish them as models of transparency. The Prime Minister urged cooperatives to leverage available technology,

उन्होने सहकारी समितियों से भारत के रिकॉर्ड निर्यात में योगदान देने का आग्रह किया और विनिर्माण क्षेत्र में सहकारी समितियों के लिए कर कटौती पर प्रकाश डाला। उन्होंने डेयरी क्षेत्र की निर्यात क्षमता का भी उल्लेख किया और "श्री अन्न" (मिलेट) जैसे भारतीय उत्पादों के वैश्विक प्रचार पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों के समर्थन के उपायों पर चर्चा की जिसमें बकाया भुगतान के लिए 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज और इथेनॉल मिश्रण को प्राथमिकता देना शामिल है। उन्होंने मिशन पाम ऑयल जैसी पहल का हवाला देते हुए खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने पीएम मत्स्य सम्पदा योजना की सफलता की सराहना की और मत्स्य पालन में सहकारी समितियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने मछली पालन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) जैसी पहल का उल्लेख किया जिसमें बाजार में छोटे किसानों को सशक्त बनाने की उनकी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी समितियों से विकास को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सेवाएं और जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने रसायन मुक्त खेती, गोबरधन योजना के तहत अपशिष्ट से धन परियोजनाओं और डेयरी और पशुपालन में प्रगति का समर्थन करने वाली पहलों पर चर्चा की। उन्होंने सहकारी समितियों को जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई जैसे विभिन्न सरकारी मिशनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण के महत्व पर प्रकाश डाला और केंद्र सरकार की भंडारण योजना का उल्लेख किया। उन्होंने फार्मगेट बुनियादी ढांचे के विकास में सहकारी समितियों की भूमिका पर भी जोर दिया।

अंत में प्रधानमंत्री ने नए भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक योगदानकर्ताओं के रूप में सहकारी समितियों पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने आत्मनिर्भर गावों के निर्माण में सहकारी मॉडल की भूमिका की सराहना की जो कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में राजनीति से अलग रहकर कार्य करती है।

तकनीकी सत्र -1: अनुकूल सहकारी कानून एवं नीतिगत सुधार

श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) एवं इफको की अध्यक्षता में 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का पहला तकनीकी सत्र "अनुकूल सहकारी कानून और नीतिगत सुधार" शुरू हुआ। सत्र के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित वक्ताओं ने भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में नीतिगत सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार साझा किए।

अध्यक्ष : श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एवं इफको

वक्ता :-

1. श्री बी. एल. मीना, आईएएस, प्रमुख सचिव (सहकारिता), उत्तर प्रदेश सरकार
2. श्री मोहम्मद अकबर वानी, आईएएस, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जम्मू-कश्मीर सरकार
3. श्री आलोक अग्रवाल, संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्री प्रकाश पी. नाइकनवरे, प्रबंध निदेशक, नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली।

श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी, भा०रा०सह० संघ- तकनीकी सत्र की मॉडरेटर।

श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी भा०रा० सह०संघ एवं मॉडरेटर तकनीकी सत्र -1 ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया और श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष भा०रा० सह० संघ एवं इफको और पैनल के सदस्यों का परिचय कराया और तकनीकी सत्र-1 की शुरुआत की। उन्होंने सत्र के उद्देश्य को दोहराया और सहकारी समितियों को फलने-फूलने के लिए एक सक्षम कानूनी और नीतिगत ढांचा बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

श्री दिलीप संघाणी ने अपने उद्घाटन भाषण में सहकारी समितियों को सामाजिक-आर्थिक विकास का इंजन बनने के लिए सशक्त बनाने में सहकारी कानून और नीति सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी नेताओं और नीति निर्माताओं को देश भर में सहकारी समितियों के विकास और स्थिरता के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नए सहकारी कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला जिनका उल्लेख 17 वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा अपने उद्बोधन में किया गया।

emphasizing that embracing core banking and digital transactions would yield significant benefits for the nation.

The Prime Minister urged cooperatives to contribute to India's record exports and highlighted tax reductions for cooperatives in the manufacturing sector. He showcased the dairy sector's export prowess and advocated for the global promotion of Indian products like "Shree Anna" (millets).

The Prime Minister discussed measures supporting sugarcane farmers, including a Rs 20,000 crore package to clear dues and the prioritization of ethanol blending. He emphasized the push for self-reliance in edible oil production, citing initiatives such as Mission Palm Oil. He lauded the success of the PM Matsya Sampada Yojana and encouraged cooperatives' involvement in fisheries.

The Prime Minister expanded on the growth of cooperative societies in various sectors, including fish farming and inland fisheries. The Prime Minister mentioned initiatives like Farmer Producer Organizations (FPOs), emphasizing their potential to empower small farmers in the market. He urged cooperatives to provide services and information to farmers, fostering growth.

The Prime Minister discussed initiatives supporting chemical-free farming, waste-to-wealth projects under the Gobardhan Scheme, and advancements in dairy and animal husbandry. He encouraged cooperatives to participate in various government missions, such as water conservation and micro-irrigation. He highlighted the significance of storage for food security and noted the central government's storage scheme. He emphasized cooperatives' role in farmgate infrastructure development.

In conclusion, the Prime Minister expressed confidence in cooperatives as vital economic contributors in the new India. He advocated for self-sufficient villages following the cooperative model, emphasizing cooperation's role in societal and national policies rather than politics.

Technical Session 1: Conducive Cooperative Legislation and Policy Reforms

The first technical session of the 17th Indian Cooperative Congress, chaired by Shri Dileep Sanghani, President of the National Cooperative Union of India (NCUI) and Chairman of IFFCO, focused on "Conducive Cooperative Legislation and Policy Reforms". Esteemed speakers from various sectors shared their views and insights during the session, shedding light on the significance of policy reforms in strengthening the cooperative movement in India.

Chair : Shri Dileep Sanghani, President National Cooperative Union of India & Chairman, IFFCO

Speakers:

1. Shri B. L. Meena, IAS Principal, Secretary (Cooperation), Govt of U.P.
2. Shri Mohammad Akbar Wani, IAS Registrar Cooperative Societies, Government of J&K
3. Shri Alok Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Cooperation, GoI
4. Shri Prakash P Naiknavare, Managing Director, National Federation of Co-operative Sugar Factories Ltd. New Delhi

A view of Technical Session 1: Conducive Cooperative Legislation and Policy Reforms

The session commenced with **Smt. Savitri Singh, Deputy Chief Executive, NCUI** welcoming the attendees and introducing the esteemed Chair, Shri Dileep Sanghani, President of NCUI and Chairman of IFFCO and panel members. She reiterated the session's objective and highlighted the importance of creating an enabling legal and policy framework for cooperatives to thrive.

Shri Dileep Sanghani, in his opening address, emphasized the pivotal role of cooperative legislation and policy reforms in empowering cooperatives to become engines of socio-economic development. He encouraged cooperative leaders and policymakers to work collaboratively to create a conducive ecosystem for the growth and sustainability of cooperatives across the country. He highlighted the initiatives taken by the government to promote new cooperative laws and policies, as mentioned by the Hon'ble Prime Minister and the Minister for Home & Cooperation, during the inaugural session of the 17th Indian Cooperative Congress.

श्री बी. एल. मीना, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (सहकारिता), उत्तर प्रदेश सरकार तकनीकी सत्र-1 में बोलते हुए।

श्री बी.एल. मीना, आई.ए.एस प्रमुख सचिव (सहकारिता), उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए समान उप-नियमों और वित्तीय स्थिरता के लिए गतिविधियों में विविधता लाने की उनकी क्षमता के महत्व को व्यक्त किया। उन्होंने सहकारी समितियों को अपनी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

श्री मोहम्मद अकबर वानी, आईएएस, सहकारी समिति रजिस्ट्रार, जम्मू और कश्मीर, सरकार तकनीकी सत्र-1 में बोलते हुए।

श्री वानी ने इस क्षेत्र में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने सहकारी कानून और नीतिगत सुधारों का आह्वान किया जो सरकारी समर्थन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सहकारी समितियों के सामने आने वाली कठिनाइयों और भ्रम को कम करने के लिए जम्मू-कश्मीर में एकल एवं सहायक सहकारी कानून की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री आलोक अग्रवाल, संयुक्त सचिव (सहकारिता), भारत सरकार तकनीकी सत्र-1 में बोलते हुए।

श्री आलोक अग्रवाल, संयुक्त सचिव (सहकारिता), भारत सरकार ने सहकारी समितियों के प्रति दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रस्तावित नई सहकारी नीति, बहु-राज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम में संशोधन और पैक्स को बहु-सेवा केंद्रों में परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने नीतिगत सुधारों और सहकारी कानून के माध्यम से एक अनुकूल माहौल बनाने के महत्व पर जोर दिया और एक नई सहकारी नीति की वकालत की जो सहकारी समितियों में नई ऊर्जा का संचार करेगी।

श्री प्रकाश पी. नाइकनवरे, प्रबंध निदेशक, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड तकनीकी सत्र-1 में बोलते हुए।

श्री प्रकाश पी. नाइकनवरे ने चीनी सहकारी समितियों और भारत में समग्र सहकारी परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिलाया। उन्होंने सहकारी समितियों में व्यवहार परिवर्तन, व्यावसायिकता और निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होने सहकारी समितियों के विकास और जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, लागत में कमी, नूतन विपणन रणनीतियों और ब्रांडिंग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

अंत में श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए सभी सम्मानित वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से भारत में सहकारी आंदोलन को सामूहिक रूप से मजबूत करने के लिए सत्र के दौरान साझा किए गए विचारों और सिफारिशों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। प्रगतिशील कानून और नीतिगत सुधारों द्वारा संचालित सहकारी समितियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने की साझा प्रतिबद्धता के साथ सत्र संपन्न हुआ।

Shri B. L. Meena, IAS, Principal Secretary (Cooperation), Government of Uttar Pradesh speaking in the Technical Session of Conducive Cooperative Legislation and Policy Reforms

Shri B. L. Meena, IAS, Principal Secretary (Cooperation), Government of Uttar Pradesh, expressed the importance of uniform bye-laws for Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and their potential to diversify activities for financial sustainability. He emphasized the need for cooperative societies to embrace modern technology and innovation to enhance their reach and effectiveness.

Shri Alok Agarwal, Joint Secretary (Coop), Government of India speaking in the Technical Session

Shri Alok Agarwal, Joint Secretary (Coop), Government of India stressed the need for a paradigm shift in the vision towards cooperatives. He highlighted the significance of the proposed new Cooperative Policy, amendments to the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, and the transformation of PACS into MultiService Centers. He emphasized the importance of creating a conducive atmosphere through policy reforms and cooperative legislation, advocating for a New Cooperative Policy that would infuse new energy into cooperatives.

Shri Mohammad Akbar Wani, IAS, Registrar of Cooperative Societies, Government of Jammu and Kashmir speaking in the technical session.

Shri Mohammad Akbar Wani, IAS, Registrar of Cooperative Societies, Government of Jammu and Kashmir, shared his views on the challenges faced by cooperatives in the region. He called for cooperative legislation and policy reforms that would ensure government support and financial stability. He stressed the need for a single, supportive cooperative law in Jammu and Kashmir to alleviate difficulties and confusion faced by cooperatives.

Shri Prakash P Naiknavare, Managing Director of the National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd. speaking in the technical session

Shri Prakash P Naiknavare, Managing Director of the National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., brought attention to vital points concerning sugar cooperatives and the overall cooperative landscape in India. He emphasized the importance of behavioural changes, professionalism, and continuous education and training in cooperatives. Shri Naiknavare also highlighted the need for diversification, cost reduction, evolving marketing strategies, and branding to ensure the growth and vibrancy of cooperatives.

In conclusion, Smt. Savitri Singh, Deputy Chief Executive expressed her gratitude to the esteemed speakers for their valuable contributions to the session. She urged all participants to carry forward the ideas and recommendations shared during the session to collectively strengthen the cooperative movement in India. The session concluded with a shared commitment to forging ahead towards a brighter future for cooperatives, driven by progressive legislation and policy reforms.

तकनीकी सत्र - 1: मुख्य संस्तुतियाँ

1. **केंद्र एवं राज्य सरकार में समन्वयः** में सहकारी कानून और नीतियों के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ समन्वय और परामर्श के महत्व पर जोर दिया गया। कानूनों और नीतियों के सामंजस्य को सुनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार एक व्यापक रूपरेखा प्रदान कर सकती है लेकिन राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इसे अनुकूलित करने के लिए लचीलेपन की अनुमति देना आवश्यक है।

2. **हितधारको के साथ जुडावः** सत्र में सहकारी संघों, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सहकारी समितियों के साथ जुडना एक महत्वपूर्ण सिफारिश के रूप में उभरा। यह दृष्टिकोण जमीनी हकीकतों की जानकारी हासिल करने, चुनौतियों की पहचान करने और सहकारी समितियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने वाले व्यापक कानून और नीति सुधार बनाने में मदद करेगा।

3. **व्यापक समीक्षा और अद्यतनः** राज्य स्तर पर मौजूदा सहकारी कानून, अधिनियमों और नियमों की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। पुराने प्रावधानों, कमियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने से सहकारी समितियों के लिए अधिक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार होगा।

4. **सहकारी अनुकूल कानून की आवश्यकताः** सत्र में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सहकारी - अनुकूल कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। समानांतर कानून के मुद्दे को संबोधित करते हुए, जहां कुछ राज्यों में परंपरागत सहकारी अधिनियम और आत्मनिर्भर / पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम एक साथ मौजूद हैं, सहकारी समितियों के कामकाज को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

5. **नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही लालफीताशाही को कम करने के लिए सहकारी समितियों के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल पोर्टल विकसित करने की सिफारिश की गई थी जिसमे पंजीकरण, सदस्यता, चुनाव, ऑडिटिंग और मध्यस्थता सहित नियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण एक प्राथमिकता के रूप में उभरा।

6. **पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढावा देनाः** सत्र में सहकारी समितियों और नियामकों के बीच दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सहकारी समितियों के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने से सदस्यों को सेवा वितरण में वृद्धि होगी और यह सुनिश्चित होगा कि उनके हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व हो।

7. **व्यावसायिकता और कौशल विकासः** सहकारी समितियों में व्यावसायिकता अपनाने और सहकारी नेताओं के कौशल विकास की सिफारिश की गई। लागत में कमी की रणनीति और विकसित होती विपणन रणनीतियों के अनुरूप व्यवसाय विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

8. **युवाओं और महिलाओं का समावेशः** युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इस क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना गया। युवाओं और महिलाओं को सहकारी दायरे में आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए सहकारी अधिनियमों और नीतियों में प्रावधान तैयार करने का सुझाव दिया गया।

9. **निगरानी और मूल्यांकनः** सत्र में सहकारी कानून और नीति सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। सहकारी क्षेत्र पर सुधारों के प्रभाव के नियमित आकलन से आवश्यक समायोजन और सुधार संभव हो सकेंगे।

तकनीकी सत्र -2: सहकारी आंदोलन को मजबूत करने हेतु क्रॉस सेक्टोरल सहयोग

अध्यक्षः डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत एवं कृभको

मुख्य वक्ताः डॉ. रेग्मी दामोदर, सचिव, भूमि प्रबंधन, सहकारिता एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सिंहदरबार, नेपाल सरकार, नेपाल

वक्ता:

1. प्रो. (डॉ.) मुकेश कानस्कर, उप महानिदेशक, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, मुंबई (एआईआईएलएसजी) और निदेशक, एआईआईएलएसजी, सीएसआर केंद्र
2. श्री प्रसन्ना प्रभु, अध्यक्ष भारतीय व्यक्ति विकास केंद्र (आर्ट ऑफ लिविंग)
3. डॉ. माणिक बत्रा, निदेशक, बत्रा ग्रुप एवं अध्यक्ष एसोचैम जम्मू-कश्मीर काउंसिल
4. श्री विद्याधर वी. अनास्कर, प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई

Technical Session – 1: Key Recommendations

1. Central and State Government Coordination: The session emphasized the importance of close coordination and consultation between the central and state governments in the formulation of cooperative legislation and policies. While the central government can provide a broad framework, it is essential to allow flexibility for states to adapt it to their specific needs, ensuring harmonization of laws and policies.
2. Stakeholder Engagement: Engaging with cooperative federations, industry experts, academics, and cooperative societies emerged as a critical recommendation. This approach will help gain insights into ground realities, identify challenges, and create comprehensive legislation and policy reforms that address the needs and aspirations of cooperatives.
3. Comprehensive Review and Update: The need for a comprehensive review of existing cooperative legislation, acts, and rules at the state level was emphasized. Identifying outdated provisions, gaps, and areas requiring improvement will lead to a more robust legal framework for cooperatives.
4. Advocate for Cooperative-friendly Legislation: The session urged for advocacy efforts to promote cooperative-friendly legislation both at the national and state levels. Addressing the issue of parallel legislation, where Traditional Cooperative Acts and Self-Reliant/Mutually Aided Cooperative Societies Acts coexist in some states, was highlighted as crucial for simplifying the working of cooperatives.
5. Simplify Regulatory Processes: The simplification of regulatory processes, including registration, membership, election, auditing, and arbitration, emerged as a priority. Developing a user-friendly digital portal for cooperatives was recommended to streamline processes and reduce bureaucratic red tape.
6. Promote Transparency, Accountability, and Good Governance: The session stressed the need for a shift in vision and attitude among cooperators and regulators. Promoting transparency, accountability, and good governance practices within cooperative societies will enhance services delivery to members and ensure their interests are effectively represented.
7. Professionalism and Skill Development: The adoption of professionalism in cooperatives and skill development of cooperative leaders were recommended. Tactics for cost reduction and the need for business diversification, in alignment with evolving marketing strategies, were emphasized.
8. Youth and Women Inclusion: Encouraging youth and women to actively participate in cooperatives was identified as crucial for the sector's future. The formulation of provisions in Cooperative Acts and Policies to attract and retain the youth and women under the cooperative fold was suggested.
9. Monitoring and Evaluation: The session proposed establishing mechanisms for monitoring and evaluating the implementation of cooperative legislation and policy reforms. Regular assessments of the reforms' impact on the cooperative sector will enable necessary adjustments and improvements.

Technical Session 2: Cross-sectoral Collaboration for Strengthening Cooperative Movement

Chair : Dr. Chandrapal Singh Yadav President, International Cooperative Alliance – Asia Pacific and Chairman, KRIBHCO

Keynote speaker : Dr. Regmi Damodar, Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation, Singhdurbar, Government of Nepal

Speakers:

1. Prof. (Dr.) Mukesh Kanaskar, Deputy Director General, All India Institute of Local SelfGovernment, Mumbai (AIILSG) & DireXXXXana Prabhu, Chairman Vyakti Vikas Kendra India (Art of Living)
3. Dr. Manik Batra DirXector, Batra Group & Chairman ASSOCHAM J&K Council
4. Shri Vidyadhar V. Anaskar, Administrator Maharashtra State Cooperative Bank Ltd. Mumbai

तकनीकी सत्र -2 की झलकः सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अंतर क्षेत्रीय सहयोग।

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का तकनीकी सत्र- 2 "सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग" विषय पर केंद्रित रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया और प्रशांत के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव के कुशल मार्गदर्शन में सत्र में विशिष्ट वक्ताओं की एक श्रृंखला देखी गई जिन्होंने भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए सहकार एवं सहयोग के महत्व पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।

डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव, सत्र के अध्यक्ष ने अपने सम्बोधन में तकनीकी सत्र में होने वाली चर्चा की अपेक्षाएँ निर्धारित कीं। उन्होंने सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने के महत्व और सहकारी क्षेत्र की दक्षता में सुधार के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी समितियों के लिए एक मजबूत बाजार की कमी पर प्रकाश डाला और सहकारी सदस्यों के बीच शेयरों के उचित विभाजन पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होने सतत विकास और प्रगति के लिए सहकारी समितियों में कुशल सदस्यों के महत्व पर जोर दिया।

श्री सुमित सिंह, सलाहकार, भा०रा०सह० संघ-तकनीकी-2 सत्र के मॉडरेटर।

श्री सुमित सिंह, सलाहकार, भा०रा० सह०संघ ने सम्मेलन के दूसरे सत्र की शुरुआत की। उन्होने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया और अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और पैनल वक्ताओं का विस्तार से परिचय दिया। उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग पर चर्चा करने के सत्र के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और इसके महत्व पर जोर दिया।

A glimpse of Technical Session 2: Cross-sectoral Collaboration for Strengthening Cooperative Movement

The Technical Session 2 of the 17th Indian Cooperative Congress revolved around the theme of "Crosssectoral Collaboration for Strengthening Cooperative Movement." Under the able guidance of Dr. Chandrapal Singh Yadav, President of the International Cooperative Alliance – Asia and Pacific, the session witnessed a remarkable lineup of speakers who shared their insights on the importance of collaboration to empower the cooperative movement in India.

Dr. Chandrapal Singh Yadav, as the session chair, set the expectations for the discussions. He emphasized the importance of strengthening cooperative networks and the need for technological support to improve the cooperative sector's efficiency. He highlighted the lack of a robust market for cooperatives and emphasized the fair division of shares among cooperative members. Additionally, Dr. Yadav stressed the significance of skilled members in cooperatives to drive sustainable growth and progress.

Shri Sumit Singh, Adviser, NCUI-Moderator of the Technical Session

The session began with **Shri Sumit Singh, Adviser, NCUI and Moderator of the Session** welcoming attendees and introducing the Chair, keynote speaker, and panel speakers. He highlighted the session's aim of discussing Cross-sectoral Collaboration for Strengthening the Cooperative Movement, emphasizing its significance.

डॉ. रेग्मी दामोदर, सचिव, भूमि प्रबंधन, सहकारिता एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सिंहदरबार, नेपाल सरकार क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग के सत्र-2 में बोलते हुए।

सत्र के मुख्य वक्ता **डॉ. रेग्मी दामोदर** ने अपने संबोधन की शुरुआत "सहकारिता" को परिभाषित करते हुए और उनके मूल मूल्यों और मान्यताओं पर प्रकाश डालते हुए की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहकारी सदस्य अपने संस्थापकों की परंपरा का पालन करते हुए ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल जैसे नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां आवश्यक सामाजिक पूंजी हैं जो सामाजिक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और शासन प्रणाली में नागरिक भागीदारी की नींव के रूप में कार्य करती हैं। वे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय को कायम रखने में सहायक हैं।

डॉ. दामोदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहकारी समितियां सामाजिक एकजुटता एवं अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया जिसमें वैश्विक सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करना शामिल है।

आगे उन्होने सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की पहल की रूपरेखा तैयार की। इन पहलों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनके अनुकूल ढलने, बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता और बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगारी की स्थिति में सहकारिता की भूमिका के बारे में बताया।

डॉ. दामोदर ने मुख्य रूप से रणनीतिक योजना के चार प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला जिसमें सहकारी पहचान को बढ़ावा देना, सहकारी आंदोलन की वृद्धि, सहकारी समितियों के बीच सहयोग और वैश्विक सतत विकास में योगदान देना इत्यादि शामिल है।

प्रोफेसर. (डॉ.) मुकेश कानस्कर, उप-महानिदेशक, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, मुंबई (एआईआईएलएसजी) और निदेशक, एआईआईएलएसजी, सीएसआर केंद्र तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

प्रोफेसर कानस्कर ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि सहकारिता का लाभ सभी क्षेत्रों को हो जिसमें हाशिए पर रहने वाली आबादी जैसे कि गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियाँ, विकलांग आबादी और सिद्दी जनजातियाँ इत्यादि शामिल हैं। इसके लिए उन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के माध्यम से क्षैतिज क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। नए प्रयोगों और नए मॉडलों को बढ़ावा देने में सीएसआर की भूमिका पर जोर देते हुए, उन्होंने निवेश पर सामाजिक रिटर्न (एसआरओआई) के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त बच्चों और युवाओं में जीवन कौशल विकास पर केंद्रित क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग पर चर्चा की गई जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सहकारी समितियों को सचेत रूप से सामुदायिक डीएनए में निहित जीवन कौशल के रूप में बनाया जाना चाहिए। प्रोफेसर कानस्कर ने हाशिये पर मौजूद आबादी को सशक्त बनाने, आत्म-सशक्तीकरण, उन्नत शिक्षा, रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य को सक्षम करने के साथ-साथ अच्छी नागरिकता को बढ़ावा देने और तालमेल बनाने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण के रूप में "लाइफ स्किल्स एजुकेशन विद फन" (लाइफ एसईएफ) की शुरुआत की।

Dr. Regmi Damodar, Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation, Singhdurbar, Government of Nepal speaking in the session of Cross-sectoral Collaboration for Strengthening Cooperative Movement

Dr. Regmi Damodar, the keynote speaker, commenced his address by defining "cooperatives" and highlighting their core values and beliefs. He emphasized that cooperative members embrace ethical values such as honesty, openness, social responsibility, and caring for others, following the tradition of their founders. Cooperatives, he stated, are essential social capital that fosters social energy and serves as a foundation for civic engagement in the governance system. They are instrumental in socio-economic transformation, promoting social and economic democracy, and upholding social justice.

In his address, Dr. Damodar emphasized that cooperatives are an integral part of the social solidarity economy. He elaborated on the purpose of the International Cooperative Alliance, which includes promoting the global cooperative movement and protecting cooperative values and principles.

The keynote speaker shed light on the challenges faced by cooperatives and outlined initiatives to address them effectively. These initiatives encompassed the urgent need to mitigate and adapt to the effects of climate change, address growing social and economic disparities, foster digital transformation, and promote youth engagement in the cooperative movement, especially in the face of massive youth unemployment.

Furthermore, Dr. Damodar highlighted the four key themes of the strategic plan, which include the promotion of the cooperative identity, the growth of the cooperative movement, cooperation among cooperatives, and contributing to global sustainable development.

Prof. (Dr.) Mukesh Kanaskar, Deputy Director General, All India Institute of Local Self-Government, Mumbai (AIILSG) & Director, AIILSG's CSR Centre speaking in the technical session

Prof. Kanaskar addressed the need to ensure that all sectors benefit from cooperation, including marginalized populations such as De-notified & Nomadic Tribes, Differently Abled population, and Siddi Tribes. To overcome this issue, he highlighted the importance of horizontal cross-sectoral collaboration through Corporate Social Responsibility (CSR). Emphasizing the role of CSR in fostering innovations and newer models, he stressed on the significance of Social Return on Investments (SROIs). Additionally, vertical cross-sectoral collaboration focused on life skills development in children and youth was discussed, emphasizing that cooperatives should consciously be built as a life skill ingrained in the community DNA. Prof. Kanaskar introduced "Life Skills Education with Fun" (Life SEF) as an innovative approach to empower marginalized populations, enabling self-empowerment, enhanced learning, employability, and mental health, while fostering good citizenship and building synergies.

श्री प्रसन्ना प्रभु, अध्यक्ष, व्यक्ति विकास केंद्र (आर्ट ऑफ लिविंग) तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

श्री प्रसन्ना प्रभु ने बाहरी कारकों पर किसानों की निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवा नेतृत्व कार्यक्रम और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षित प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण के महत्व पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीण समुदायों के उत्थान और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए महिला सशक्तिकरण और कौशल केंद्रों के महत्व पर जोर दिया।

श्री विद्याधर वी. अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

श्री विद्याधर अनास्कर ने अंतर-क्षेत्रीय सहयोग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने सहकारी संचालन को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन सुविधाओं और साइबर सुरक्षा विकास केंद्रों की क्षमता पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में जनशक्ति, विशेषज्ञता, प्रभावी प्रशासन और नकदी रहित लेनदेन के लाभों पर जोर दिया।

डॉ. माणिक बत्रा, निदेशक, एसोचैम एवं बत्रा ग्रुप, जे एंड के काउंसिल तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

डॉ. माणिक बत्रा ने सहकारी आंदोलन के महत्व और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों जैसे सीमित जागरूकता, बाजार दबाव और नियामक मुद्दों सहित अन्य विषयों पर ज़ोर देकर चर्चा प्रारम्भ की। इसके बाद उन्होंने आम लक्ष्यों और साझा मूल्यों की दिशा में काम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाने, क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग के महत्व पर जोर दिया। डॉ. बत्रा ने आवास सहकारी श्रमिक सहकारी समितियों और किसानों की सहकारी समितियों में सफल अंतर- क्षेत्रीय सहयोग के उदाहरणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सहकारी आंदोलन में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होने युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और संसाधन उपलब्ध कराने से प्रासंगिकता और सामाजिक प्रभाव पर बल दिया।

Shri Prasana Prabhu, Chairman, Vyakti Vikas Kendra India (Art of Living) speaking in the technical Session

Shri Prasanna Prabhu highlighted the need to reduce the dependence of farmers on external factors. He discussed the youth leadership program and the importance of trained natural farming training to empower farmers. Additionally, he stressed the significance of afforestation, women empowerment, and skilling centers to uplift rural communities and strengthen the cooperative movement.

Dr. Manik Batra Director, Batra Group & Chairman ASSOCHAM J&K Council speaking in the technical session

Dr. Manik Batra began by underscoring the importance of the cooperative movement and the challenges it faces, including limited awareness, market pressures, and regulatory issues. He then emphasized the significance of cross-sectoral collaboration, bringing together stakeholders from various sectors to work towards common goals and shared values. Dr. Batra highlighted examples of successful cross-sectoral collaborations in cooperative housing, worker cooperatives, and farmers' cooperatives. He stressed the role of youth in the cooperative movement, as they bring new perspectives and diverse skill sets. Encouraging youth leadership and providing networking platforms and resources can lead to increased relevance and social impact.

Shri Vidyadhar V. Anaskar, Administrator Maharashtra State Cooperative Bank Ltd. Mumbai speaking in the technical session

Shri Vidhyadhar Anaskar discussed the importance of cross-sectoral collaboration and public-private partnerships. He highlighted the potential of blockchain facilities and cybersecurity development centers to enhance cooperative operations. Additionally, he emphasized the benefits of manpower, expertise, effective governance, and cashless transactions in driving the cooperative movement forward.

तकनीकी सत्र -2: मुख्य सिफ़ारिशें:

1. **सहयोगात्मक मंच स्थापित करनाः** सत्र में ऐसे मंच बनाने की सिफारिश की गई जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि ज्ञान का आदान-प्रदान करने, अनुभव साझा करने और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक साथ आ सकें। ये सहयोगी मंच कार्य समूहों, कार्य बलों या सहकारी नेटवर्क का रूप ले सकते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों और सीखने को बढ़ावा देते हैं।
2. **नीति संवाद को प्रोत्साहित करनाः** विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को शामिल करते हुए नीतिगत संवाद को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया। नीतिगत संवादों में शामिल होने से सहकारिता से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर रचनात्मक चर्चा हो सकेगी। यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सहकारी दृष्टिकोण व्यापक नीति ढांचे में एकीकृत हैं।
3. **विकासात्मक चुनौतियों के लिए साझेदारी को बढावा देनाः** सत्र में माना गया कि सहकारी समितियाँ भारत के सामने आने वाली प्रमुख विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहयोग करके, सहकारी समितियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और युवा बेरोजगारी से निपटने में योगदान दे सकती हैं।
4. **सीमांत आबादी के लिए समावेशिताः** सहकारी दायरे में हाशिए पर रहने वाली आबादी को शामिल करने के लिए चंहुमुखी रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों, विशेष रूप से विकलांग आबादी और सिद्दी जनजातियों को सशक्त बनाने और उत्थान के लिए विशिष्ट भागीदारी और सहयोग की आवश्यकता है। इन समुदायों के बच्चों और युवाओं में जीवन कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी पहल को एक सचेत दृष्टिकोण के साथ डिजाइन करने की आवश्यकता है।
5. **क्षैतिज सहयोग के लिए सीएसआर का लाभ उठानाः** सत्र में क्षैतिज क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर जोर दिया गया। सहकारी समितियों को उपेक्षित आवश्यक सेवाओं को उजागर करने के लिए सीएसआर पहल के साथ सहयोग करना चाहिए और निवेश पर सामाजिक रिटर्न (एसआरओआई) पर ध्यान देने के साथ नए मॉडल बनाने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देना चाहिए।
6. **वर्टिकल सहयोग के लिए सचेत दृष्टिकोणः** बच्चों और युवाओं में जीवन कौशल विकास पर केंद्रित वर्टिकल क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा। सहकारी समितियों को खुद को सामुदायिक डीएनए में शामिल एक जीवन कौशल के रूप में विकसित करना चाहिए जिसमें बाल पंचायत (बच्चों के संगठन), युवा समूह और शीर्ष निकाय शामिल हों। युवाओं को आत्म-सशक्तीकरण, उन्नत शिक्षा, रोजगार क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य के साथ सशक्त बनाने के लिए "लाइफ स्किल्स एजुकेशन विद फन" (लाइफ एसईएफ) जैसे नवाचारों की सिफारिश की गई थी।
7. **ज्ञान-साझाकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदानः** तकनीकी सत्र ने अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठनों को दुनिया भर में सहकारी समितियों के बीच ज्ञान के साझाकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया। कनाडा में आवास सहकारी समितियों, स्पेन और बेल्जियम में कार्यकर्ता सहकारी समितियों और केन्या और ब्राजील में किसानों की सहकारी समितियों के बीच सफल साझेदारी को प्रेरक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया।
8. **दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठानाः** तकनीकी सत्र ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता पर प्रकाश डाला। प्रौद्योगिकी का एकीकरण सहकारी समितियों को अधिक कुशल और सुलभ बना सकता है, साथ ही विविध कौशल वाले युवाओं को आकर्षित करके उन्हें सहकारी आंदोलन में भविष्य का नेता बना सकता है।
9. **संसाधनों और बाजारों तक पहुंच को सुगम बनानाः** सहयोग को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजारों सहित संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। सार्वजनिक और निजी संगठन इन क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
10. **प्रौद्योगिकी समावेशन पर जोरः** तकनीकी सत्र, सहकारी समितियों के तंत्र और कामकाज में बेहतर दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता को दोहराता है। प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और सहकारी समितियों को अधिक चुस्त और उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

तकनीकी सत्र -3: सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य का सुदृढ़ीकरण

अध्यक्षः डॉ. के.के. त्रिपाठी, आई.ई.एस. , ओएसडी, माननीय सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
मुख्य वक्ताः प्रो. यशवन्त पी. डोंगरे, कुलपति चाणक्य विश्वविद्यालय, बेंगलुरु

वक्ताः

1. श्री उमाकांत दास, निदेशक, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (ईरमा), आनंद
2. डॉ. निरुपम मेहरोत्रा, निदेशक, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी) लखनऊ
3. डॉ. हेमा यादव, निदेशक, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम), पुणे
4. सुश्री शरीना अब्दुल्ला, वरिष्ठ निदेशक (नीति और रणनीति प्रभाग) मलेशिया सहकारी संस्थान (सीआईएम)

Technical Session 2 - Key recommendations:

1. Establishing Collaborative Platforms: The session recommended creating platforms or forums where representatives from different sectors can come together to exchange knowledge, share experiences, and identify areas of collaboration. These collaborative platforms can take the form of working groups, task forces, or cooperative networks, fostering joint efforts and learning across diverse sectors.
2. Encouraging Policy Dialogue: Facilitating policy dialogues involving stakeholders from different sectors was emphasized. Engaging in policy dialogues will enable constructive discussions on cooperative-related issues, challenges, and opportunities. This inclusive approach ensures that cooperative perspectives are integrated into broader policy frameworks.
3. Fostering Partnerships for Developmental Challenges: The session recognized that cooperatives can play a vital role in addressing key developmental challenges faced by India. By collaborating with various sectors, cooperatives can contribute to mitigating the effects of climate change, addressing social and economic disparities, promoting gender equality, and tackling youth unemployment.
4. Inclusivity for Marginalized Populations: The need to traverse horizontally, vertically, and tangentially to include marginalized populations within the cooperative ambit was highlighted. Specific partnerships and collaborations are required to empower and uplift De-notified & Nomadic Tribes, Specially Abled population, and Siddi Tribes. Cooperative initiatives need to be designed with a conscious approach to promote life skills development in children and youth from these communities.
5. Leveraging CSR for Horizontal Collaboration: The session emphasized Corporate Social Responsibility (CSR) as a key tool for promoting horizontal cross-sectoral collaboration. Cooperatives should collaborate with CSR initiatives to highlight essential services that may have been neglected and foster innovations to create newer models with a focus on Social Return on Investments (SROIs).
6. Conscious Approach for Vertical Collaboration: Vertical cross-sectoral collaboration focused on life skills development in children and youth emerged as crucial. Cooperatives should consciously build themselves as a Life Skill ingrained in community DNA, involving Bal Panchayats (children's organizations), youth groups, and apex bodies. Innovations like "Life Skills Education with Fun" (Life SEF) were recommended to empower youth with self-empowerment, enhanced learning, employability, and mental health.
7. Knowledge-Sharing and Best Practices Exchange: The session encouraged international cooperative organizations to facilitate knowledge-sharing and exchange of best practices among cooperatives worldwide. Successful partnerships between housing cooperatives in Canada, worker cooperatives in Spain and Belgium, and farmers' cooperatives in Kenya and Brazil were cited as inspiring examples.
8. Leveraging Technology for Efficiency: The session highlighted the potential of technology to enhance cooperation and coordination among sectors. Integrating technology can make cooperatives more efficient and accessible, while also attracting youth with diverse skill sets, making them future leaders in the cooperative movement.
9. Facilitating Access to Resources and Markets: Foster collaborations that enable cooperatives to access resources, including finance, technology, and markets. Public and private organizations can provide support and guidance to cooperatives in these areas, ensuring their growth and sustainability.
10. Emphasizing Technology Inclusion: The session reiterates the need to leverage technology for improved efficiency in the mechanism and functioning of cooperatives. Integrating technology can streamline processes, enhance transparency, and make cooperatives more agile and responsive.

Technical Session 3: Strengthening Cooperative Education, Training, and Research

Chair : Dr. K. K. Tripathy, IES, OSD to Hon'ble Minister of Cooperation, Ministry of Cooperation, GoI
Keynote speaker: Prof. Yashavantha P. Dongre, Vice Chancellor Chanakaya University, Bengaluru

Speakers:

1. Shri Umakant Dash, Director, Institute of Rural Management (IRMA), Anand
2. Dr. Nirupam Mehrotra, Director, Bankers Institute of Rural Development (BIRD) Lucknow
3. Dr. Hema Yadav, Director Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management (VAMNICOM), Pune
4. Ms. Sharina Abdullah, Senior Director (Policy and Strategy Division) Cooperative Institute of Malaysia (CIM)

तकनीकी सत्र-3 की एक झलक।

तकनीकी सत्र - 3 " सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करना " के महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित था।

डॉ. सागर के. वाडकर, सलाहकार ,एनसीयूआई ने सत्र का कुशलतापूर्वक संचालन किया। उन्होने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और सत्र के अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और पैनल वक्ताओं का परिचय दिया। उन्होंने सत्र के उद्देश्यों को रेखांकित किया और सहकारी आंदोलन की वृद्धि और विकास में सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

डॉ. के. के. त्रिपाठी, आई.ई.एस. ओ.एस.डी., माननीय सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, तकनीकी सत्र-3 में बोलते हुए।

सत्र के **अध्यक्ष ने सहकारी शिक्षा** के सभी स्तरों पर और विशेष रूप से युवाओं के समावेशन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भावी पीढ़ियों में सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम में सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों को एकीकृत करने पर जोर दिया।

सत्र की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री ओएसडी डॉ. के. के. त्रिपाठी ने की। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में **डॉ. त्रिपाठी ने सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान** की पहचान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी सदस्यों और पेशेवरों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) की आवश्यकता पर बल दिया। प्रशिक्षण में एकरूपता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास का प्रस्ताव रखा, जिसे विभिन्न सहकारी संस्थानों में अनुकूलित किया जा सकता है।

इसके अलावा डॉ. त्रिपाठी ने उन क्षेत्रों की पहचान करने में केंद्रित अनुसंधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जहां वास्तव में सहकारी अनुसंधान की आवश्यकता है। उन्होंने शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने प्रयासों को सहकारी क्षेत्र की व्यावहारिक जरूरतों के साथ जोड़ने का आग्रह किया।

तत्पश्चात डॉ. त्रिपाठी ने सहकारी शिक्षा और अनुसंधान में स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के सहयोग से प्रौद्योगिकी और ज्ञान के हस्तांतरण में आसानी हो सकती है जिससे सहकारी क्षेत्र में अधिक प्रगति होगी।

डॉ. त्रिपाठी ने सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों पर की गई सभी पहलों की निगरानी और मूल्यांकन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी कार्यक्रमों और पहलों के प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए डिजिटल डेटा संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करने का सुझाव दिया।

A glimpse of Technical Session 3: Strengthening Cooperative Education, Training, and Research

The Technical Session 3 focused on the crucial theme of "Strengthening Cooperative Education, Training, and Research." **Dr. Sagar Kisan Wadkar,** Adviser at NCUI, expertly moderated the session, welcoming participants and introducing the Chair, keynote speaker, and panel speakers. He outlined the session's objectives and emphasized the vital role of Cooperative Education, Training, and Research in the cooperative movement's growth and development. The session was chaired by **Dr. K. K. Tripathy (IES), Officer on Special Duty to the Minister of Cooperation** and delivered an enlightening address, setting the tone and expectations for the discussions.

In his opening remarks, Dr. Tripathy emphasized the significance of identifying the gaps in cooperative education, training, and research. He stressed the need for a comprehensive Training Needs Analysis (TNA) to understand the specific requirements of cooperative members and professionals across various sectors.

To promote uniformity and effectiveness in training, he proposed the development of standardized training modules that can be adapted across different cooperative institutions.

The chairman emphasized the importance of inclusivity, particularly concerning the youth, at all levels of cooperative education. He advocated for integrating cooperative principles and values into the curriculum at schools and higher education institutions to instill a sense of cooperation and social responsibility in future generations.

Furthermore, Dr. Tripathy highlighted the need for focused research in identifying areas where cooperative research is genuinely required. He urged researchers and academicians to align their efforts with the practical needs of the cooperative sector to address real-world challenges effectively.

Regarding collaboration, the chairman stressed the significance of forging partnerships with premier institutes like IITs and IIMs to define clear roles and responsibilities in cooperative education and research. He emphasized that such collaborations could facilitate the transfer of technology and knowledge, leading to greater advancements in the cooperative sector.

Dr. Tripathy emphasized the importance of monitoring and evaluating all initiatives taken at different levels of cooperative education and training. He suggested using digital data-driven approaches to assess the impact and effectiveness of cooperative programs and initiatives.

Dr. K. K. Tripathy, IES, OSD to Hon'ble Minister of Cooperation, Ministry of Cooperation, GoI speaking in the technical session of Strengthening Cooperative Education, Training, and Research

प्रो. यशवन्त पी. डोंगरे, कुलपति, चाणक्य विश्वविद्यालय, बेंगलुरु तकनीकी सत्र-3 में बोलते हुए।

प्रो. यशवन्त पी. डोंगरे द्वारा दिए गए मुख्य भाषण में सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के महत्व को सहकारी क्षेत्र की सतत वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

प्रो. डोंगरे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकांश सदस्य और कर्मचारी एक सचेत संस्थागत विकल्प के बजाय अपनी जरूरतों को पूरा करने या आजीविका कमाने के लिए सहकारी समितियों में शामिल होते हैं। इसलिए, प्रभावी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इन सदस्यों और कर्मचारियों को सहकारी समितियों में परिवर्तित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

मुख्य वक्ता ने सहकारी समितियों के 5वें सिद्धांत, "शिक्षा" पर चर्चा की जिसमें सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों को समझना और उन्हें दिन-प्रतिदिन के कार्यों में लागू करना शामिल है। सहकारी शिक्षा सदस्यों, नेताओं, प्रबंधकों और कर्मचारियों को सहकारी विचार और कार्रवाई की जटिलता और समृद्धि को समझने में सहकारिता प्रदान करती है जिससे एक सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा होता है। दूसरी ओर, "प्रशिक्षण", लोकतांत्रिक नियंत्रण, जिम्मेदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सहकारी व्यवसायों को कुशलतापूर्वक और नैतिक रूप से चलाने के लिए व्यावहारिक कौशल विकसित करने पर केंद्रित है।

सदस्य शिक्षा के संबंध में, प्रो. डोंगरे ने नीचे से ऊपर की ओर के दृष्टिकोण की वकालत की जहां सदस्यों को उनके स्वयं के सहकारी स्तर पर या स्थानीय स्तर पर शिक्षित किया जाता है। आम जनता विशेषकर युवाओं को जागरूक करने के लिए, सहकारी सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को आवश्यक बताया गया।

मुख्य वक्ता ने युवाओं को सहकारिता विषय में शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया और उच्च शिक्षा संस्थानों पर इस दिशा में ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र सदस्यता के साथ सहकारी समितियों की शुरुआत करना, उद्योग-आधारित दृष्टिकोण के साथ सहकारी समितियों से संबंधित पेशेवर कार्यक्रमों की पेशकश करना और सहकारी क्षेत्र में कैरियर बनाना जैसी रणनीतियों की सिफारिश की गई।

प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों को पेशेवर रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया गया। इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री को स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाना चाहिए, और संयुक्त प्रशिक्षण केंद्रों (जेटीसी) जैसे स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रो. डोंगरे ने निर्वाचित नेताओं के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण तंत्र का प्रस्ताव रखा।

प्रोफेसर डोंगरे ने अनुसंधान पहलू के विषय को संबोधित करते हुए भारतीय संदर्भ में सहकारिता से संबंधित अनुसंधान की कमी के बारे में चिंता जताई। उन्होंने सहकारिता के समक्ष नित-प्रतिदिन आने वाली चुनौतियों व अनुसंधान आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की शर्त पर बल दिया। शिक्षा और अनुसंधान दोनों को सुविधाजनक बनाने के लिए फेलोशिप के माध्यम से अनुसंधान का समर्थन करने और सहकारी अध्ययन के लिए समर्पित विश्वविद्यालय/केंद्र/संस्थान की स्थापना की खोज करने का सुझाव दिया गया। प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रख्यात वक्ताओं ने सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण के लिए नवीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हुए अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए।

Prof. Yashavantha P. Dongre, Vice Chancellor Chanakaya University, Bengaluru speaking in the technical session

In the keynote address delivered by Prof. Yashavantha P. Dongre, the importance of cooperative education, training, and research was highlighted as vital for the sustainable growth and development of the cooperative sector.

Prof. Dongre emphasized that most members and employees join cooperatives seeking to fulfill their needs or earn a livelihood, rather than as a conscious institutional choice. Hence, it becomes crucial to convert these members and staff into cooperators through effective education and training programs.

The speaker discussed the 5th Principle of cooperatives, "education," which involves understanding cooperative principles and values and applying them in day-to-day operations. Cooperative education engages members, leaders, managers, and employees to comprehend the complexity and richness of cooperative thought and action, thereby creating a positive social impact. "Training," on the other hand, focuses on developing practical skills to efficiently and ethically run cooperative businesses, ensuring democratic control, responsibility, and transparency.

Regarding member education, Prof. Dongre advocated for a bottom-up approach, where members are educated at the level of their own cooperative or at the local level. For the general public, particularly youth, awareness about cooperative success stories and achievements was highlighted as essential.

The keynote speaker stressed the significance of educating youth and suggested focusing on higher education institutions. Introducing cooperatives with student membership in colleges and universities, offering professional programs related to cooperatives with an industry-embedded approach, and creating career pathways in the cooperative sector were recommended strategies.

Regarding training, the emphasis was on making staff professionally competent. To achieve this, training materials should be developed in local/regional languages, and local training institutions like Joint Training Centres (JTCs) need strengthening. For elected leaders, Prof. Dongre proposed mandatory training mechanisms.

Addressing the research aspect, Prof. Dongre raised concerns about the lack of cooperative-related research in the Indian context. He stressed the need to identify research needs and secure funding for applied research focused on the sector's day-to-day challenges. Supporting research through fellowships and exploring the establishment of dedicated University/Centre/ Institute for cooperative studies were suggested to facilitate both education and research.

Eminent speakers from esteemed institutions shared their insights and experiences, shedding light on innovative approaches to nurture the cooperative ecosystem.

डॉ. उमाकांत दास, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आई.आर.एम.ए) तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

डॉ. उमाकांत दास, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आई.आर.एम.ए) ने आई.आर.एम.ए के पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए सत्र की शुरुआत की। उन्होने बताया कि आईआरएमए का पाठ्यक्रम ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के संपर्क को बढ़ावा देता है। उन्होने सहकारी समितियों के बारें में शीघ्र जानकारी देने के लिए गावों में प्रवास करने व दौरों के महत्व पर जोर दिया जिससे छात्रों को सहकारी कार्यप्रणाली में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सके। डॉ. दास ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास को बाजार की मांग के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सीखने को प्रोत्साहित करने और युवा दिमागों को उद्यमिता और स्टार्टअप के माध्यम से सहकारी समितियों में शामिल होने के लिए पदोन्नति में प्राथमिकताएं देकर सहकारी प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा। डॉ. दास ने युवाओं की आकांक्षाओं को समझने और सहकारी क्षेत्र को युवा प्रतिभाओं के लिए अधिक समावेशी और आकर्षक बनाने के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया।

डॉ. हेमा यादव, निदेशक, वैमनीकाम पुणे तकनीकी सत्र-3 में बोलते हुए।

डॉ. हेमा यादव ने डेटा संचालित अनुसंधान और एक सहकारी राष्ट्रीय डेटाबेस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसमें युवाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. यादव ने कॉर्पोरेट समकक्षों की तुलना में सहकारी नियुक्तियों की सीमित संख्या पर चिंता व्यक्त की और एक सहकारी संस्कृति विकसित करने का प्रस्ताव रखा जो इस क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों को इंटर्नशिप, फेलोशिप, लाइव प्रोजेक्ट और नौकरी प्लेसमेंट प्रदान करती है। डॉ. यादव ने सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप एक कुशल और प्रतिबद्ध कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मान्यता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ एकीकरण के माध्यम से सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने का सुझाव दिया।

डॉ. निरुपम मेहरोत्रा, निदेशक, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी) लखनऊ तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

डॉ. मेहरोत्रा ने सहकारी समितियों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के एकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने गहन अनुसंधान द्वारा समर्थित क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी शिक्षा की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए भौतिक और डिजिटल माध्यमों के संयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। क्षेत्रीय विविधताओं को स्वीकार करते हुए विविध प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण मैनुअल प्रस्तावित किए। डॉ. मेहरोत्रा ने वित्तीय समावेशी अध्ययन को बढ़ावा दिया और सफल वित्तीय साक्षरता पहल के प्रेरक उदाहरण साझा किए। सी-पीईसी की स्थापना के माध्यम से व्यावसायिकता बढ़ाने में बर्ड लखनऊ के प्रयासों का उल्लेख किया गया। उन्होंने निरंतर सुधार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने का सुझाव दिया।

Dr. Umakant Dash, the Director of the Institute of Rural Management Anand (IRMA) speaking in the technical session

Dr. Hema Yadav, Director, VAMNICOM, Pune speaking in the technical session

Dr. Umakant Dash, the Director of the Institute of Rural Management Anand (IRMA), commenced the session by highlighting IRMA's unique curriculum that fosters exposure to the rural ecosystem. He emphasized the significance of early exposure to cooperatives through visits and village stays, enabling students to gain practical insights into the cooperative functioning. Dr. Dash stressed the importance of aligning skill development with market demands to enhance employability. He proposed incentivizing cooperative training by offering preferences in promotions to incentivize learning and encourage young minds to engage in cooperatives through entrepreneurship and startups. Dr. Dash advocated for understanding the aspirations of the youth and formulating strategies to make the cooperative sector more inclusive and attractive to young talent.

Dr. Hema Yadav, emphasized data-driven research and the importance of a cooperative national database. She stressed the need to involve youth in the cooperative sector to ensure its future growth. Dr. Yadav expressed concern over the limited number of cooperative hiring compared to corporate counterparts and proposed developing a cooperative culture that offers internships, fellowships, live projects, and job placements to business management graduates to attract young talent into the sector. Dr. Yadav suggested strengthening cooperative education and training through National Accreditation and integration with the National Education Policy to ensure a skilled and committed workforce aligned with cooperative principles.

Dr. Mehrotra emphasized the integration of education, training, and research in cooperatives as complementary pillars. He stressed designing sector-specific training programs supported by thorough research. He highlighted the importance of combining physical and digital mediums to enhance accessibility and reach of cooperative education. Tailored training manuals for diverse Primary Agricultural Credit Societies (PACS) were proposed, acknowledging regional variations. Dr. Mehrotra promoted financial inclusive study and shared inspiring examples of successful financial literacy initiatives. BIRD Lucknow's efforts in enhancing professionalism were mentioned through the establishment of C-PEC. He suggested accrediting cooperative training institutions to foster continuous improvement and healthy competition.

Dr. Nirupam Mehrotra, Director, Bankers Institute of Rural Development (BIRD) Lucknow speaking in the technical session

सुश्री शरीना अब्दुल्ला, वरिष्ठ निदेशक (नीति और रणनीति प्रभाग), सहकारी संस्थान (सीआईएम), मलेशिया तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

सुश्री शरीना अब्दुल्ला ने मलेशिया में सहकारी आंदोलन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, मलेशिया में सहकारी आंदोलन के विकास पर चर्चा की और उद्यमिता एवं सहकारी विकास मंत्रालय (एमईसीडी) की पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने घटते टर्नओवर और शासन और व्यवसाय नियोजन विशेषज्ञता जैसे गैर-वित्तीय मुद्दों के संदर्भ में सूक्ष्म-स्तरीय सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया। अब्दुल्ला ने सहकारी शिक्षा, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सहयोग कार्यक्रमों की पेशकश में मलेशियाई सरकार की पहल को साझा किया। सुश्री अब्दुल्ला ने पहुंच बढ़ाने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, "आईकेएमए बिजनेस मॉडल" को सहकारी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यावहारिक प्रशिक्षण दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

सत्र के बाद अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और वक्ताओं की ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों के बाद एक प्रश्न-उत्तर का सत्र हुआ। इसमे प्रासंगिक प्रश्न उठाए गए। अध्यक्ष और संबंधित वक्ताओं द्वारा उन प्रश्नों का जवाब दिया गया।

तकनीकी सत्र -3: मुख्य सिफ़ारिशें:-

1. **सभी स्तरों पर सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना:**

(i) **मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल:** एनसीयूआई द्वारा शुरू किए गए प्रयासों के आधार पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना और उन्हें देश भर की स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना।

(ii) **सदस्य गतिविधि कक्ष:** नियमित सदस्य सहभागिता और सहकारी मामलों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सहकारी समिति में "सदस्य गतिविधि कक्ष" स्थापित करना।

(iii) **सहकारी साक्षरता केंद्र:** इसके तहत न केवल सदस्यों की शिक्षा के लिए बल्कि वित्तीय साक्षरता और स्वास्थ्य साक्षरता जैसे विषयों के लिए भी सहकारी साक्षरता केंद्र बनाएं जाएँ।

(iv) **कम-ज्ञात सहकारी समितियों की सफलता की कहानियाँ का उपयोग :** सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम-ज्ञात सहकारी समितियों की सफल कहानियाँ का उपयोग करना।

(v) **युवाओं और महिलाओं के लिए सहकारी शिक्षा:** उच्च स्तर पर "सहकारी शिक्षा" शुरू करना और सहकारी समितियों पर पाठ्य पुस्तकें विकसित करना।

2. **निर्वाचित निदेशक मंडल के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

(i) **कौशलता मैपिंग:** सहकारी नेताओं हेतु कौशलता मैपिंग के आधार पर प्रशिक्षण पैकेज विकसित करना।

(ii) **जमीनी स्तर के प्रशिक्षण संस्थान:** बड़ी संख्या में किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर अधिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

3. **सहकारी अध्ययन में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:**

(i) **राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान एजेंडा:** सहकारी उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों को सहकारी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए संयुक्त रूप से "राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान एजेंडा" तैयार करना चाहिए।

(ii) **अनुसंधान कोष की स्थापना:** राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुसंधान कोष की स्थापना करना।

(iii) **अनुसंधान के लिए फ़ेलोशिप:** एमएससी और पीएचडी करने वाले छात्रों को फ़ेलोशिप प्रदान करना।

(iv) इंटर्नशिप और सहकारी कार्य अनुभवों को बढ़ावा देगा छात्रों की इंटर्नशिप और सहकारी कार्य अनुभवों को प्रोत्साहित करना।

4. **मौजूदा संस्थानों के साथ सहयोग:** शैक्षणिक/तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी करना। सहकारी शिक्षा को उनके पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों सहित मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करना।

5. **राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय (एनसीयू):** सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय (एनसीयू) की स्थापना करना जो सहकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम, डिग्री कार्यक्रम और अनुसंधान के अवसर प्रदान करता हो।

6. **पाठ्यक्रम का विकास:** विभिन्न स्तरों पर सहकारी शिक्षा के लिए व्यापक और अद्यतन पाठ्यक्रम विकसित करना जिसमें सहकारी सिद्धांत, शासन, प्रबंधन, वित्त, विपणन और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को शामिल किया जाए।

7. **ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा:** सहकारी शिक्षा के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाना जिससे सीखने के कार्यक्रम में व्यापक पहुंच वाला और लचीला बनाया जा सके।

8. **अनुसंधान और नवाचार:** अंतःविषय अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना, अनुसंधान केंद्र स्थापित करना और विद्वानों को अपने निष्कर्षों और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त सहकारी स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक इन्क्यूबेशन एवं इनोवेशन लैब स्थापित करना।

Ms. Sharina Abdullah, Senior Director (Policy and Strategy Division) Cooperative Institute of Malaysia (CIM) speaking in the technical session

Ms. Sherina Abdullah, provided valuable insights into the cooperative movement in Malaysia, discussed the evolution of the cooperative movement in Malaysia and highlighted initiatives by the Ministry of Entrepreneur & Cooperatives Development (MECD). She emphasized the challenges faced by micro-level cooperatives in terms of decreasing turnover and non-financial issues like governance and business planning expertise. Abdullah shared the Malaysian government's initiatives in cooperative education, offering diploma courses and collaboration programs. Ms. Abdullah suggested adopting an online approach for education and training to increase accessibility. She also stressed the importance of strengthening international collaborations.

Additionally, the "IKMa Business Model" was presented as a practical training approach tailored to cooperative needs.

After the Chair, Keynote Address, and speakers' insightful presentations, participants engaged in a lively question-and-answer session, where pertinent questions were raised and adequately addressed by the Chair and respective speakers.

Technical Session 3- Key Recommendations:

1. **Strengthen Cooperative Education and Training Programs at all Levels:**
   - a. Standardized Training Modules : Develop standardized training modules and make them available in vernacular languages across the country, building upon the efforts initiated by the NCUI.
   - b. Member Activity Room: Establish "Member Activity Rooms" at each cooperative society to ensure regular member engagement and involvement in cooperative affairs.
   - c. Cooperative Literacy Centers: Create Cooperative Literacy Centers not only for members' education but also for subjects like financial literacy and health literacy.
   - d. Document Lesser-Known Cooperatives: Document stories of lesser-known cooperatives to be used in cooperative education and training programs.
   - e. Cooperative Education for Youth and Women: Introduce "Cooperative Education" at the higher education level and develop textbooks on cooperatives.
2. **Mandatory Training Programs for Elected Board of Directors:**
   - a. Skill-sets Mapping: Develop training packages based on skill-sets mapping of cooperative leaders.
   - b. Grass-root Level Training Institutions: Establish more training institutions at the grass-root level to cater to the vast number of farmers.
3. **Promote Research and Innovation in Cooperative Studies:**
   - a. National Level Research Agendas: Cooperative industry and training institutes should jointly prepare "National Level Research Agendas" to benefit the cooperative sector.
   - b. Research Fund Establishment: Establish a research fund at the national level.
   - c. Fellowships for Research: Award fellowships to students pursuing M.Sc and Ph.D. level research in academic institutions.
   - d. Promote Internship and Cooperative Work Experiences: Encourage students' internships and cooperative work experiences.
4. **Collaboration with Existing Institutions: Partnerships with Academic/ Technical Institutions:** Collaborate with existing educational institutions, including universities, colleges, and vocational training centers, to integrate cooperative education into their curriculum.
5. **National Cooperative University (NCUI):** Establish the National Cooperative University (NCU) as a center of excellence for cooperative education, training, and research, offering specialized courses, degree programs, and research opportunities tailored to the needs of the cooperative sector.
6. **Curriculum Development :** Develop comprehensive and updated curricula for cooperative education at various levels, covering topics such as cooperative principles, governance, management, finance, marketing, and technology.
7. **Online and Distance Learning :** Leverage digital platforms to offer online and distance learning programs for cooperative education, enabling wider reach and flexibility in learning schedules.
8. **Research and Innovation :** Promote interdisciplinary research collaborations, establish research centers, and encourage scholars to share their findings and experiences. Additionally, establish an incubation/ innovation lab to nurture cooperative start-ups.

तकनीकी सत्र-4: प्रतिस्पर्धी सहकारी व्यावसायिक उद्यमों हेतु इज ऑफ डूइंग बिज़नेस (व्यवसाय करने में आसानी)

अध्यक्षः डॉ. निधि पुंडीर, उपाध्यक्ष, ग्लोबल सीएसआर एवं एचसीएल फाउंडेशन

मुख्य वक्ताः श्री बिपिन केवड़िया, एथिक्स ग्रुप के संस्थापक एवं प्रबन्धक निदेशक

वक्ता:

1. श्री सी.ए. मिलिंद काले, अध्यक्ष, द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे
2. श्री यश रंगा, निदेशक, रणनीति एवं नवाचार, PYXERA ग्लोबल, राजस्थान
3. श्री एम.के. ठाकुर, अध्यक्ष, मिथिला सब्जी वितरण एवं वितरण सहकारिता संघ लिमिटेड, बिहार
4. श्रीमती अंजलि गोपाल पाटिल, उप कार्यकारी निदेशक, महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ क्रेडिट को- ऑपरेटिव सोसाइटीज, पुणे

तकनीकी सत्र -4 की एक झलक

डॉ. नवीन आनंद, सलाहकार, एएफसी इंडिया लिमिटेड, तकनीकी सत्र-4 के संचालक।

तकनीकी सत्र-4 "प्रतिस्पर्धी सहकारी व्यावसायिक उद्यमों के लिए व्यवसाय करने में आसानी" पर केंद्रित था। एएफसी इंडिया लिमिटेड, सलाहकार और सत्र **संचालक डॉ. नवीन आनंद** ने प्रतिभागियों को विषय से परिचित कराया और विशेषज्ञों तथा वक्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। सत्र की शुरुआत वैश्विक स्तर पर व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में सुधार के लिए भारत द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा के साथ हुई।

भारत ने कंपनी पंजीकरण के लिए अपने त्वरित सुधारों और सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ अपने कारोबारी माहौल में काफी सुधार किया है। 2015 में, व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत 142वें स्थान पर था लेकिन लगातार प्रयासों के कारण अब यह विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। सत्र में व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की अग्रणी पहल पर भी प्रकाश डाला गया जो प्रतिस्पर्धी माहौल में सहकारी उद्यमों को पनपने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

Technical Session 4: Ease of Doing Business for Competitive Cooperative Business Enterprises

Chair : . Nidhi Pundir, Vice President, Global CSR and HCL foundation
Keynote speaker : Shri Bipin Kevadiya, Founder and MD of Ethics group

Speakers:

1. Shri CA Milind Kale, Chairman, The Cosmos Co-operative Bank Ltd., Pune
2. Shri Yash Ranga, Director, Strategy & Innovation, PYXERA Global, Rajasthan
3. Shri M.K. Thakur, Chairman, Mithila Sabji Prasankaran Evem Vipanan Sahakarita Sangh Ltd. Bihar
4. Smt. Anjali Gopal Patil, Vice-Working Director, Maharashtra Federation of Credit Co-operative Societies, Pune

Dr. Naveen Anand, Consultant (Cooperation), AFC India Ltd. Moderator of the Session

The Technical Session 4 of the 17th Indian Cooperative Congress focused on "Ease of Doing Business for Competitive Cooperative Business Enterprises." **Dr. Naveen Anand, Consultant (Cooperation), AFC India Ltd.** and the session moderator, introduced the theme to participants and warmly welcomed the experts and speakers. The session commenced with a discussion on the significant strides India has made in improving its ease of doing business ranking on a global scale.

India, with its quick reforms for company registration and modernized ports facilitating cross-border trade, has significantly improved its business environment. In 2015, India ranked at 142 in terms of ease of doing business, but due to consistent efforts, it has now risen to the commendable position of 63rd in the world rankings. The session also highlighted the pioneering initiative of ranking states based on the Ease of Doing Business (EODB), which provides crucial insights for cooperative enterprises to thrive in a competitive environment.

डॉ. निधि पुंडीर, उपाध्यक्ष, ग्लोबल सीएसआर और एचसीएल फाउंडेशन प्रतिस्पर्धी सहकारी व्यापार उद्यमों के लिए "व्यापार करने में आसानी" के सत्र में बोलते हुए।

डॉ. निधि पुंडीर, उपाध्यक्ष, ग्लोबल सीएसआर और एचसीएल फाउंडेशन ने पैनल की अध्यक्षता की और एक सफल सहकारी व्यवसाय के संचालन और स्थापना के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि साझा की।

1. आकांक्षाः किसी भी सफल सहकारी उद्यम की नींव उसके सदस्यों की आकांक्षात्मक दृष्टि में निहित होती है। डॉ. पुंडीर ने सहकारी समितियों के बीच साझा दृष्टिकोण और उद्देश्य को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।
2. जोखिम लेने की क्षमता: किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में अंतर्निहित जोखिम शामिल होते हैं और वित्तीय समावेशन उद्यमियों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों के साथ समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ. पुंडीर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एचसीएल फाउंडेशन ने पिछले पांच वर्षों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से 45,000 महिलाओं के साथ साझेदारी की है जिससे उन्हें जोखिम लेने और उद्यमशीलता यात्रा शुरू करने के लिए सशक्त बनाया गया है।
3. क्षमता निर्माणः डॉ. पुंडीर ने हार्ड और सॉफ्ट दोनों कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहकारी सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया। क्षमता निर्माण प्रयासों के अभिन्न तत्वों के रूप में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई।
4. बाजार तक पहुंचः सहकारी व्यवसायों के लिए बाजारों तक पहुंच के अवसर पैदा करना उनकी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। डॉ. पुंडीर ने एचसीएल फाउंडेशन की पहल, "माई ई-हाट" का उदाहरण साझा किया जिसने कारीगरों और सामाजिक उद्यमों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान किया। उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता मानकों और बाजार की गतिशीलता पर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।
5. ईएसजी बाजार के अवसरः उभरता पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) बाजार भारतीय सहकारी समितियों के लिए अवसर प्रदान करता है। डॉ. पुंडीर ने सहकारी समितियों को पर्यावरण- अनुकूल उत्पाद और समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे वे बाजार में अद्वितीय बिक्री केंद्र बन सकें।
6. वित्तीय समावेशनः सरकार द्वारा प्रदान किए गए कई क्रेडिट लिंकेज अवसर आज वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और सहकारी उद्यमों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
7. बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी: आज के तेज गति वाले कारोबारी माहौल में दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी तक पहुंच महत्वपूर्ण है।

श्री बिपिन केवड़िया, एथिक्स ग्रुप के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

एथिक्स ग्रुप के सम्मानित संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री बिपिन केवडिया ने ज्ञानवर्धक भाषण दिया।

श्री बिपिन केवड़िया ने अपने संबोधन में सहकारी समितियों के सामने आने वाली कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, प्रतिस्पर्धी गोदामों की कमी और डिजिटल बाजारों तक सीमित पहुंच से संबंधित मुद्दे पर बात की। हालाँकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहकारिता मंत्रालय के गठन ने इन चुनौतियों को काफी हद तक कम कर दिया जिससे सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सत्र के दौरान आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं की चुनौती भी सामने आई क्योंकि सहकारी समितियों को प्रतिस्पर्धी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा धन की कमी एवं सीमित पहुंच सहकारी उद्यमों के विकास और विस्तार में बाधा बन रही थी।

Dr. Nidhi Pundir, Vice President of Global CSR and HCL Foundation speaking in the session of Ease of Doing Business for Competitive Cooperative Business Enterprises

Dr. Nidhi Pundir, Vice President of Global CSR and HCL Foundation, chaired the panel discussion and shared essential insights for operating and establishing a successful cooperative business:

1. Aspiration: The foundation of any successful cooperative venture lies in the aspirational vision of its members. Dr. Pundir emphasized the importance of fostering a shared vision and purpose among cooperators.
2. Risk-taking Ability: Starting a business entails inherent risks, and financial inclusion plays a vital role in supporting entrepreneurs with the necessary resources and opportunities to overcome these challenges. Dr. Pundir highlighted how HCL Foundation had partnered with 45,000 women through Self Help Groups (SHGs) over the last five years, empowering them to take risks and embark on entrepreneurial journeys.
3. Capacity Building: Dr. Pundir emphasized the significance of capacity building for cooperative members, focusing on both hard and soft skills development. Health, family planning, and other vital aspects were discussed as integral elements of capacity building efforts.
4. Access to Market: Creating opportunities for cooperative businesses to access markets is crucial for their growth. Dr. Pundir shared the example of HCL Foundation's initiative, "MY E-HAAT," which provided a platform for artisans and social enterprises to reach wider audiences. She emphasized the need for training on quality standards and market dynamics to enhance competitiveness.
5. ESG Market Opportunities: The emerging Environmental, Social, and Governance (ESG) market offers a new window of opportunities for Indian cooperatives. Dr. Pundir encouraged cooperatives to develop environment-friendly products and solutions, making them unique selling points in the market.
6. Financial Inclusion: Multiple credit linkage opportunities provided by the government today play a crucial role in enhancing financial inclusion and supporting cooperative enterprises.
7. Infrastructure and Technology: Access to modern infrastructure and technology is vital for improving efficiency and competitiveness in today's fast-paced business environment.

Shri Bipin Kevadiya, Founder and Managing Director of Ethics Group speaking in the technical session

Shri Bipin Kevadiya, the esteemed Founder and Managing Director of Ethics Group, who delivered an enlightening keynote address.

In his address, Shri Bipin Kevadiya highlighted several challenges faced by cooperatives, particularly concerning infrastructure, the lack of competitive warehouses, and limited access to digital marketplaces. However, he emphasized that the formation of the Ministry of Cooperation had significantly mitigated these challenges, leading to notable improvements in the cooperative ecosystem.

The challenge of supply chain inefficiencies was also brought to light during the session, as cooperatives faced hurdles in establishing competitive global supply chains. Furthermore, limited access to funds had been a recurring obstacle hindering the growth and expansion of cooperative enterprises.

श्री केवड़िया ने एनसीयूआई हाट पोर्टल और मोबाइल ऐप के लॉन्च की सराहना की जिसने सहकारी समितियों को चुनौतियों से निपटने के लिए मूल्यवान उपकरण प्रदान किए। उन्होंने सहकारी बाज़ार के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए पोर्टल और ऐप के लाभों पर प्रकाश डाला।

इसके तहत विक्रेताओं के लिए सहकारी बाज़ार के महत्व को समझाया गया जिसमें दिखाया गया कि इसने बिचौलियों को कैसे ख़त्म किया, ग्राहक आधार का विस्तार किया, वैश्विक विपणन को सुविधाजनक बनाया, सहकारी के लिए लाभ मार्जिन बढ़ाया और सोसायटी के सदस्यों को हर समय उत्पाद बिक्री को सक्षम बनाया। इसके अतिरिक्त उत्पाद खरीदारों के लिए सहकारी बाज़ारों के फायदे दिखाए। विविध उत्पाद चयन, प्रतिस्पर्धी कीमतें, डोरस्टेप उत्पाद वितरण, और परेशानी मुक्त रिटर्न और रिफंड. सहकारी उद्यमों की परिवर्तनकारी क्षमता का उदाहरण देने के लिए श्री केवड़िया ने दो प्रेरक उदाहरण साझा किए। पहले उदाहरण में दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक दवा फ़ार्मेसी श्रृंखला शामिल थी जिसमें उन्होने बताया कि कैसे सहकारी समितियां स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति ला सकती हैं। दूसरे केस स्टडी में हरियाणा राज्य के उन लोगों के बारें में बताया कि गांवों और ब्लॉक स्तरों पर 800 से अधिक किराना स्टोर स्थापित करने की सरकार की पहल ने 2000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। मुख्य भाषण के बाद विशिष्ट वक्ताओं द्वारा गहन चर्चा की गई और सहकारी विकास और व्यवहार्यता को बढ़ावा देने में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव भी साझा किए।

श्री सी.ए. मिलिंद काले, अध्यक्ष, द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

श्री सी.ए. मिलिंद काले, अध्यक्ष द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 117 साल पुराने बैंक की सफलता की कहानी प्रस्तुत की जो महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर देने के साथ उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंक की सफलता की कुंजी उसके जमाकर्ताओं की विश्वास प्रवृत्ति में निहित है। महिलाओं को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और बैलेंस शीट बनाने के प्रशिक्षण पर बैंक के फोकस ने उनकी साख में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होने क्रेडिट सहकारी बैंक के वास्तविक डेटा को प्रतिबिंबित करने के लिए अच्छी ऑडिटिंग व्यवस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डाला जिससे हितधारकों का विश्वास हासिल किया जा सके और दीर्घकालिक संघों को बढ़ावा दिया जा सके।

श्री यश रंगा, निदेशक, रणनीति एवं नवाचार, PYXERA ग्लोबल, राजस्थान तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

श्री यश रंगा ने प्रतिभागियों को सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र की फिर से कल्पना करने और परिवर्तनकारी नेतृत्व को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जबकि 80% सहकारी समितियाँ बुनियादी सिद्धांतों के पालन के कारण फलती-फूलती हैं। उन्होंने सहकारी प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री रंगा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्व स्तर पर इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता होने के नाते भारत डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से सहकारी समितियों को फलने-फूलने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। उन्होंने इस सम्मेलन से शुरुआत करते हुए विविध प्रतिभाओं और मानसिकताओं को एक साथ लाने में भा०रा०स०संघ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने भविष्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी क्षेत्र में युवा और परिवर्तनकारी नेतृत्व पेश करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

Shri Kevadiya expressed appreciation for the launch of the NCUI Haat portal and mobile app, which provided cooperative societies with valuable tools to overcome challenges. He elucidated the benefits of the portal and app, highlighting the cooperative marketplace's transformative impact.

The Cooperative Marketplace for Sellers was explained, demonstrating how it eliminated middlemen, expanded the customer base, facilitated global marketing, increased the profit margin for cooperative society members, and enabled 24x365 product selling.

Additionally, the Cooperative Marketplace for Product Buyers was described, showcasing the advantages of diverse product selections, competitive prices, doorstep product delivery, and hassle-free returns and refunds.

To exemplify the transformative potential of cooperative ventures, Shri Kevadiya shared two inspiring case studies. The first involved the world's largest generic medicine pharmacy chain, which exemplified how cooperatives could revolutionize healthcare access. The second case study highlighted the Haryana Government's initiative of establishing 800+ Kirana stores across villages and block levels, creating employment opportunities for over 2000 individuals, and bolstering rural economies.

The keynote address followed by insightful discussions led by distinguished speakers who shared their expertise and experiences in promoting cooperative growth and viability.

Shri C.A .Milind Kale, Chairman, The Cosmos Co-operative Bank Ltd. speaking in the technical session

Shri C.A. Milind Kale, Chairman, The Cosmos Co-operative Bank Ltd., presented the success story of a 117-year-old bank that has been providing handholding support to entrepreneurs, with a special emphasis on empowering women. He stressed that the key to the bank's success lay in the trust instinct of its depositors. The bank's focus on training women in record-keeping and maintaining balance sheets has significantly increased their creditworthiness. Emphasizing transparency, CA Milind Kale highlighted the importance of good auditing practices to reflect the true data of a credit cooperative bank, thereby gaining the trust of stakeholders and fostering long-term associations.

Shri Yash Ranga, Director, Strategy & Innovation, PYXERA Global, Rajasthan speaking in the technical session

Shri Yash Ranga, Director (Strategy and Innovation) of PYXERA Global, encouraged participants to reimagine the cooperative ecosystem and embrace transformational leadership. While 80% of cooperatives thrive due to their adherence to basic principles, he underscored the need to incorporate technology for cooperative progress. Shri Ranga highlighted that India, being the largest user of the internet globally, offers immense potential for cooperatives to flourish through digital platforms. He praised NCUI's role in bringing diverse talents and mindsets together, starting with this congress. He emphasized the necessity of introducing young and transformative leadership in the cooperative sector to drive future growth.

श्री एम. के. ठाकुर, अध्यक्ष, मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं वितरण सहकारिता संघ लिमिटेड, बिहार तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

श्री एम. के. ठाकुर ने सहकारी समिति की प्रभावशाली उपलब्धियों को साझा किया। बिहार के 18 जिलों में 50,000 किसानों की सदस्यता के साथ समिति ने 60 प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों को पंजीकृत किया है। श्री ठाकुर ने प्रत्येक परिचालन ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज और सफाई, छंटाई और ग्रेडिंग सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सहकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जिससे रिलायंस सहित विभिन्न खुदरा दुकानों में सब्जियों का वितरण संभव हो सके।

श्रीमती अंजलि गोपाल पाटिल, उप-कार्यकारी निदेशक, महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, पुणे तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

श्रीमती अंजलि गोपाल पाटिल ने कहा कि ये संस्थाएं महिलाओं और युवा उद्यमियों को पारंपरिक, घरेलू और घरेलू क्षेत्रों में वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है। उन्होंने सहकारी उद्यमों को सशक्त बनाने में व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तपोषण के महत्व पर जोर दिया। इसमे "सात सूत्र" जिसमें प्रशिक्षण, संपर्क, तकनीकी सहायता, वित्तीय सेवाएं, बाजार सहायता, कानूनी औपचारिकताएं और प्रचार और ब्रांडिंग शामिल हैं, सहकारी सफलता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं।

उन्होंने वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार सहायता के माध्यम से महिलाओं और युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने पर उनके जोर ने आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

सत्र एक गहन चर्चा के साथ संपन्न हुआ जिसमें नवीन दृष्टिकोण, परिवर्तनकारी नेतृत्व और तकनीकी प्रगति के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि ने प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ सहकारी व्यापार परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने के लिए सहकारी समितियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया।

Shri M.K. Thakur, Chairman, Mithila Sabji Prasankaran Evem Vipanan Sahakarita Sangh Ltd. Bihar speaking in the technical session

Shri M. K. Thakur, Chairman, Mithila Vegetable Processing and Marketing Cooperative, shared the cooperative's impressive achievements. With a farmer membership of 50,000 across 18 districts of Bihar, the cooperative has registered 60 primary vegetable cooperative societies. Shri Thakur outlined the cooperative's plans to establish infrastructure, including cold storage and cleaning, sorting, and grading facilities, in every operational block, enabling the distribution of vegetables to various retail outlets, including those of Reliance.

Smt. Anjali Gopal Patil, Vice-Working Director, Maharashtra Federation of Credit Co-operative Societies, Pune speaking in the technical session

Adv. Anjali Patil, Vice Working Director of MAFCOCS Pune and Chairperson of Kalyani Women Urban Credit Cooperative Society, Nashik, presented the innovative "Sahakar Udyami" program of MAFCOCS, offering financial support and training to women and young entrepreneurs in traditional, home-based, and SME enterprises. She emphasized the significance of business coaching and financing in empowering cooperative enterprises. The "Seven Sutras" at MAFCOCS, encompassing training, liasoning, technical support, financial services, market assistance, legal formalities, and promotion and branding, serve as guiding principles for cooperative success.

Adv. Anjali Patil's presentation resonated with the audience, offering valuable insights into the essential components of successful cooperative business enterprises. Her emphasis on empowering women and young entrepreneurs through financial support, training, and market assistance highlighted the pivotal role of cooperatives in driving economic growth and social development.

The session concluded with a vibrant discussion, highlighting the significance of empowering cooperatives through innovative approaches, transformative leadership, and technological advancements. The speakers' valuable insights served as an inspiration for cooperators to forge ahead, leveraging new opportunities to foster a competitive and sustainable cooperative business landscape.

तकनीकी सत्र 4- मुख्य सिफ़ारिशें :-

तकनीकी सत्र के दौरान अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और अन्य वक्ताओं ने ज्ञानवर्धक संबोधन दिया। उन्होने सहकारी व्यावसायिक उद्यमों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और अवसरों पर भी प्रकाश डाला। उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के आधार पर सत्र सहकारी समितियों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सिफारिशों के साथ संपन्न हुआ।

1. **वित्तीय समावेशन को बढ़ानाः** सहकारी उद्यमियों को धन और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन पहल को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना। यह उन्हें जोखिम लेने, अपने व्यवसाय का विस्तार करने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाएगा।
2. **प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन का समावेशः** सहकारी समितियों को परिचालन को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और व्यापक बाजारों तक पहुंचने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों को अपनाना चाहिए। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की क्षमता का लाभ उठाने से सहकारी समितियों को तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।
3. **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेशः** सहकारी सदस्यों को व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ आवश्यक हार्ड और सॉफ्ट कौशल से लैस करने से उनकी साख और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि होगी।
4. **पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देनाः** सहकारी संचालन में पारदर्शिता और सुशासन पर जोर देना। वित्तीय डेटा की नियमित ऑडिटिंग और सटीक रिपोर्टिंग से सदस्यों और हितधारकों के बीच विश्वास बनाने में मदद मिलेगी जिससे अधिक लोग सहकारी समिति से जुडने के लिए आकर्षित होंगे।
5. **बाजार में पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को सुगम बनानाः** सहकारी उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार में पहुंच में सुधार के लिए तंत्र बनाना। प्रतिस्पर्धी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने से सहकारी समितियां व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने में सक्षम होंगी।
6. **महिलाओं और युवा उद्यमियों को सशक्त बनानाः** सहकारी उद्यमों में महिलाओं और युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करने से उन्हें परिवर्तनकारी उद्यमों का नेतृत्व करने और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।
7. **परिवर्तनकारी नेतृत्वः** सहकारी समितियों को ऐसे परिवर्तनकारी नेताओं का पोषण और आकर्षित करना चाहिए जो नवीन रणनीतियों की कल्पना कर सकें और परिवर्तन को अपना सकें। परिवर्तनकारी नेतृत्व सहकारी समितियों को विकास और स्थिरता की ओर ले जाएगा।
8. **सहयोग और नेटवर्किंगः** सहकारी समितियों को आपस में और प्रासंगिक हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना चाहिए। सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ साझेदारी से विकास और संसाधन साझा करने के नए रास्ते खुलेंगे।
9. **सहकारी बाज़ारों को बढ़ावा देनाः** सहकारी बाज़ारों की स्थापना और उपयोग को प्रोत्साहित करना जो बिचौलियों को खत्म करते हैं, व्यापक बाज़ार में पहुंच प्रदान करते हैं और निर्बाध लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे मंच निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देंगे और सहकारी उत्पादों की दृश्यता बढाएंगे।
10. **वकालत और नीति समर्थनः** सहकारी समितियों को सामूहिक रूप से सहायक नीतियों और विनियमों की वकालत करनी चाहिए जो सहकारी विकास को प्रोत्साहित करती हैं। नीति निर्माताओं और सरकारी निकायों के साथ जुडने से यह सुनिश्चित होगा कि सहकारी क्षेत्र के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

तकनीकी सत्र -5: सहकारी शासन हेतु नवाचार एवं प्रौद्योगिकी

अध्यक्षः श्री शाजी के. वी., अध्यक्ष, नाबार्ड

मुख्य वक्ताः डॉ. आर. एस. पटेल, प्रबंध निदेशक, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड अमरेली, गुजरात

वक्ताः

1. श्री प्रसाद पाटिल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विश्वास सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक
2. श्री किशोर टी.के., मुख्य परियोजना समन्वयक, द यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, केरल
3. श्री साइमन जॉर्ज लामा, संस्थापक अध्यक्ष मल्टीस्टेट एनर्जी कंज्यूमर्स कम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सिक्किम

Technical Session 4 - Key Recommendations:

The insightful addresses from the Chair, Keynote Speaker, and four speakers during Technical Session 4 shed light on various challenges and opportunities faced by cooperative business enterprises. Building upon their valuable insights, the session concluded with key recommendations to foster a more competitive and conducive environment for cooperatives:

1. **Enhance Financial Inclusion:** Encourage and promote financial inclusion initiatives to provide cooperative entrepreneurs with access to funds and resources. This will empower them to take calculated risks, expand their businesses, and drive economic growth.
2. **Embrace Technology and Digital Transformation:** Cooperatives must adopt modern technology and digital solutions to streamline operations, enhance transparency, and reach wider markets. Leveraging the potential of the internet and digital platforms will help cooperatives stay competitive in the rapidly evolving business landscape.
3. **Invest in Training and Capacity Building:** Focus on providing comprehensive training and capacity-building programs to cooperative members. Equipping them with essential hard and soft skills, along with financial literacy, will enhance their creditworthiness and business acumen.
4. **Promote Transparency and Good Governance:** Emphasize transparency and good governance practices in cooperative operations. Regular auditing and accurate reporting of financial data will help build trust among members and stakeholders, attracting more people to associate with the cooperative society.
5. **Facilitate Market Access and Supply Chain Efficiency:** Create mechanisms to improve market access for cooperative products and services. Developing competitive global supply chains will enable cooperatives to reach a broader customer base and explore international markets.
6. **Empower Women and Young Entrepreneurs:** Encourage the active participation of women and young entrepreneurs in cooperative ventures. Providing financial support, training, and mentorship will empower them to lead transformative enterprises and contribute to socio-economic development.
7. **Nurture Transformational Leadership:** Cooperatives must nurture and attract transformational leaders who can envision innovative strategies and embrace change. Transformational leadership will drive cooperatives towards growth and sustainability.
8. **Collaboration and Networking:** Cooperatives should foster collaboration and networking among themselves and with relevant stakeholders. Partnering with government agencies, NGOs, and corporate entities will open new avenues for growth and resource sharing.
9. **Promote Cooperative Marketplaces:** Encourage the establishment and utilization of cooperative marketplaces that eliminate middlemen, provide wider market access, and facilitate seamless transactions. Such platforms will promote fair trade practices and enhance the visibility of cooperative products.
10. **Advocacy and Policy Support:** Cooperatives should collectively advocate for supportive policies and regulations that incentivize cooperative growth. Engaging with policymakers and government bodies will ensure that the cooperative sector's interests are adequately represented.

Technical Session 5: Innovation and Technology for Cooperative Governance

Chair : Shri Shaji K.V., Chairman, NABARD

Keynote speaker: Dr. R. S. Patel, Managing Director, Amreli District Co-operative Milk Producers' Union Limited Gujarat

Speakers:

1. Shri Prasad Patil, Chief Executive Officer, Vishwas Co-operative Bank Limited, Nashik
2. Shri Kishore T K, Chief Project Coordinator, The Uralungal Labour Contract Co-operative Society, Kerala
3. Shri Simon George Lama, Founder Chairman Multistate Energy Consumers' Cum Producers' Cooperative Society Ltd., Sikkim

"सहकारी शासन हेतु नवाचार एवं प्रौद्योगिकी" तकनीकी सत्र -5 की एक झलकः

श्रीमती संध्या कपूर, निदेशक, भा०रा० सह०संघ, सत्र की मॉडरेटर

इस महासम्मेलन का पाँचवाँ सत्र "सहकारी शासन हेतु नवाचार एवं प्रौद्योगिकी" पर केंद्रित था।, **श्रीमती संध्या कपूर, निदेशक एनसीयूआई** ने इस सत्र का कुशल संचालन किया। सत्र में सभी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्होंने सत्र के विषय के बारें में बताया और उपस्थित सम्मानित विशेषज्ञों और वक्ताओं को शुभकामनाएं दीं।

सहकारी शासन के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के तकनीकी सत्र में बोलते हुए श्री शाजी के.वी., अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

श्री शाजी के.वी. ने नाबार्ड की यात्रा और उपलब्धियों पर विचार साझा किए। अपने संबोधन में उन्होंने नवाचार, प्रौद्योगिकी और सहकारी गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला।

उनके द्वारा विचारों, सहकारी परिदृश्य के भीतर नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए कई प्रमुख अनिवार्यताओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने सहकारी समितियों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में नए विचारों और तकनीकी प्रगति को अपनाने पर जोर दिया। सेवा वितरण में गति, सटीकता, पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ाकर सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता के साथ - साथ समाज के पहले से वंचित क्षेत्रों तक प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने की अनिवार्यता पर बल दिया गया।

श्री शाजी के.वी. ने सहयोगात्मक तालमेल के माध्यम से नए स्टार्टअप के लिए पोषण आधार के रूप में सहकारी समितियों की कल्पना की और सहकारी ढांचे में नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए आधारशिला के रूप में मजबूत शासन को मान्यता दी। सहकारी समितियों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निकायों से नीति समर्थन की वकालत करते हुए उन्होंनें दूरदर्शी सहकारी नीति को आकार देने, विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों को अग्रणी के रूप में स्थापित करने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

सत्र में नाबार्ड द्वारा की गई पहलों का भी खुलासा किया गया जिसमें एक प्रौद्योगिकी क्लाउड की स्थापना और देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का प्रावधान शामिल है। सहकारिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप सभी पैक्स में कम्प्यूटरीकरण शुरू करने के लिए नाबार्ड द्वारा चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया। कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड की अटूट वित्तीय सहायता को स्वीकार किया गया।

The Technical Session 5 of the 17th Indian Cooperative Congress, focusing on "Innovation and Technology for Cooperative Governance," commenced under the adept moderation of **Smt. Sandhya Kapoor, Director NCUI.** With a warm welcome, she introduced the session's theme and extended greetings to the esteemed experts and speakers present.

Smt. Sandhya Kapoor, Director NCUI-Moderator of the Session

Shri Shaji K. V., Chairman of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) speaking in the technical session of Innovation and Technology for Cooperative Governance

The distinguished Chairman of the panel, **Shri Shaji K. V., the eminent Chairman of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)**, shared his insights, reflecting upon the journey and accomplishments of NABARD. In his address, he illuminated critical facets at the nexus of innovation, technology, and cooperative activities.

In the enlightening discourse led by Shri Shaji K. V., Chairman of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), several key imperatives were highlighted to catalyze innovation within the cooperative landscape. He emphasized the crucial adoption of fresh ideas and technological advancements as catalysts for the evolution of cooperatives. The imperative to extend technology's reach to previously unreached segments of society was stressed, alongside the potential for technology to empower cooperatives by enhancing speed, accuracy, transparency, and convenience in service delivery.

जमीनी स्तर और सामाजिक नवाचारों के पोषण के लिए उपजाऊ आधार के रूप में सहकारी समितियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए इसका समापन हुआ। संक्षेप में सत्र सहकारी शासन को आकार देने में नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण महत्व पर केंद्रित रहा जिसमें क्षेत्र को गतिशील विकास और प्रगति की ओर ले जाने के लिए सहकारी भागीदारी की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया गया।

डॉ. आर.एस. पटेल, प्रबंध निदेशक, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, अमरेली, गुजरात तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

डॉ. आर.एस. पटेल, प्रबंध निदेशक, अमरेली जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, गुजरात ने एक ज्ञानवर्धक मुख्य भाषण के साथ अमूल डेयरी की संरचना और सराहनीय कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की जो सहकारी क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने में डेयरी सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जो सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत और कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 35 प्रतिशत है।

डॉ. पटेल ने सुदृढ़ प्रशासन और प्रभावी नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हुए सहकारी समितियों के विकास के लिए नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने लोकतांत्रिक नियंत्रण की भूमिका पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और उपलब्ध जानकारी के माध्यम से सहकारी समितियों की दिशा को आकार देना चाहिए। नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होने आधुनिक बुनियादी ढांचे और मशीनरी की आवश्यक खरीद पर ज़ोर दिया जो नए विचारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अतिरिक्त उन्होने ध्यान आकर्षित करते हुए सहकारी समितियों के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग के महत्व पर जोर दिया गया।

डॉ. पटेल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सहकारी सफलता, दृश्यता, ग्राहक विश्वास और बढ़ी हुई बाज़ार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी विपणन रणनीतियाँ और एक मजबूत ब्रांड की उपस्थिति महत्वपूर्ण है।

संक्षेप में उन्होनें मुख्य भाषण में एक व्यापक माहौल तैयार किया और प्रतिभागियों को अमूल डेयरी मॉडल के बारे में बताया और सहकारी समितियों की जीत में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डाला। उन्होनें सहकारी शासन के परिदृश्य को आकार देने में मजबूत, लोकतांत्रिक नियंत्रण, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक ब्रांडिंग के महत्व को रेखांकित किया।

श्री पाटिल ने सहकारी परिदृश्य में शासन की महत्वपूर्ण भूमिका और प्रौद्योगिकी के आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस के उपयोग को भी रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण न केवल दक्षता बढ़ाता है बल्कि जटिल कार्यों को सरल बनाकर और व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ाकर जीवन को बेहतर बनाने में भी योगदान देता है।

प्रौद्योगिकी की समय-बचत और डेटा निर्माण क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए श्री पाटिल ने इसे अपनाने के महत्व पर जोर दिया। हालाँकि उन्होंने संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए तकनीकी क्षेत्र में सुरक्षा और गोपनीयता उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

Shri Shaji K. V. envisioned cooperatives as nurturing grounds for novel startups through collaborative synergy and recognized robust governance as the cornerstone to effectively integrate innovation and technology into cooperative frameworks. Advocating for policy support from governmental bodies to nurture innovation within cooperatives, Shri Sahji shed light on NABARD's pivotal role in shaping a forward-looking cooperative policy, positioning cooperatives as pioneers across diverse sectors. Collaborative partnerships were underscored as potent tools for amplifying cooperative impact, extending beyond credit to domains like grain storage.

The session further unveiled NABARD's initiatives, including the establishment of a technology cloud and provision of Core Banking Solutions (CBS) to Primary Agricultural Credit Societies (PACS) nationwide.

Ongoing efforts by NABARD to usher in computerization across all PACS, in alignment with the Ministry of Cooperation's directives, were also highlighted. NABARD's unwavering financial support to state cooperative banks for skill augmentation and capacity building was acknowledged.

The discourse concluded by underscoring cooperatives' role as fertile grounds for nurturing grassroots and social innovations. In summation, the session resonated with the pivotal significance of innovation and technology in shaping cooperative governance, emphasizing the transformative potential of cooperative partnerships to steer the sector toward dynamic growth and evolution.

Dr. R. S. Patel, Managing Director, Amreli District Co-operative Milk Producers' Union Limited, Gujarat speaking in the technical session

Dr. R. S. Patel, Managing Director, Amreli District Co-operative Milk Producers' Union Limited, Gujarat with an illuminating keynote address provided insightful insights into the structure and commendable practices of the Amul Dairy, a pioneering example in the cooperative domain. He underscored the pivotal role of dairy cooperatives in contributing significantly to the nation's economy, constituting 5% of the GDP and an impressive 35% of the agricultural GDP.

Dr. Patel elaborated on the prerequisites for the triumph of cooperatives, emphasizing the importance of sound governance and effective leadership. He highlighted the essence of democratic control, emphasizing that the members' active participation and input should shape the direction of cooperatives. To facilitate innovation, Dr. Patel noted the essential procurement of modern infrastructure and machinery, which play an instrumental role in fostering novel ideas.

Drawing attention to the broader picture, the importance of marketing and branding for cooperatives was emphasized. Dr. Patel underscored that effective marketing strategies and a robust brand presence are crucial for cooperative success, ensuring visibility, customer trust, and enhanced market reach.

In summation, Dr. R. S. Patel's keynote address set a comprehensive tone for the session, enlightening the participants about the Amul Dairy model and elucidating the critical factors that contribute to the triumph of cooperatives. His insights underscored the significance of robust governance, democratic control, technological advancements, and strategic branding in shaping the landscape of cooperative governance.

The speaker wise panel discussion, commenced with an illuminating address by Shri Prasad Patil, Chief Executive Officer of Vishwas Co-operative Bank Limited, Nashik. Shri Patil underscored the pivotal role of governance and the intelligent utilization of technology in the cooperative landscape. He emphasized that the integration of technology, particularly Artificial Intelligence, not only enhances efficiency but also contributes to the betterment of lives by simplifying complex tasks and bolstering productivity in businesses.

Highlighting the time-saving and data-forming capabilities of technology, Shri Patil stressed the importance of its adoption. However, he also emphasized the critical need for security and privacy measures in the technological realm to safeguard sensitive information.

श्री किशोर टी.के., मुख्य परियोजना समन्वयक, यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, केरल, तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

केरल में यूरातुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मुख्य परियोजना **समन्वयक श्री किशोर टी.के.** ने सहकारी क्षेत्र में अधिक युवाओं को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान दिलाया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अगले दशक में नौकरियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खतरे में होगा जिससे रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए युवाओं को शामिल करने की आवश्यकता हैं।

श्री किशोर ने एक व्यापक व्यावसायिक रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें सांस्कृतिक परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन शामिल हों। उन्होंने प्रभावी मॉडल तैयार करने के महत्व को रेखांकित किया जो सक्रिय सदस्य भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और जो सहकारी सफलता की आधारशिला भी है।

श्री साइमन जॉर्ज लामा, संस्थापक अध्यक्ष, मल्टीस्टेट एनर्जी कंज्यूमर्स कम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सिक्किम तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

सिक्किम में मल्टीस्टेट एनर्जी कंज्यूमर्स कम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के **संस्थापक अध्यक्ष श्री साइमन जॉर्ज** लामा ने जलविद्युत उत्पादन के लिए बहु-राज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम के तहत एक अभूतपूर्व पहल शुरू की। जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से यह अग्रणी सहकारी उद्यम विशेष रूप से भारत भर के अविकसित क्षेत्रों और राज्यों में अपार संभावनाएं रखता है।

श्री लामा ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार की ऊर्जा नीति के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तत्वावधान में सहकारी क्षेत्र समर्पित युवाओं को परिवर्तनकारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अपनी ऊर्जा को जलविद्युत उत्पादन में लगाकर सहकारी क्षेत्र भारत के ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संक्षेप में इस तकनीकी सत्र में वक्ताओं के संबोधन ने सामूहिक रूप से नवाचार, प्रौद्योगिकी और सहकारी शासन के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला। उनकी अंतर्दृष्टि ने कुशल संचालन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने, क्षेत्र की जीवन शक्ति सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को शामिल करने और नए क्षितिज की खोज करने की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया। जैसा कि अग्रणी जलविद्युत पहल द्वारा उदाहरण दिया गया है, इन विचार-विमर्शों में मजबूत और स्थायी सहकारी शासन को बढ़ावा देने में नवाचार और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया गया।

Shri Kishor T. K., Chief Project Coordinator, The Uralungal Labour Contract Co-operative Society in Kerala speaking in the technical session

Shri Kishor T. K., Chief Project Coordinator, The Uralungal Labour Contract Co-operative Society in Kerala, brought attention to the pressing need to involve more youth in the cooperative sector. He highlighted that a significant portion of jobs would be at risk over the next decade, accentuating the urgency of engaging youth to bolster employment opportunities.

Shri Kishor emphasized the necessity for a comprehensive business strategy that encompasses cultural transformation, business transformation, and digital transformation. He underscored the significance of formulating effective models that encourage active member participation, a cornerstone of cooperative success.

Shri Simon George Lama, Founder Chairman, Multistate Energy Consumers' Cum Producers' Cooperative Society Ltd. Sikkim speaking in the technical session

Shri Simon George Lama, the Founder Chairman, Multistate Energy Consumers' Cum Producers' Cooperative Society Ltd. in Sikkim, introduced a groundbreaking initiative under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act for hydropower generation. This pioneering cooperative venture, aimed at harnessing hydropower potential, carries immense promise, particularly in underdeveloped regions and states across India.

Shri Lama articulated that the cooperative sector, under the aegis of the Green Hydrogen Policy within the Energy Policy of the Government of India, offers dedicated youth a platform to initiate transformative projects. By channeling their energies into hydropower generation, the cooperative sector can play a pivotal role in India's energy landscape.

In summary, the speakers' addresses in Technical Session 5 collectively highlighted the symbiotic relationship between innovation, technology, and cooperative governance. Their insights underscored the criticality of harnessing emerging technologies for efficient operations, engaging youth to ensure the sector's vitality, and exploring new horizons, as exemplified by the pioneering hydropower initiative. These deliberations emphasized the transformative potential of innovation and technology in fostering robust and sustainable cooperative governance.

तकनीकी सत्र 5 - मुख्य सिफ़ारिशें:-

1. **सुशासन के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना।**
   - सहकारी उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए पैक्स कम्प्यूटरीकरण, सीबीएस सिस्टम, ईआरपी सिस्टम और "भारत कॉप टैग" जैसी सहकार मंत्रालय के तहत नाबार्ड की पहल का लाभ उठाएं।
   - विशेष रूप से सहकारी समितियों के माध्यम से जमीनी स्तर और सामाजिक नवाचारों को बढ़ावा देना।
   - अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के बराबर होने के लिए सहकारी समितियों की स्थिति को ऊपर उन्नत बनाना।
2. **प्रभावी शासन के लिए संचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना।**
   - स्व-विनियमन और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रक्रियाओं और प्रणालियों के साथ मजबूत सहकारी समितियों के सभी स्तरों पर मानक संचालन प्रक्रियाएं स्थापित करें।
3. **सतत प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।**
   - अपने उत्पाद और सेवा की पेशकश के संदर्भ में सहकारी समितियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को नियोजित करना।
4. **सहकारी शासन के लिए डिजिटल उपकरण और प्लेटफ़ॉर्म अपनाना।**
   - मूल्य संरेखण, संस्कृति प्रशिक्षण और जुड़ाव के माध्यम से सहकारी समितियों को सांस्कृतिक रूप से परिवर्तित करना।
   - व्यवसाय, वास्तुकला, प्रक्रियाओं और संसाधन आबंटन को विकसित करके व्यवसाय परिवर्तन करना।
   - डेटा और एप्लिकेशन मैपिंग, और प्रौद्योगिकी वास्तुकला सिद्धांतों को शामिल करते हुए डिजिटल परिवर्तन निष्पादित
   - नए संगठनात्मक डिजाइन विकसित करना, चुस्त टीमें बनाना, नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान कराना और शासन ढांचे की स्थापना करना।
5. **डिजिटल विभाजन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।**
   - डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए मंच सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
   - डिजिटल पहुंच और सेवाओं को बढ़ाने के लिए फिनटेक स्टार्ट-अप के साथ सहयोग करना।
   - उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रबंधन में सक्षम कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास को प्राथमिकता देना।
6. **साइबर सुरक्षा उपाय बढ़ाना ।**
   - सहकारी डेटा और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना।
7. **तकनीकी अवसंरचना विकास को बढ़ावा:**
   - देशभर में बहु-राज्य ऊर्जा सहकारी समितियों द्वारा सिक्किम की सफल प्रथाओं का अनुकरण करना। पर्वतीय क्षेत्रों में मिनी और ग्रिड से जुडे जल विद्युत संयंत्रों जैसी पहलों को लागू करना और हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर स्थापित करना।

तकनीकी सत्र-6: सहकारिता के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना

अध्यक्षः श्री रंजीत कुमार (प्रधान वैज्ञानिक), आईसीएआर-एनएएआरएम, हैदराबाद

मुख्य वक्ताः डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग

वक्ता:

1. श्रीमती मिराई चटर्जी, अध्यक्ष, स्व-रोज़गार महिला संघ (सेवा), गुजरात
2. श्रीमती शुभ्रा देवी (प्रसिद्ध महिला उद्यमी और संस्थापक), मीरा फूड्स, मणिपुर
3. सुश्री प्रीति पटेल, उपाध्यक्ष/आईसीए-एपी महिला समिति गुजरात महिला क्रेडिट सहकारी समिति लिमिटेड, गुजरात
4. श्री जयेन मेहता, प्रबंध निदेशक (प्रभारी) गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (एएमयूएल) गुजरात

तकनीकी सत्र-6 की एक झलकः सहकारिता के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।

Technical Session 5 - Key Recommendations:

1. **Embrace Innovation and Technology for Good Governance:**

- Leverage NABARD's initiatives under the Ministry of Cooperation, such as PACS computerization, CBS System, ERP System, and "Bharat Coop Tag" for branding cooperative products.
- Foster grass-root and social innovations exclusively through cooperatives.
- Elevate the status of cooperatives to be on par with other business entities.

2. **Standardize Operating Procedures for Effective Governance:**

- Establish Standard Operating Procedures at all levels of cooperatives, fortified with robust processes and systems to ensure self-regulation and good governance.

3. **Promote Sustainable Competitive Cooperatives:**

- Employ technology to enhance the competitiveness of cooperatives in terms of their product and service offerings.

4. **Adopt Digital Tools and Platforms for Cooperative Governance:**

- Culturally transform cooperatives through value alignment, culture training, and engagement.
- Undertake business transformation by developing business architecture, processes, and resource allocation.
- Execute digital transformation encompassing agile model development, data and application mapping, and technology architecture principles.
- Develop new organizational designs, form agile teams, provide leadership training, and establish governance frameworks.

5. **Bridge the Digital Divide and Promote Digital Literacy**

- Promote platform cooperatives to bridge the digital divide.
- Collaborate with FinTech start-ups to enhance digital access and services.
- Prioritize skill development to ensure a competent workforce capable of managing advanced technologies.

6. **Enhance Cybersecurity Measures:**

- Bolster cybersecurity to safeguard cooperative data and sensitive information.

7. **Foster Technical Infrastructure Development:**

- Emulate the successful practices of Multi-State Energy Cooperatives, Sikkim, nationwide. Implement initiatives like mini and grid-connected hydro power plants in mountainous and hilly regions and establish hydrogen valley innovation clusters.

Technical Session 6: Promoting Gender Equality and Social Inclusion through Cooperatives

Chair : Dr. Ranjeet Kumar (Principal Scientist), ICAR-NAARM: Hyderabad

Keynote speaker: Dr. Neelam Patel, Senior Adviser, NITI Aayog

Speakers:

1. Smt. Mirai Chatterjee, Chairperson, Self-Employed Women's Association (SEWA), Gujarat
2. Smt. Shubhra Devi (Renowned Women Entrepreneur & Founder), Meira Foods, Manipur
3. Ms. Priti Patel, Vice Chairperson / ICA-AP Women Committee Gujarat Mahila Credit Cooperative Society Ltd., Gujarat
4. Shri Jayen Mehta, Managing Director (I/c) Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (AMUL) Gujarat

A glimpse of Technical Session 6: Promoting Gender Equality and Social Inclusion through Cooperatives

श्री बिनोद आनंद, महासचिव, कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ फॉर रूरल इंडिया (सीएनआरआई), दिल्ली, तकनीकी सत्र के मॉडरेटर।

यह तकनीकी सत्र सहकारिता के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना" विषय पर केंद्रित था। सत्र का **संचालन श्री बिनोद आनंद, महासचिव, कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ फॉर रूरल इंडिया (सीएनआरआई), दिल्ली,** जिन्होंने प्रतिभागियों को विषय से परिचित कराया और विशेषज्ञों एवं वक्ताओं का स्वागत किया।

डॉ. रंजीत कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-एनएएआरएम हैदराबाद "सहकारी समितियों के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना" के तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

पैनल अध्यक्ष डॉ. रंजीत कुमार ने भारत के विशाल सहकारी क्षेत्र जिसमें 8.5 लाख सहकारी समितियां शामिल हैं, उसमें लैंगिक समानता के महत्व पर जोर देते हुए चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने लैंगिक समानता हासिल करने और इस क्षेत्र में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सत्र के दौरान उन्होने सहकारी समितियों में महिलाओं की कम भागीदारी की चुनौती के बारे में बताया जिसमें केवल 1.5% महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल थीं। इस असमानता को एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में पहचाना गया जिस पर तत्काल ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता है।

डॉ. कुमार द्वारा उठाई गई एक और चुनौती सहकारी समितियों में सदस्यता से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि संपत्ति के बिना महिलाओं को अक्सर सदस्यता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो सहकारी समितियों के भीतर उनके प्रतिनिधित्व और अवसरों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है। सभी सदस्यों के लिए समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

डॉ. रंजीत कुमार ने 36-37 प्रतिशत प्रतिनिधित्व के साथ सहकारी समितियों के भीतर महिलाओं के नेतृत्व की स्थिति के संदर्भ में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसकी तुलना ब्रिक्स देशों से की जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 32 प्रतिशत है और जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भारत की सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है।

डॉ. कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि सहकारी समितियों को समुदाय के लिए चिंता के सिद्धांत के साथ काम करना चाहिए और नेतृत्व पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों के भीतर महिलाओं के लिए नेतृत्व के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपाय और नीतियां तैयार की जानी चाहिए। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने सहकारी क्षेत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है।

Mr. Binod Anand, Secretary General of Confederation of NGOs for Rural India (CNRI), Delhi-Moderator of the Technical Session

The Technical Session 6 of the 17th Indian Cooperative Congress centered on the theme "Promoting Gender Equality and Social Inclusion through Cooperatives." The session was moderated by **Mr. Binod Anand, Secretary General of Confederation of NGOs for Rural India (CNRI),** Delhi who introduced the topic to the participants and welcomed the experts and speakers

Dr. Ranjeet Kumar, Principal Scientist at ICAR-NAARM Hyderabad speaking in the technical session of Promoting Gender Equality and Social Inclusion through Cooperatives

The Chairman of the Panel, **Dr. Ranjeet Kumar, Principal Scientist at ICAR-NAARM Hyderabad,** initiated the discussion by emphasizing the significance of gender equality within India's vast cooperative sector, which comprises 8.5 lakh cooperatives. He highlighted the pressing need to achieve gender equality and promote social inclusion within this sector.

During the session, Dr. Ranjeet Kumar pointed out the challenge of low women's participation in cooperatives, with only 1.5% of women actively involved. This disparity was identified as a significant hurdle that needs immediate attention and rectification.

Another challenge raised by Dr. Kumar was related to membership in cooperatives. He noted that women without assets often face difficulties in obtaining membership, which hinders their representation and access to opportunities within cooperatives. Addressing this issue is crucial to ensure equal participation and representation for all members.

Dr. Ranjeet Kumar highlighted India's progress in terms of women's leadership positions within cooperatives, with36-37% representation. He compared this to BRICS countries, where the representation of women is 32%, illustrating India's positive strides in promoting gender equality and women's empowerment.

As a key recommendation, Dr. Kumar emphasized that cooperatives should work with the principle of concern for the community and focus on increasing the number of women in leadership positions. To achieve this goal, specific measures and policies should be framed to promote leadership opportunities for women within cooperatives. A strategic approach is essential to foster gender equality and women's empowerment, making the cooperative sector more inclusive and representative.

डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग तकनीकी सत्र में बोलतीं हुई।

डॉ. नीलम पटेल ने अपने मुख्य भाषण में सार्वजनिक भागीदारी, व्यापार करने में आसानी, मेक इन इंडिया और भारत में आत्मनिर्भरता से प्रेरित एक समावेशी अर्थव्यवस्था के सपने पर जोर दिया। उन्होंने दुनिया की शीर्ष पांच सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की स्थिति को स्वीकार किया।

एक महत्वपूर्ण आंकड़े पर प्रकाश डालते हुए डॉ. नीलम पटेल ने कहा कि 2025 तक भारत की आबादी का पांचवां हिस्सा युवा होगा जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए युवाओं की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कृषि में लैंगिक अंतर को दूर करने में हालिया प्रगति की ओर भी ध्यान दिलाया।

उन्होंने संस्थागत ऋण तक पहुँचने और आवश्यक कौशल हासिल करने में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। वर्तमान में केवल 5.7% ऋण महिला किसानों को जाता है और कौशल दर सिर्फ 4% से 6% तक ही है। महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। वर्तमान में केवल 5.7% ऋण महिला किसानों को जाता है और कौशल दर सिर्फ 4% से 6% तक ही है।

डॉ. पटेल ने आर्थिक सशक्तीकरण, सशक्तीकरण, दक्षता और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 पी से 4 ई दृष्टिकोण की शुरुआत की। उन्होंने एक अध्ययन के नतीजे साझा किए जिसमें संकेत दिया गया कि 8.6% किसान सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं जो काफी कम ब्याज दरों पर उपलल्ध कराया जाता हैं।

उन्होने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह सरकारी विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में कैसे योगदान देता है।

ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए डॉ. नीलम पटेल ने भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग हब और स्पाइक मॉडल के साथ "एक गांव, एक उद्यम" मॉडल का सुझाव दिया। उन्होंने फलों और सब्जियों में स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण की आवश्यकता पर जोर दिया जो वर्तमान में केवल तीन प्रतिशत है। गैस और बिजली जैसे उपयोगी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने के लिए कृषि और संबद्ध कचरे के कुशल उपयोग की भी वकालत की गई।

उन्होने बाजार विकास सहायता और उर्वरकों के एकीकृत उपयोग सहित हाल के सरकारी प्रयासों को रेखांकित किया गया। डॉ. पटेल ने नीति आयोग की पहल पर भी प्रकाश डाला जो किसानों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं से जोड़ती है। यह कार्यक्रम वर्तमान में छह राज्यों और बारह जिलों में चालू है जिससे कृषि और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ हो रहा है। साथ ही यह कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में भी योगदान दे रहा है।

डॉ. नीलम पटेल ने आगे बढ़ने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसमें महिलाओं के लिए कौशल और उन्नयन कार्यक्रम, एक सक्षम संस्थागत वातावरण बनाना, गांव और स्वयं सहायता समूह स्तरों पर मॉडल सहकारी समितियों को मजबूत करना और महिलाओं की सक्रिय आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अवैतनिक देखभाल कार्यों को कम करना, पुनर्वितरित करना और पुरस्कृत करना शामिल है।

डॉ. पटेल के भाषण ने तकनीकी सत्र के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जिससे प्रतिभागियों को सहकारी समितियों के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जिससे भारत में एक समावेशी और सशक्त सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद अन्य सम्मानित वक्ताओं का संबोधन हुआ जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में अपने विचार और अनुभव साझा किए।

श्रीमती मिराई चटर्जी, अध्यक्ष, "सेवा" गुजरात तकनीकी सत्र में बोलती हुई।

श्रीमती चटर्जी ने "सेवा" की सफलता की कहानी पर प्रकाश डाला जो 50 साल पहले एक सहकारी संस्था के रूप में शुरू हुई थी और जिसमें प्रत्येक 4,000 महिलाओं ने प्रति व्यक्ति 10 रुपये का योगदान दिया था। आज "सेवा" बिना किसी अनुदान के 600 करोड़ रुपये का बैंक बन गई है और जो छह क्षेत्रों में 300,000 महिला श्रमिकों के जीवन को प्रभावित करता है। उन्होंने महिलाओं को संगठित करने और एकजुट करने, सहकार के माध्यम से नेतृत्व निर्माण करने और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान लचीलापन विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। मजबूत सहकारी समितियों के संचालक के रूप में धैर्य और दृढ़ता पर जोर देते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित किया। श्रीमती चटर्जी ने महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए डेटा और अनुसंधान को सहकारी समितियों में शामिल करके सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने का भी सुझाव दिया।

Dr. Neelam Patel, Senior Adviser at NITI Aayog speaking in the technical session

Dr. Neelam Patel, Senior Adviser at NITI Aayog in her Keynote address, emphasized the dream of an inclusive economy, driven by public participation, ease of doing business, Make in India, and Aatmanirbhar(self-reliance) in India. She acknowledged India's position as one of the world's top five fastest-growing economies.

Highlighting an important statistic, Dr. Neelam Patel noted that by 2025, one-fifth of India's population would be young, signifying the potential of the youth to contribute significantly to the nation's progress. She further pointed out the recent progress in overcoming gender gaps in agriculture. However, she also shed light on the challenges faced by women in accessing institutional credit and acquiring necessary skills. Currently, only 5.7% of credit goes to women farmers, and skilling rates range from 4% to 6%.

Dr. Patel introduced the 3P to 4E approach, focusing on economic empowerment, empowerment, efficiency, and energy. She shared a study's results, which indicated that 8.6% of farmers take credit from cooperative societies that offer significantly lower interest rates. Emphasizing the importance of cooperative support, she highlighted how it contributes to the successful implementation of government development programs.

To empower rural areas, Dr. Neelam Patel suggested the "One Village, One Enterprise" model with Geographical Indication (GI) tag hubs and spike models. She emphasized the need for local-level processing in fruits and vegetables, which currently stands at only 3%. Efficient utilization of agricultural and allied waste to produce useful and environmentally friendly products, such as gas and electricity, was also advocated.

The Keynote Address outlined recent government efforts, including market development assistance and the integrated use of fertilizers. Dr. Patel highlighted the role of CREYO, an initiative by NITI Aayog, which connects farmers with end consumers through technology. The program is currently operational in six states and twelve districts, benefiting various sectors, including agriculture and handlooms, while also contributing to multiple Sustainable Development Goals (SDGs).

In the spirit of comprehensive and sustainable development, Dr. Neelam Patel put forth an integrated approach for the way forward. This includes skilling and upskilling programs for women, creating an enabling institutional environment, strengthening model cooperatives at the village and self-help group levels, and reducing, redistributing, and rewarding unpaid care work to encourage women's active economic participation.

The Keynote Address set a strong foundation for the Technical Session, inspiring participants to work towards promoting gender equality and social inclusion through cooperatives, thereby fostering an inclusive and empowering cooperative ecosystem in India. This followed by address of esteemed speakers who shared their insights and experiences in promoting gender equality and social inclusion through cooperatives.

Smt. Mirai Chatterjee, Chairperson, SEWA Gujarat speaking in the technical session

Smt. Mirai Chatterjee, Chairperson, SEWA Gujarat, highlighted the success story of SEWA, which started as a cooperative 50 years ago with 4,000 women contributing 10 rupees each. Today, SEWA has grown into a 600-crore bank without any grants and impacts the lives of 300,000 women workers across six sectors. She stressed the importance of organizing and mobilizing women, building their leadership through cooperation, and developing resilience during challenging times. Her emphasis on patience, perseverance, and persistence as drivers of strong cooperatives underscored the significance of women's economic empowerment and self-reliance. Smt. Chatterjee also suggested expanding the cooperative sector to include data and research cooperatives to further empower women.

श्रीमती शुभ्रा देवी, संस्थापक मीरा फूड्स, मणिपुर तकनीकी सत्र में बोलती हुई।

श्रीमती शुभ्रा देवी ने मणिपुर में सहकारी समितियों की स्थिति पर चर्चा की जहां लगभग 20,000 सहकारी समितियां बुनाई समितियों पर आधारित हैं और जिनमें से 80% का नेतृत्व महिलाएं करती हैं। मणिपुर में 50% महिलाएँ सहकारी समितियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय औसत 30% से अधिक है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और सहकारी समितियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने, विपणन और प्रसंस्करण के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होनें पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाली परिवहन चुनौतियों को स्वीकार किया गया और उन्होंने उच्च राजस्व उत्पन्न करने के लिए उच्च मूल्य वाले उत्पादों को लक्षित करने और उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने की सिफारिश की।

सुश्री प्रीति पटेल, उपाध्यक्ष आईसीए-एपी एवं सदस्य भा.रा. सह.संघ, महिला समिति तकनीकी सत्र में बोलती हुई।

सुश्री प्रीति पटेल ने वित्तीय संसाधनों, भूमि, ऋण और सहायता प्रणालियों तक सीमित पहुंच और सहकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारें में बताया। उन्होनें लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला जो नेतृत्व पदों तक महिलाओं की पहुंच को प्रतिबंधित करती हैं। उन्होंने सहकारी समितियों में सामाजिक समावेशन के महत्व पर जोर दिया और समावेशी नीतियों और प्रथाओं के विकास और कार्यान्वयन की सिफारिश की। अधिक समावेशी सहकारी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक समावेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक माना गया।

श्री जयेन मेहता, प्रबंध निदेशक (प्रभारी), जीसीएमएमएफ (अमूल) सत्र में बोलते हुए।

श्री जयेन मेहता ने वैश्विक लैंगिक अंतर और इसे समाप्त करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत में लैंगिक समानता प्राप्त करने में लगभग 150 साल लग गए। उन्होंने गुजरात के डेयरी उद्योग में महिलाओं के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला जहां 31% दूध उत्पादक और 4,639 महिला ग्राम डेयरी सहकारी समितियां परिचालन में हैं। इन समितियों की प्रबंध समितियों में 81,000 से अधिक महिलाओं की सदस्यता है और 75 महिलाओं ने दुग्ध संघों में निदेशक मंडल में कार्य किया है। उन्होंने अगले पांच वर्षों में 2 लाख नई सहकारी समितियां बनाने और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के गठन के सहकारिता मंत्रालय के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। महिला उद्यमिता और जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व सहित "डब्ल्यू 20 कम्युनिक 2023" प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया गया।

इस तकनीकी सत्र में अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और अन्य चार वक्ताओं के ज्ञानवर्धक संबोधन हुए जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने पर अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। इस तरह से सत्र एक समावेशी और सशक्त सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सिफारिशों के साथ संपन्न हुआ।

Smt. Shubha Devi, Founder, Meira Foods, Manipur speaking in the technical session

Ms. Priti Patel, Vice Chairperson ICA-AP Women Committee Speaking in the technical session

Smt. Shubha Devi, Founder, Meira Foods, Manipur, discussed the status of cooperatives in Manipur, where approximately 20,000 cooperatives are based on weaving societies, with 80% being led by women. In Manipur, 50% of women are involved in cooperatives, higher than the national average of 30%. She emphasized the need to provide women with opportunities for decision-making, marketing, and processing to empower them and ensure their active participation in cooperatives. The transportation challenges faced in the northeastern region were acknowledged, and she recommended targeting high-value products and promoting product exportation to generate higher revenue.

Ms. Priti Patel, Vice Chairperson ICA-AP Women Committee, addressed the challenges faced by women in actively engaging in cooperative activities, including limited access to financial resources, land, credit, and support systems. Gender stereotypes and discriminatory practices that restrict women's access to leadership positions were also highlighted. She stressed the importance of social inclusion in cooperatives and recommended the development and implementation of inclusive policies and practices. Raising awareness and providing education about social inclusion were also seen as essential to foster a more inclusive cooperative environment.

Sh. Jayen Mehta, Managing Director (I/c), GCMMF (AMUL) speaking in the session

Sh. Jayen Mehta, Managing Director (I/c), GCMMF (AMUL), highlighted the global gender gap and the urgency to close it, as it is projected to take around 150 years to achieve gender parity in India. He emphasized the significant impact of women in Gujarat's dairy industry, where 31% of milk producers and 4,639 women village dairy cooperative societies are in operation. Over 81,000 women hold membership in managing committees of these societies, and 75 women have served on the Board of Directors in milk unions. He also mentioned the Ministry of Cooperation's goal to create 2 lakh new cooperative societies in the next five years and the formation of the National Cooperative University for training. The "W20 Communique 2023" priorities, including women entrepreneurship and grassroots women leadership, were also mentioned.

The enriching Technical Session 6 witnessed enlightening addresses from the Chair, Keynote Speaker, and four speakers, who shared their experiences and perspectives on promoting gender equality and social inclusion through cooperatives. Building on their insights, the session concluded with key recommendations to foster an inclusive and empowering cooperative ecosystem.

तकनीकी सत्र - 6: मुख्य सिफ़ारिशें:

1. **सहकारी समितियों में महिला नेतृत्व को सशक्त बनानाः** सहकारी समितियों में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिकाओं को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना। इससे उनके द्वारा निर्णय लेने, विपणन, प्रसंस्करण और अन्य पहलुओं के लिए अवसर प्रदान करने से सहकारी समितियों के भीतर उनकी सक्रिय भागीदारी और प्रभाव बढ़ेगा।
2. **वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनानाः** वित्तीय संसाधनों, ऋण और सहायता प्रणालियों तक पहुंचने में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। वित्तीय सेवाओं और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी नीतियों और प्रथाओं को बढ़ावा देना।
3. **कौशल और शिक्षा को बढ़ावा देनाः** महिलाओं के बीच शिक्षण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। कौशल विकास कार्यक्रम और शैक्षिक अवसर प्रदान करने से महिलाओं को सहकारी गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।
4. **लचीलेपन और दृढ़ता को अपनानाः** मजबूत और टिकाऊ संस्थानों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों में लचीलेपन और दृढ़ता को बढ़ावा देना। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर जोर देना।
5. **सहकारी क्षेत्रों का विस्तार :** डेटा और अनुसंधान को सहकारी समितियों में शामिल करने के लिए सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने पर विचार करना। इससे महिलाओं की भागीदारी के नए रास्ते खुलेंगे और वे विविध क्षेत्रों में सशक्त होंगी।
6. **क्षेत्रीय सहकारी समितियों को मजबूत करनाः** समान प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कुछ क्षेत्रों में परिवहन चुनौतियों का समाधान करना। राजस्व सृजन को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले उत्पाद बनाने और उत्पाद निर्यात की खोज पर ध्यान केंद्रित करना।
7. **सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देनाः** सामाजिक समावेशन को केवल एक आकांक्षा नहीं, बल्कि सहकारी समितियों की आवश्यकता के रूप में प्राथमिकता देना। अधिक विविध और प्रतिनिधि सहकारी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समावेशी नीतियों और प्रथाओं का विकास और कार्यान्वयन करना।
8. **जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करनाः** सहकारी समितियों के भीतर जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना। सहायता, संसाधन और सलाह प्रदान करने से महिलाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने और बदलाव लाने में सक्षम होंगी।
9. **डिजिटल समावेशन को अपनानाः** सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ावा देकर लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
10. **साझेदारी और सहयोग को मजबूत करनाः** सहकारी समितियों, सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना। साथ मिलकर काम करने से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।
11. **महिला उद्यमिता को बढ़ावा देनाः** सहकारी समितियों के भीतर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना। सलाह, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने से महिलाएं अपने उद्यम शुरू करने और विकसित करने में सक्षम होंगी।
12. **अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देना और पुरस्कृत करनाः** महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अवैतनिक देखभाल कार्य को स्वीकार करना और पुरस्कृत करना। इससे घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ कम करके महिलाएं सहकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकती हैं।

तकनीकी सत्र -7: "भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली का महत्व"

अध्यक्षः श्री विजय कुमार, विशेष सचिव एवं केन्द्रीय पंजीयक सहकारी समितियां, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य वक्ताः श्री सतीश मराठे, निदेशक, आरबीआई

वक्ताः

1. श्री ज्योतिंद्र एम. मेहता, अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट, नई दिल्ली
2. श्री बी. सुब्रमण्यम, प्रबंध निदेशक, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (नैफसकोब),महाराष्ट्र
3. श्री के.के. रवींद्रन, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक महासंघ, नवी मुंबई
4. सुश्री जयश्री, एडवोकेट एवं एटॉर्नी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, पुणे
5. डॉ. सुकेश जामवार, प्रबंध निदेशक, बुलढाणा शहरी क्रेडिट सोसायटी, बुलढाणा, महाराष्ट्र

Technical Session 6 - Key Recommendations:

1. **Empower Women's Leadership in Cooperatives :** Encourage and support women's leadership roles in cooperative societies. Providing opportunities for decision-making, marketing, processing, and other aspects will enhance their active involvement and influence within cooperatives.
2. **Facilitate Access to Financial Resources :** Address the challenges faced by women in accessing financial resources, credit, and support systems. Promote inclusive policies and practices to ensure equitable access to financial services and resources.
3. **Promote Skilling and Education :** Focus on education, training, and capacity building among women. Providing skill development programs and educational opportunities will empower women to thrive in cooperative activities.
4. **Embrace Resilience and Persistence :** Foster resilience and persistence in cooperatives to build strong and sustainable institutions. Emphasize the importance of patience and perseverance to achieve women's economic empowerment and self-reliance.
5. **Expand Cooperative Sectors :** Consider expanding the cooperative sector to include data and research cooperatives. This will create new avenues for women's involvement and further empower them in diverse fields.
6. **Strengthen Regional Cooperatives :** Address transportation challenges in certain regions to ensure equitable progress. Focus on creating high-value products and exploring product exportation to boost revenue generation and empower local communities.
7. **Promote Social Inclusion :** Prioritize social inclusion as a necessity for cooperatives, not just an aspiration. Develop and implement inclusive policies and practices to ensure a more diverse and representative cooperative environment.
8. **Encourage Grassroots Women Leadership :** Empower grassroots women leadership within cooperatives. Providing support, resources, and mentorship will enable women to effectively lead and drive change at the grassroots level.
9. **Embrace Digital Inclusion :** Bridge the gender digital divide by promoting digital literacy and access to technology for women in cooperatives. This will enhance their participation in the digital economy and facilitate growth.
10. **Strengthen Partnerships and Collaboration :** Foster partnerships and collaboration among cooperatives, government agencies, NGOs, and other stakeholders. Working together will create a more supportive ecosystem for promoting gender equality and social inclusion.
11. **Promote Women Entrepreneurship :** Encourage and support women entrepreneurship within cooperatives. Providing mentorship, training, and financial support will enable women to start and grow their enterprises.
12. **Recognize and Reward Unpaid Care Work :** Acknowledge and reward unpaid care work to promote women's economic participation. By reducing the burden of household responsibilities, women can actively engage in cooperative activities.

Technical Session 7: Importance of Cooperative Credit System in the Indian Economy

Chair : Shri Vijay Kumar, Special Secretary & CRCS, Ministry of Cooperation, Govt. of India

Keynote speaker : Mr. Satish Marathe, Director, RBI

Speakers:

1. Shri Jyotindra M. Mehta, Chairman, National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit, New Delhi
2. Shri B. Subrahmanyam, Managing Director, National Federation of State Co-operative Banks Ltd. (NAFSCOB), Maharashtra
3. Shri K. K. Ravindran, Managing Director, National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation, Navi Mumbai
4. Ms. Jayshree, Advocate & Attorney Cyber Security Expert, Pune
5. Dr. Sukesh Zamwar, Managing Director, Buldhana Urban Coop. Credit Society, Buldhana, Maharashtra

तकनीकी - सत्र 7 "भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली का महत्व" का एक दृश्य।

श्री सुभाष गुप्ता, सलाहकार, एनसीयूआई, तकनीकी सत्र-7 का संचालन करते हुए।

17वीं भारतीय सहकारी सम्मेलन के ज्ञानवर्धक तकनीकी सत्र -7 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली के महत्व पर चर्चा की गई। एनसीयूआई के **सलाहकार श्री सुभाष गुप्ता** द्वारा संचालित सत्र की शुरुआत विषय के परिचय / सम्मानित पैनलिस्टों और विशेषज्ञों के परिचय के साथ हुई।

A view of Technical Session 7: Importance of Cooperative Credit System in the Indian Economy

The enlightening Technical Session 7 of the 17th Indian Cooperative Congress delved into the significance of the Cooperative Credit System in the Indian economy. Moderated by Mr. Subhash Gupta, Adviser at NCUI, the session commenced with an introduction to the theme and the introduction of the esteemed panelists and experts.

Shri Subhash Gupta, Adviser, NCUI -Moderator of the Technical Session

श्री विजय कुमार, विशेष सचिव एवं केंद्रीय पंजीयक सहकारी समिति (सीआरसीएस), सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली के महत्व के तकनीकी सत्र-7 में बोलते हुए।

पैनल अध्यक्ष, श्री विजय कुमार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के समय के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। मंत्रालय के समक्ष चुनौतियों में देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की मैपिंग की कमी भी शामिल थी। इसे संबोधित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के गठन की शुरुआत की जहां छह लाख समितियों का डेटा पहले से ही संग्रहीत है।

सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास में मंत्रालय ने विशेष रूप से पैक्स को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया। पैक्स को सशक्त बनाने के लिए कई पहलों पर प्रकाश डाला गया जिसमें जनवरी 2024 तक 2500 करोड़ की परियोजना के साथ 63000 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पैक्स को बहुउद्देशीय संस्थाएं बनाकर उनकी आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसमें पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण सुविधाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां और बहुत कुछ बनाना शामिल था।

मंत्रालय ने पैक्स को पेट्रोल आउटलेट, उर्वरक वितरण केंद्र और अन्य उद्यम खोलने के लिए अधिकृत करके उनका विस्तार करने की भी वकालत की। सहकारी पहलों को और अधिक समर्थन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ सहयोगात्मक प्रयास स्थापित किए गए। सहकारी समितियों के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन को भी प्रोत्साहित किया गया।

मंत्रालय ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मजबूत करने के लिए जमा होल्डिंग्स में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की। यह सुनिश्चित करने के लिए शाखा लाइसेंसिंग की सुविधा को आवश्यक माना गया कि यूसीबी की व्यापक पहुंच हो और खासकर उन जिलों में जहां वे वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

इसके अलावा सत्र में सहकारी ऋण समितियों (सीसीएस) को मजबूत करने के लिए उचित उपाय करने के महत्व पर जोर दिया गया जिससे भारत में सहकारी ऋण प्रणाली को मजबूत किया जा सके।

श्री सतीश मराठे, निदेशक, आर.बी.आई. तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

इस तकनीकी सत्र-7 में श्री सतीश मराठे, निदेशक, आर.बी.आई. ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली के महत्व पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने सहकारी ऋण प्रणाली को मजबूत करने और देश की आर्थिक वृद्धि पर इसके प्रभाव के लिए मूल्यवान विचार और प्रासंगिक सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

उन्होने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत का क्रेडिट-जीडीपी अनुपात 55-60% है जो दक्षिण कोरिया (165%), वियतनाम (148%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (140%) जैसे अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने भारत में संस्थागत ऋण को धीरे-धीरे बढ़ाने और इसे देश की जीडीपी के साथ समरूप करने के लिए एक बड़े नीतिगत बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया।

सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण की दक्षता और लागत प्रभावशीलता को पहचानते हुए श्री मराठे ने सहकारी चैनलों के माध्यम से ऋण वितरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) द्वारा डेटा रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर दिया और उन्हें शीर्ष संस्थानों को अपने वित्तीय विवरण सकारात्मक रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया।

श्री मराठे ने ऋण तक व्यापक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक पैक्स बनाने की सिफारिश की। उन्होंने ग्रामीण ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने में केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के महत्व पर जोर दिया और उनके संचालन में देरी या कमी करने के प्रति आगाह किया क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत ऋण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्री मराठे ने किसानों के बीच निजी ऋण को संस्थागत ऋण से बदलने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि वर्तमान में केवल 20% किसानों के पास ही इसकी पहुंच है। उन्होंने सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की गैर-कृषि गतिविधियों के वित्तपोषण की वकालत की और श्रेणीबद्ध नियमों के साथ एनबीएफसी के समान पैरा-बैंकिंग इकाइयों की स्थापना का सुझाव दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों दोनों के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह की कमी पर प्रकाश डालते हुए श्री मराठे ने दो संभावित समाधान प्रस्तावित किए जैसे कि बैंकों को स्वतंत्र रूप से स्वयं का पोषण करना चाहिए या सहकारी समितियों के लिए यूनिवर्सल बैंकों का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को और अधिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे सहकारी वित्तीय संस्थानों को पुरजोर तरीके से मदद की जा सकें।

Shri Vijay Kumar, Special Secretary & Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS), Ministry of Cooperation, GoI speaking in the technical session of Importance of Cooperative Credit System in the Indian Economy

The Chairman of the Panel, Shri **Vijay Kumar, Special Secretary & Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS), Ministry of Cooperation, GoI,** shed light on the challenges faced by the Ministry of Cooperation at its inception. The challenges included the lack of proper mapping of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) across the country. To address this, the Ministry initiated the formation of the National Cooperative Database, where data of 6 lakh societies are already stored.

In an effort to strengthen the cooperative sector, the Ministry focused on supporting its pillars, particularly PACS. Several initiatives were highlighted to empower PACS, including computerization of 63,000 PACS with a project worth '2500 crore' by January 2024. Additionally, the Ministry aimed to enhance the income of PACS by making them multipurpose entities. This involved forming decentralized grain storage facilities, custom hiring centers, processing units, and more at the PACS level.

The Ministry also advocated for expanding the horizons of PACS by authorizing them to open petrol outlets, fertilizer distribution centers, and other ventures. Collaborative efforts with the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and Common Service Centres (CSC) were established to further support cooperative initiatives. The formation of Farmer Producer Organizations (FPOs) through cooperatives was also encouraged.

To strengthen Urban Cooperative Banks (UCBs), the Ministry sought to increase their share in deposit holdings. Facilitating branch licensing was identified as essential to ensure that UCBs have a wider reach, especially in districts where they are currently absent.

Furthermore, the session emphasized the importance of taking appropriate measures to strengthen Cooperative Credit Societies (CCSs), thereby reinforcing the cooperative credit system in India.

Mr. Satish Marathe, Director of RBI speaking in the technical session.

The highly informative Technical Session 7 on the Importance of Cooperative Credit System in the Indian Economy commenced with a thought-provoking Keynote Address by Mr. Satish Marathe, Director of RBI. Mr. Marathe presented valuable insights and made pertinent recommendations to strengthen the cooperative credit system and its impact on India's economic growth.

Mr. Marathe highlighted that India's Credit-GDP ratio stands at 55-60%, which is significantly lower compared to other countries like South Korea (165%), Vietnam (148%), and the USA (140%). He emphasized the need for a major policy change to gradually increase institutional credit in India and align it with the country's GDP.

Recognizing the efficiency and cost-effectiveness of delivering credit through cooperatives, Mr. Marathe called for promoting the delivery of credit through cooperative channels. He emphasized the importance of data reporting by Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and suggested providing training and facilitation to enable them to report their financial statements positively to apex institutions.

To ensure widespread access to credit, Mr. Marathe recommended having at least one PACS in each gram panchayat. He emphasized the significance of Central District Cooperative Banks (DCCBs) in improving rural credit flow and cautioned against delayering or detiering their operations, as they play a crucial role in decentralized lending in rural areas.

Mr. Marathe stressed the need to replace private lending among farmers with institutional credit, as only 20% of farmers currently have access to it. He advocated for funding non-farm activities of rural communities through cooperative banks, suggesting the establishment of Para-Banking Units akin to NBFCs with graded regulations.

Highlighting the lack of long-term capital inflow in rural areas for both farm and non-farm activities, Mr. Marathe proposed two potential solutions: banks should independently nurture themselves or the creation of Universal Banks for Cooperatives. He also emphasized the need to strengthen the National Cooperative Development Corporation (NCDC) to support cooperative financial institutions effectively.

Mr. Marathe drew attention to a crucial Banking Regulatory Act loophole that prohibits urban banks from financing cooperatives, which he suggested should be removed to enhance cooperative credit access.

In conclusion, Mr. Marathe highlighted the importance of researching and creating a policy for Cooperative Financial Institutions to further strengthen the cooperative credit system and its role in driving India's economic growth. His keynote address sparked meaningful discussions during the Technical Session, leading to an enriched understanding of the critical role of the cooperative credit system in the Indian economy.

This followed by the valuable insights shared by distinguished speakers who shed light on critical aspects of the cooperative credit system and its impact on the nation's economy.

श्री मराठे ने एक महत्वपूर्ण बैंकिंग नियामक अधिनियम की खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जो शहरी बैंकों को सहकारी समितियों को वित्तपोषण करने से रोकता है उन्होंने सुझाव दिया कि सहकारी ऋण की पहुंच बढ़ाने के लिए इनकी खामियों को दूर किया जाना अति आवश्यक है।

अंत में श्री मराठे ने सहकारी ऋण प्रणाली को और मजबूत करने तथा भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका के लिए सहकारी वित्तीय संस्थानों पर शोध करने और एक नीति बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके मुख्य भाषण से तकनीकी सत्र के दौरान सार्थक चर्चा हुई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका की समृद्ध समझ पैदा हुई।

इसके बाद अन्य वक्ताओं ने बहुमूल्य विचार साझा किए जिन्होंने सहकारी ऋण प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं और देश की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला।

श्री ज्योतिंद्र एम. मेहता, अध्यक्ष, नैफकब तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

श्री ज्योतिंद्र एम. मेहता ने समाज में उपस्थित वर्ग असमानताओं को कम करने में सहकारी समितियों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त दायित्व समूहों के पंजीकरण और उन्हें सहकारी समितियों में शामिल करने पर बल दिया, उन्होंने व्यावहारिक समूहों के निर्माण के माध्यम से सहकारी संघों और संसाधनों के एकत्रितकरण को प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश की। इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने बुनियादी ढांचे और व्यापार विविधीकरण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और वित्त पोषण करने का सुझाव दिया।

श्री बी. सुब्रह्मण्यम, प्रबंध निदेशक, नैफसकोब तकनीकी सत्र-7 में बोलते हुए।

श्री बी. सुब्रमण्यम, प्रबंध निदेशक, नैफसकोब ने सहकारी समितियों और सहकारी ऋणों के विकास को प्रतिबंधित करने वाले कारकों पर अपने विचार व्यक्त किए। इनमें अग्रिम और जमा पर प्रशासित ब्याज दर संरचनाएं एक उपयुक्त राष्ट्रीय सहकारी नीति का अभाव, पुनर्वित्त पर ब्याज दर नीतियों में बार-बार बदलाव, विलंबित और अपर्याप्त पुनर्पूंजीकरण समर्थन, विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुप्रयोग इत्यादि शामिल है। उन्होंने व्यवसाय प्रबंधन, धन प्रबंधन, वसूली प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित क्रेडिट सहकारी प्रणालियों में प्रमुख मुद्दों की पहचान की। उनकी सिफारिशें सहकारी समितियों को स्वायत्त और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए "3 आर" पुर्नस्थापना, पुर्नपूंजीकरण और पुर्नग्रहण रणनीतियों पर केंद्रित थीं। दोनों क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने कृषि प्रक्रियाओं और सहकारी समितियों इन्हें आपस में जोड़ने पर भी जोर दिया।

श्री के.के.रवींद्रन, प्रबंध निदेशक, NAFCARD तकनीकी सत्र-7 में।

श्री के.के. रवींद्रन, प्रबंध निदेशक, NAFCARD ने दीर्घकालिक ऋण तक सहकारी समितियों की सीमित पहुंच पर प्रकाश डाला और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कम ब्याज दर पर इसे बढ़ावा देने की सिफारिश की। उन्होंने कृषि में निवेश ऋण को प्रसारित करने के लिए समर्पित संरचना के रूप में दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीसीएआरडीबी और एससीएआरडीबी के पुनर्निर्देशन का भी आह्वान किया। उनकी स्पष्ट भूमिका निर्धारण के साथ कृषि और ग्रामीण ऋण में संस्थानों की सापेक्ष हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। एआरडीबी को बैंकों में बदलने के लिए लाइसेंस देने की संभावना का सुझाव दिया गया था ताकि उनकी जमा राशि, विनियमन और दीर्घकालिक ऋण के प्रति नीतिगत ध्यान में सुधार किया जा सके।

Shri Jyotindra M. Mehta, Chairman NAFCUB speaking in the technical session

Shri Jyotindra M. Mehta, Chairman NAFCUB, emphasized the role of cooperatives in reducing class disparities in society. He advocated for the registration and inclusion of Self-Help Groups (SHGs) and Joint Liability Groups with cooperatives. He further recommended the encouragement of cooperative federations and resource pooling through the creation of workable conglomerates. To strengthen the sector, he suggested facilitating and funding infrastructure and business diversification activities.

Shri B. Subrahmanyam, Managing Director, NAFSCOB in the technical session

Shri B. Subrahmanyam, Managing Director, NAFSCOB, addressed the factors restricting the growth of cooperatives and cooperative credits. These included administered interest rate structures on advances and deposits, absence of an appropriate National Cooperative Policy, frequent changes in interest rate policies on refinance, delayed and inadequate recapitalization support, application of prudential norms, and the absence of a level playing field. He identified key issues in credit cooperative systems related to business management, funds management, recovery management, and human resources management. His recommendations focused on the "3 R" strategies - Restore, Recapitalize, and Recapture - to make cooperatives autonomous and competitive. Interlinking agricultural processes and cooperatives to revitalize both sectors was also emphasized.

Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD, highlighted the limited access of cooperatives to long-term credit and recommended promoting it at a lower interest rate to strengthen the sector. He emphasized the need to revive the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS) as the dedicated structure for channelizing investment credit into agriculture. He also called for reorientation of PCARDBs and SCARDBs meant for catering to long-term credit needs of the rural sector. The relative share of institutions in agricultural and rural credit should increase with clearer role demarcations. The possibility of licensing ARDBs to transform into banks was suggested to improve their deposits, regulation, and policy attention towards long-term credit.

सुश्री जयश्री, एडवोकेट एवं एटॉर्नी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, पुणे तकनीकी सत्र में बोलते हुए।

सुश्री जयश्री, एडवोकेट एवं एटॉर्नी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने सहकारी बैंकिंग में साइबर खतरों और अपराधों को रोकने पर आवश्यक जानकारी प्रदान की। उन्होंने साइबर हमलों से बचाव के लिए पहचान, रोकथाम और सुरक्षा के तीन-चरणीय दृष्टिकोण पर जोर दिया। साइबर धोखाधड़ी बीमा और हमलों का पता लगाने के लिए कुशल मानव संसाधनों सहित परिचालन सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया। फ़ायरवॉल, पासवर्ड सुरक्षा, एसआईईएम और लोग प्रबंधन और एन्क्रिप्शन जैसे पंद्रह सुरक्षा नियंत्रणों का उल्लेख किया गया था। उनकी सिफारिशों में आरबीआई की साइबर अनुपालन सुरक्षा का पालन करना, नियमित सुरक्षा मूल्यांकन ऑडिट करना और कर्मचारियों को नियमित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। संभावित लीक या खतरों को रोकने के लिए तीसरे पक्ष के डेटा से निपटने के दौरान उचित आउटसोर्सिंग समझौतों का भी सुझाव दिया गया।

अंत में इस तकनीकी सत्र-7 ने भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली के महत्व की व्यापक समझ को सुविधाजनक बनाया। वक्ताओं की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशों ने सहकारी समितियों को मजबूत करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सहकारी ऋण क्षेत्र में साइबर खतरों से की जाने वाली सुरक्षा पर प्रकाश डाला।

तकनीकी सत्र 7- मुख्य सिफ़ारिशें:-

1. **समावेशिता को बढ़ावा देनाः** क्रेडिट प्रणाली में हाशिये पर रह रहे वर्गों की व्यापक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त दायित्व समूहों को सहकारी समितियों के साथ एकीकृत करना चाहिए। किसानों की ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए संस्थागत ऋण को निजी ऋण की जगह लेनी चाहिए।
2. **सहकारी संघ और संसाधन पूलिंगः** सहकारी संघों के गठन को प्रोत्साहित करना और सहकारी समितियों की सामूहिक शक्ति को मजबूत करने और उनकी वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए संसाधन पूलिंग की सुविधा प्रदान करना। ऐसा करने पर सहकारी बैंकों के माध्यम से गैर-कृषि गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के समान पैरा-बैंकिंग इकाइयां भी स्थापित की जा सकती हैं। इन इकाइयों का उचित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए श्रेणीबद्ध नियम लागू करना।
3. **बुनियादी ढाँचा और व्यवसाय विविधीकरणः** सतत विकास और बढ़े हुए प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढाँचे के विकास और व्यवसाय विविधीकरण गतिविधियों का समर्थन और वित्तपोषण करना।
4. **प्रमुख नीतिगत परिवर्तनः** भारत में संस्थागत ऋण बढ़ाने के लिए नीतिगत परिवर्तन लागू करना जिसका लक्ष्य उच्च क्रेडिट-जीडीपी अनुपात प्राप्त करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
5. **दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) को पुनर्जीवित करनाः** ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास का समर्थन करते हुए, कृषि में निवेश ऋण के प्रभावी ढंग से चैनलीकरण की सुविधा के लिए एलटीसीसीएस को मजबूत करना।
6. **स्पष्ट भूमिका सीमांकनः** कृषि और ग्रामीण ऋण में संस्थानों की सापेक्ष हिस्सेदारी बढ़ाना और सहकारी ऋण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए स्पष्ट भूमिका सीमांकन प्रदान करना।
7. **वित्तीय समावेशनः** विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण तक पहुंच को सक्षम करके वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना।
8. **कृषि प्रक्रियाओं और सहकारी समितियों को आपस में जोडना:** दोनों क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने और बहुउद्देशीय/बहु-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए कृषि प्रक्रियाओं और सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
9. **साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ानाः** सहकारी बैंकिंग प्रणालियों के लिए साइबर खतरों का पता लगाने, रोकथाम और सुरक्षा सहित मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना।
10. **नियमित सुरक्षा मूल्यांकन ऑडिटः** कमजोरियों की पहचान करने और साइबर सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए नियमित सुरक्षा मूल्यांकन ऑडिट आयोजित करें।
11. **आउटसोर्सिंग समझौतेः** संभावित लीक या साइबर अपराधों को रोकने के लिए तीसरे पक्ष के डेटा से निपटने के दौरान व्यापक आउटसोर्सिंग समझौते विकसित करें।

Adv. Jayshree, Cyber Security Expert, provided essential insights on preventing cyber threats and crimes in cooperative banking. She emphasized the three-step approach of detection, prevention, and protection to safeguard against cyber-attacks. Operational security, including cyber fraud insurance and skilled human resources to detect attacks, were highlighted. Fifteen security controls, such as firewall, password protection, SIEM and Log management, and encryption, were mentioned. Her recommendations included adhering to RBI's Cyber Compliance Protection, conducting regular security assessment audits, and providing regular cybersecurity training to employees. Proper outsourcing agreements were also suggested when dealing with third-party data to prevent potential leaks or threats.

In conclusion, the Technical Session 7 facilitated a comprehensive understanding of the importance of the cooperative credit system in India's economy. The speakers' valuable insights and recommendations highlighted the path towards strengthening cooperatives, promoting inclusive growth, and safeguarding against cyber threats in the cooperative credit sector.

Ms. Jayshree, Advocate & Attorney Cyber Security Expert, Pune speaking in the technical session

Technical Session 7 - Key Recommendations:

1. **Promote Inclusivity :** Integrate Self-Help Groups (SHGs) and Joint Liability Groups with cooperatives to ensure broader participation and representation of marginalized sections in the credit system. Institutional credit should replace private lending among farmers to expand their access to credit.
2. **Cooperative Federations and Resource Pooling :** Encourage the formation of cooperative federations and facilitate resource pooling to strengthen the collective power of cooperatives and enhance their financial viability. In doing so the Para-Banking Units may also be established similar to Non-Banking Financial Companies (NBFCs) to fund non-farm activities through cooperative banks. Implement graded regulations for these units to ensure their proper functioning.
3. **Infrastructure and Business Diversification :** Support and fund infrastructure development and business diversification activities within the cooperative sector to ensure sustainable growth and increased impact.
4. **Major Policy Changes :** Implement policy changes to increase institutional credit in India, aiming to achieve a higher Credit-GDP ratio and foster economic growth.
5. **Revive Long-Term Cooperative Credit Structure (LTCCS):** Strengthen the LTCCS to facilitate the channelization of investment credit into agriculture effectively, supporting the growth of rural cooperatives.
6. **Clearer Role Demarcations :** Increase the relative share of institutions in agricultural and rural credit and provide clearer role demarcations to enhance the cooperative credit system's efficiency.
7. **Financial Inclusion :** Ensure financial inclusion by enabling access to long-term credit at lower interest rates, especially for farmers and rural entrepreneurs.
8. **Interlinking Agricultural Processes and Cooperatives :** Foster cooperation between agricultural processes and cooperatives to revitalize both sectors and establish multipurpose/multi-service centers.
9. **Enhance Cybersecurity Measures :** Implement robust cybersecurity measures, including detection, prevention, and protection against cyber threats, for cooperative banking systems.
10. **Regular Security Assessment Audits :** Conduct regular security assessment audits to identify vulnerabilities and improve cybersecurity practices.
11. **Outsourcing Agreements :** Develop comprehensive outsourcing agreements when dealing with third-party data to prevent potential leaks or cybercrimes.

समापन समारोह

समापन समारोह के अवसर पर मंच पर मुख्य अतिथि और अन्य सम्मानित अतिथि।

दिनांक 01 जुलाई, 2023 को शुरू हुए 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का समापन समारोह दिनांक 2 जुलाई 2023 को शाम 4 बजे आयोजित किया गया था। देश भर के प्रतिष्ठित अतिथि, सहकारी नेता और विशेषज्ञ इसमें शामिल जिनकी संख्या लगभग 1500 थी।

श्री ओम बिड़ला, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा इस समारोह में मुख्य अतिथि एवं श्री पुरुषोत्तम रूपाला, माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, और डेयरी मंत्री विशेष अतिथि और अन्य सम्मानित अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, भा०रा०सह० संघ एवं इफको ने इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण दिया।

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के दौरान कुल 7 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिसमें सहकारी ऋण प्रणाली, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के महत्व के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। महासम्मेलन में सभी वक्ताओं, विशेषज्ञों और पैनलिस्टों ने सहकारिता के चहुँमुखी विकास हेतु बहुमूल्य अंतर्दृष्टि, नवीनतम रणनीतियाँ और नई खोजो से मंच को सुशोभित किया जो निस्संदेह भारत के सहकारी आंदोलन को समृद्धि की ओर ले जाएंगे।

श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय राज्य सहकारिता मंत्री, डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत, डॉ. बिजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नैफेड, डॉ. सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (बिस्कोमान), श्री विजय कुमार, विशेष सचिव, सहकारिता मंत्रालय को कार्यक्रम के दौरान उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया एवं उनका आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने सभी वक्ताओं, विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों, नेताओं, सदस्यों और प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य योगदान और सक्रिय भागीदारी के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

Valedictory Function

On the occasion of Valedictory Function Chief Guest and other Guests of Honor on the dais.

The Valedictory function of the 17th Indian Cooperative Congress was held on 2nd July 2023 at 4 PM to conclude the enriching and insightful event that commenced on 1st July 2023. The esteemed gathering included distinguished guests, cooperatives leaders, experts, and enthusiasts from across the country, who came together to deliberate on the theme "Amrit Kaal: Prosperity through Cooperation for a Vibrant India".

The function was graced by the presence of the Chief Guest, Shri Om Birla, Hon'ble Speaker, Lok Sabha, who added immense significance to the event. Shri Purushottam Rupala, Hon'ble Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying, was the Guest of Honour, and their esteemed participation elevated the occasion.

In the course of the 17th Indian Cooperative Congress, a total of 7 technical sessions were organized, covering various aspects of cooperative credit systems, gender equality, social inclusion, and the importance of cooperatives in the Indian economy. The speakers, experts, and panelists provided valuable insights, strategies, and innovations that will undoubtedly propel India's cooperative movement towards prosperity.

Shri Dileep Sanghani, President, NCUI expressed heartfelt gratitude to the Hon'ble Prime Minister of India for gracing the inaugural session of the congress and the Hon'ble Union Cabinet, Home and Cooperation Minister, the Hon'ble Minister of State (Cooperation), Dr. Chandrapal Singh Yadav, Chairman of International Cooperative Alliance – Asia Pacific, and Dr. Bijender Singh, Chairman of NAFED; Dr. Sunil Kumar Singh, Chairman, Bihar State Cooperative Marketing Union Ltd. (BISCOMAUN); Shri. Vijay Kumar, Special Secretary, Ministry of Cooperation for their esteemed presence during the event. In addition, he also extended his heartfelt gratitude to all the speakers, experts, delegates, leaders, members and participants for their valuable contributions and active engagement.

Shri Dileep Sanghani, President, NCUI delivered his presidential speech on the occasion of 17th Indian Cooperative Congress

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत एवं कृभको इस अवसर पर बोलते हुए।

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत एवं अध्यक्ष कृभको ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री के सामूहिक प्रयास के आह्वान की गूंज पूरे सहकारी क्षेत्र में हुई, जिससे एकता और विकास को प्रेरणा मिली। उन्होंने कम्प्यूटरीकरण और नीति निर्माण जैसे रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करने में भारत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करके और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया।

इस दृढ़ विश्वास के साथ कि सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं, उन्होंने उसे मजबूत भारत के लिए उत्प्रेरक के रूप में पेश किया। उन्होंने इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला और सहकारी सदस्यों के सामने आने वाली चुनौतियों को सुलझाने और व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए और दो दिवसीय आयोजन की शानदार सफलता का श्रेय सभी हितधारकों और उनकी भागीदारी को दिया।

डॉ. यादव ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहकारी क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की जो वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफार्मों के निर्माण के माध्यम से प्रकट हुआ। उन्होंने सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण समुदायों को मिलने वाले वास्तविक लाभों की गहराई से पड़ताल की और भारत की समृद्धि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। आगे उन्होने कहा कि "सहकार से समृद्धि" की प्रामाणिकता भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन के माध्यम से गूंज उठी हैं।

सहकारी समितियों की व्यापक पहुंच पर प्रकाश डालते हुए डॉ. यादव ने बताया कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही उनके साथ जुडा हुआ है। दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने सहकारी आंदोलन में तेजी से वृद्धि की कल्पना करते हुए इसमें अधिक से अधिक भागीदारी का आग्रह किया। अंत में उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से सहकारी समितियों के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया जो एक मौलिक सिद्धांत है जिसके बारे में उनका मानना है कि यह भारत की आर्थिक प्रगति को रेखांकित करेगा। डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव के संबोधन में एकता, विकास और सशक्तिकरण की भावना समाहित थी जो भारत के सहकारी क्षेत्र के केंद्र में है।

डॉ. बिजेंद्र सिंह, अध्यक्ष, नेफेड इस अवसर पर बोलते हुए।

डॉ. बिजेंद्र सिंह, अध्यक्ष, नेफेड ने सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान सम्मेलन की अपार सफलता हेतु प्रशंसा भरा भाषण दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) को सशक्तिकरण और उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष भा०रा०सह०संघ की प्रशंसा करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की।

डॉ. बिजेंद्र सिंह ने सफल और ज्ञानवर्धक दो दिवसीय महासम्मेलन को आयोजित करने के लिए भा०रा० सह०संघ के पूरे स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने इस सम्मेलन के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने में उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों की भी प्रशंसा की जिसने कई सहकारी हितधारकों को एक छत के नीचे एक साथ ला दिया।

डॉ. सिंह का संबोधन उस सहयोगात्मक भावना के प्रति एक सम्मान था जो भारत में सहकारी आंदोलन को रेखांकित करती है। उन्होंने इस भावना को बढ़ावा देने में भा०रा०सह०संघ की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और सहकारी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके अटूट समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया।

Dr. Chandrapal Singh Yadav, President, International Cooperative Alliance – Asia Pacific and Chairman, KRIBHCO speaking on the occasion

Dr. Chandrapal Singh Yadav, President of International Cooperative Alliance – Asia Pacific and Chairman, KRIBHCO in his address, recounted how the Hon'ble Prime Minister's call for collective effort resonated across the cooperative sector, inspiring unity and growth. He emphasized the pivotal role of the Indian government in strengthening primary cooperative societies through strategic decisions like computerization and policy formulation. Dr. Yadav underscored the transformative impact of cooperatives, particularly in rural areas, by reducing dependence on external resources and fostering self-sufficiency.

With a firm conviction that cooperatives bolster the rural economy, Dr. Yadav projected them as catalysts for a stronger India. He highlighted the core purpose of the 17th Indian Cooperative Congress - an endeavor to unravel challenges faced by cooperative members and devise pragmatic solutions. Expressing gratitude, he credited the resounding success of the two-day event to the enthusiastic participation of all stakeholders.

Dr. Yadav commended the cooperative sector's efforts in embracing technology, manifested through the creation of websites and digital platforms. He delved into the tangible benefits that cooperatives bring to rural communities and acknowledged their pivotal role in India's prosperity. The authenticity of "Sahakarita se Samruddhi" echoed through the cooperative movement, transcending geographical boundaries, especially in rural areas.

Highlighting the immense outreach of cooperatives, Dr. Yadav revealed that a significant quarter of the country's population is already associated with them. With a forward-looking approach, he urged greater participation in the cooperative movement, envisioning its exponential growth. In conclusion, he urged the audience to nurture cooperation within cooperatives, a fundamental tenet that he believed would underpin India's economic progress. Dr. Chandrapal Singh Yadav's address encapsulated the spirit of unity, growth, and empowerment that lies at the heart of India's cooperative sector.

Dr. Bijender Singh, Chairman of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) speaking on the occasion

Dr. Bijender Singh, Chairman, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), delivered a commendation-filled address during the valedictory function of the 17th Indian Cooperative Congress. He commenced by extending his accolades to Mr. Dileep Sanghani, acknowledging his contributions in elevating the National Cooperative Union of India (NCUI) to new heights of empowerment and excellence.

With a sense of admiration, Dr. Singh congratulated the entire staff of NCUI for orchestrating a successful and enlightening two-day event. He recognized their dedication, commitment, and tireless efforts in ensuring the seamless conduct of the congress, which had brought together numerous cooperative stakeholders under one roof.

Dr. Singh's address was a tribute to the collaborative spirit that underpins the cooperative movement in India. He emphasized the pivotal role that NCUI plays in fostering this spirit, extending his gratitude for their unwavering dedication to advancing the cooperative cause. In doing so, he encapsulated the sense of unity, empowerment, and shared purpose that the congress aimed to promote.

श्री परषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री समापन समारोह के अवसर पर प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए।

माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी ने इस सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान सम्मानित अतिथि के रूप में एक व्यापक और व्यावहारिक भाषण दिया। उनके भाषण ने भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में सहकारी समितियों के गहन महत्व और उनके बहुमुखी योगदान को रेखांकित किया।

श्री ओम बिरला की सराहना करते हुए श्री रूपाला ने वैश्विक सहकारी परिदृश्य के बारें में गहराई से बताया और अमेरिका जैसे देशों में सहकारी आंदोलन की प्रभावशाली उपलब्धियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका संबोधन अमूल और इफको जैसी प्रतिष्ठित भारतीय सहकारी समितियों के उदाहरणों से गूंज उठा जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास और परिवर्तन को प्रेरित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण के अनुकूल विकल्प, नैनो-यूरिया के उत्पादन में भारत की अग्रणी उपलब्धि का श्रेय सहकारी क्षेत्र के नवाचार की निरंतर खोज को दिया। उन्होंने नैनो-यूरिया की लागत को कम करने और किसानों को रियायती दरों पर इसे प्राप्त करने में सक्षम बनाने में सरकार के समर्थन की सराहना की। उन्होंने सहकारी सदस्यों को इस प्रगति का आधार बताया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी सामूहिक ताकत सहकारिता को आवश्यक शक्ति प्रदान करती है।

श्री रूपाला जी के भाषण में सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर समर्पित और निस्वार्थ सेवा का आह्वान शामिल था। उन्होंने सदस्यों से राष्ट्रीय हितों को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखते हुए अपने प्रयासों को राष्ट्र की भलाई के साथ जोड़ने का आग्रह किया। उनके द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण मुद्दा सहकारी समितियों के अपने पारंपरिक बचत-केंद्रित लोकाचार से भटकने से संबंधित था। उन्होंने गुजरात में बाल-गोपाल बैंक का उल्लेखनीय उदाहरण दिया जिसने 8 से 18 आयु वर्ग के युवा सदस्यों की क्षमता का दोहन किया और एक राष्ट्रव्यापी सहयोगी पहल की कल्पना की जिसमें सहकारी समितियां भविष्य के वित्तीय प्रयासों के लिए संसाधनों को एकत्रित करती हैं।

श्री रूपाला का संबोधन एक प्रेरणादायक नोट पर समाप्त हुआ और उन्होंने सहकारी समितियों से महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करने का आग्रह किया। उनके शब्द नवाचार, एकता को बढ़ावा देने और भारत के समग्र विकास और समृद्धि लिए सहकारी सिद्धांतों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता से भरे थे।

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन में शामिल विशिष्ट प्रतिभागियों का एक दृश्य।

Shri Purushottam Rupala, Hon'ble Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, addressing the delegates on the occasion of Valedictory ceremony.

Shri Purushottam Rupala, the Hon'ble Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, delivered a comprehensive and insightful address as the Guest of Honour during the valedictory function of the 17th Indian Cooperative Congress. His speech underscored the profound significance of cooperatives and their multifaceted contributions to India's socio-economic landscape.

Commencing with his admiration for Shri Om Birla's commendable dedication, Shri Rupala delved into the global cooperative panorama, drawing attention to the cooperative movement's impressive accomplishments in countries like America. His address resonated with examples of eminent Indian cooperatives such as Amul and IFFCO, reflecting the substantial role they play in catalyzing growth and transformation across sectors.

The Hon'ble Union Minister attributed India's pioneering achievement in producing nano-urea, an eco-friendly alternative, to the cooperative sector's relentless pursuit of innovation. He lauded the government's support in reducing the cost of nano-urea, enabling farmers to access it at subsidized rates. Shri Rupala highlighted the cooperative members as the bedrock of this progress, emphasizing that their collective strength fuels the cooperative engine.

Shri Rupala's speech encapsulated a call for dedicated and selfless service within the cooperative ecosystem. He implored members to align their efforts with the betterment of the nation, placing national interests above individual gains. An illuminating point raised by him pertained to cooperatives straying from their traditional savings-centric ethos. He cited the remarkable example of Bal-Gopal bank in Gujarat, which harnessed the potential of young members aged 8-18, envisioning a nationwide collaborative initiative wherein cooperatives pool resources for future financial endeavors.

Shri Rupala's address concluded on an inspiring note, urging cooperatives to establish ambitious goals and ardently strive to achieve them. His words resonated with a collective commitment to foster innovation, unity, and a renewed focus on cooperative principles for India's holistic growth and prosperity.

A view of distinguished participants joined the 17th Indian Cooperative Congress

डॉ. सुधीर महाजन, मुख्य कार्यकारी, भा०रा०सह० संघ 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के अवसर पर बोलते हुए।

डॉ. सुधीर महाजन, मुख्य कार्यकारी, भा०रा०सह०संघ ने दो दिवसीय कार्यक्रम का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने सम्मेलन को सफल बनाने में उनके सामूहिक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देकर शुरुआत की।

डॉ. महाजन ने अपने संबोधन में भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में सहकारी समितियों के सर्वोपरि महत्व और व्यापक लाभों को रेखांकित किया। सम्मेलन ने विकास, समावेशिता और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की बहुमुखी क्षमता का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। आगे उन्होंने कहा कि सभी वक्ताओं, विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने सहकारी क्षेत्र के भीतर प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श और रणनीति बनाने के लिए सफल बैठकें की।

इस कार्यक्रम में सहकारी शासन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और जमीनी स्तर की पहल जैसे विविध विषयों पर ढेर सारी चर्चाएं और अंतर्दृष्टियां शामिल हुई। विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए अपने विचार साझा किए।

डॉ. महाजन ने सेवाओं और कल्याण-उन्मुख संस्थाओं के रूप में इसकी स्थापना से लेकर सामाजिक- आर्थिक संबल के रूप में इसकी वर्तमान भूमिका तक सहकारी आंदोलन की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डाला। सम्मेलन ने कृषि, डेयरी और वित्त जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए सहकारी समितियों की उपलब्धियों का जश्न मनाया जिससे भारत की जीडीपी को बढ़ावा मिला और लाखों लोगों की आजीविका में सराहनीय वृद्धि हुई।

इसके अलावा उन्होंने सहकार के सार को दोहराया और सभी प्रतिभागियों से सहकारी आंदोलन और बड़े पैमाने पर राष्ट्र की बेहतरी के लिए साझा ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने और लागू करने का आग्रह किया। डॉ. महाजन ने सभी प्रतिनिधियों को सहकारी उन्नति की दिशा में अपने समर्पित प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया और कहा कि इसका परिणाम एक अधिक जीवंत और समृद्ध भारत होगा।

श्री ओम बिरला, लोकसभा, अध्यक्ष ने दो दिवसीय 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के समापन समारोह के दौरान अपने ज्ञानवर्धक समापन भाषण से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। मंच पर सम्मानित सदस्यों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने दो दिवसीय कार्यक्रम में हुई समृद्ध चर्चाओं पर प्रकाश डाला। श्री बिरला ने "सहकार से समृद्धि" की व्यापक दृष्टि के अनुरूप, सहकारी क्षेत्र के भीतर दक्षता और अपनी सिफारिशों/ सुझावों के साथ सम्मेलन के प्रभाव पर जोर दिया।

माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सम्मेलन के अवसर पर संबोधित करते हुए।

माननीय अध्यक्ष ने सामाजिक सुधार और विशेष रूप से वित्तीय उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण जैसे पहलुओं में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इतिहास से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने सहकारी आंदोलन के ऐतिहासिक लचीलेपन को रेखांकित करते हुए प्रतिनिधियों को प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान उभरी सामूहिक ताकत की याद दिलाई।

श्री बिरला ने सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले लाभों पर प्रकाश डाला जिसमें किसानों के लिए शून्य-ब्याज ऋण और कृषि समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य के सकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। उन्होंने सहकारी समितियों के साथ एकीकृत होने पर किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया और खासकर ग्रामीण परिवेश में जहां इनसे व्यापक लाभ मिलते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने सहकारी समितियों में निहित बचत करने की शक्ति पर जोर दिया। यह देखते हुए कि कैसे ये संस्थाएं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देती हैं और न्यूनतम या शून्य-ब्याज पर ऋण तक पहुंच प्रदान करके आजीविका में बदलाव लाती हैं। उन्होंने हरित क्रांति, श्वेत और नीली क्रांति जैसी परिवर्तनकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के पीछे सहकारी समितियों को प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया।

Dr. Sudhir Mahajan, Chief Executive, NCUI speaking on the occasion of 17th Indian Cooperative Congress

Dr. Sudhir Mahajan, Chief Executive, NCUI offered a succinct summary of the impactful two-day event, the 17th Indian Cooperative Congress. He commenced by extending heartfelt congratulations to all participants, highlighting the significance of their collective efforts in making the congress a success.

In his address, Dr. Mahajan underscored the paramount importance and wide-ranging benefits of cooperatives in shaping India's socio-economic landscape. The congress served as a forum to explore the multifaceted potential of cooperatives in fostering growth, inclusivity, and sustainable development. The speakers, experts, and participants convened to deliberate and strategize on key challenges and opportunities within the cooperative sector.

The event encapsulated a plethora of discussions and insights encompassing diverse topics such as cooperative governance, innovation, technology, and grassroots initiatives. Prominent figures from various sectors shared their wisdom, emphasizing the pivotal role of cooperatives in driving economic progress and societal welfare.

Dr. Mahajan highlighted the cooperative movement's transformative journey from its inception as services and welfare-oriented entities to its current role as socio-economic enablers. The congress celebrated the achievements of cooperatives, underlining their contributions to critical sectors like agriculture, dairy, and finance, thereby bolstering India's GDP and enhancing the livelihoods of millions.

Furthermore, he reiterated the essence of cooperation, urging participants to internalize and implement the shared knowledge and best practices for the betterment of the cooperative movement and the nation at large. Dr. Mahajan concluded with a resounding call to action, encouraging the audience to continue their dedicated efforts towards cooperative advancement, culminating in a more vibrant and prosperous India.

Shri Om Birla, Hon'ble Speaker of Lok Sabha addressing on the occasion of 17th Indian Cooperative Congress

Shri Om Birla, Hon'ble Speaker, Lok Sabha, graced the occasion with his insightful valedictory address during the valedictory function of the two days 17th ICC. Commencing with expressions of gratitude towards esteemed members on the stage, he delved into the enriching discussions that transpired over the two-day event. Shri Birla emphasized the tangible impact of the congress, with its recommendations and suggestions poised to enhance the efficiency and practices within the cooperative sector, aligning with the overarching vision of "Sahakar se Samruddhi."

The Hon'ble Speaker accentuated the significant role that cooperatives play in societal betterment, particularly in aspects like financial upliftment and women's empowerment. Drawing inspiration from the nation's history, he reminded the audience of the collective strength that emerged during times of adversity, underlining the cooperative movement's historical resilience.

Shri Birla spotlighted the unique benefits offered by cooperatives, including zero-interest loans for farmers and the positive impact of initiatives aimed at alleviating the challenges faced by the agricultural community. He elaborated on the pivotal role of Farmer Producer Organizations (FPOs) when integrated with cooperatives, especially in rural settings, where these collaborations yield amplified benefits.

श्री बिरला ने उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों से चिह्नित इस क्षेत्र की यात्रा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। उन्होंने उस दौर का जिक्र किया जब अनैतिक प्रथाओं ने सहकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था। हालाँकि उन्होंने एक अलग मंत्रालय यानी सहकार मंत्रालय की स्थापना से आए सकारात्मक बदलाव पर प्रकाश डाला जिसने नैतिक शासन और क्षेत्र की गति को फिर से बहाल किया।

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर मंच का एक दृश्य।

श्री बिरला ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्थापित करने के लिए एकता और समर्पण की वकालत की। उन्होंने पैक्स को वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य करने, निर्बाध उत्पादन, भंडारण, खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की। सहकारी समितियों से अपनी क्षमता को अधिकतम करने का आग्रह करते हुए उन्होंने एक व्यापक वित्तीय मॉडल स्थापित करने के एनसीयूआई के प्रयास की सराहना की जो आर्थिक विकास और शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाएगा।

माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सहकारी समितियों के लिए एक समृद्ध भविष्य की कल्पना करते हुए एक आशावादी नोट पर अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में सहकारी भावना को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रगान की प्रस्तुति के समय गणमान्य व्यक्तियों का एक दृश्य।

इस दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम का समापन औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों और योगदानकर्ताओं को उनकी अमूल्य अंतर्दृष्टि और भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया गया। इसके बाद सभी ने एकजुट होकर राष्ट्रगान की प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता अर्पित की।

17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन जोरदार तालियों और सभी लोगों की व्यापक सराहना के साथ संपन्न हुआ जो इसकी सफलता और सार्थक प्रभाव को रेखांकित करता है।

The Hon'ble Speaker emphasized the power of savings inherent in cooperatives, noting how these entities foster financial stability and transform livelihoods by providing access to loans with minimal or zero interest. He acknowledged cooperatives as the driving force behind the implementation of transformative schemes such as the green revolution, white and blue revolution.

Shri Birla candidly acknowledged the sector's journey, marked by both achievements and challenges. He recounted a phase where unethical practices tarnished the cooperative sector's reputation. However, he highlighted the positive turn brought about by the establishment of a separate Ministry, i.e. Ministry of Cooperation, which restored ethical governance and reignited the sector's momentum.

A view of the dais on the occasion of Valedictory Ceremony of 17th Indian Cooperative Congress

Looking ahead, Shri Birla advocated unity and dedication to establish Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in every Gram Panchayat. He envisaged PACS acting as financial hubs, facilitating seamless production, storage, procurement, and sales. Urging cooperatives to maximize their potential, he applauded NCUI's endeavor to set up a comprehensive financial model that will empower individuals through economic growth and education.

The Hon'ble Speaker concluded on a hopeful note, envisioning a prosperous future for cooperatives that contribute significantly to nation-building. He inspired the audience to embrace the cooperative spirit as a catalyst for national progress.

A view of dignitaries pay homage to the nation through the rendition of the National Anthem.

The two-day mega event celebrating cooperatives culminated with a formal vote of thanks, expressing gratitude to all participants and contributors for their invaluable insights and enthusiastic engagement. The gathering then united in unison to pay homage to the nation through the rendition of the national anthem.

The 17th Indian Cooperative Congress concluded with resounding applause and widespread appreciation from all involved, underscoring its success and meaningful impact.

अनुलग्नक - 1: कार्यक्रम अनुसूची

समय	कार्यक्रम	गतिविधि
दिनांक 01 जुलाई, 2023		
11:00 बजे	**उद्घाटन समारोह**	गणमान्य व्यक्तियों एवं अतिथियों का आगमन
11:02 बजे		लघु नाटिका "धरती कहे पुकार के" का मंच प्रदर्शन
11:10 बजे		माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन श्री बी.एल. वर्मा, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री अन्य गणमान्य व्यक्तियों श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और श्री दिलीप संघानी, अध्यक्ष, एनसीयूआई द्वारा किया गया।
11:15 बजे		श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष एनसीयूआई द्वारा स्वागत भाषण
11:20 बजे		माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का संबोधन
11:25 बजे		माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एनसीयूआई-हाट और एलएमएस पोर्टल का ई-लॉन्चिंग 1. सहकारी विपणन के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट 2. सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवाएँ - एलएमएस पोर्टल
11:26 बजे		सहकारिता पर फिल्म आत्मनिर्भर भारत "सहकार से समृद्धि"" का संकल्प
11:31 बजे		भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन भाषण
2:00 अप. से 2:30 अप.	तकनीकी सत्र - 1	अनुकूल सहकारी कानून और नीतिगत सुधार
4:00 अप. से 5:30 अप.	तकनीकी सत्र - 2	सहकारी आंदोलन को मजबूत करने हेतु क्रोस सेक्टोरल सहयोग
4:00 अप. से 5:30 अप.	तकनीकी सत्र - 3	सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य का सुदृढ़ीकरण
दिनांक 01 जुलाई, 2023		
10:00 बजे से 11:30 बजे	तकनीकी सत्र -4	प्रतिस्पर्धी सहकारी व्यावसायिक उद्यमों हेतु इज ऑफ डूइंग बिज़नेस (व्यवसाय करने में आसानी)
10:00 बजे से 11:30 बजे	तकनीकी सत्र -5	सहकारी शासन हेतु नवाचार एवं प्रौद्योगिकी
12:00 अप. से 01:30 अप.	तकनीकी सत्र -6	सहकारिता के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना
12:00 अप. से 01:30 अप.	तकनीकी सत्र -7	भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली का महत्व
03:00 अप.	समापन समारोह	गणमान्य व्यक्तियों एवं अतिथियों का आगमन
03:05 अप.		श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, भा०रा० सह०संघ का संबोधन
03:20 अप.		श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, भा०रा०सह०संघ द्वारा अतिथियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन
03:25 अप.		डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष आईसीए-एपी एवं अध्यक्ष कृभको का संबोधन
03:35 अप.		डॉ. बिजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नेफेड का संबोधन
03:45 अप.		श्री परषोत्तम रुपाला, माननीय केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री का संबोधन
04:00 अप.		डॉ. सुधीर महाजन, मुख्य कार्यकारी भा०रा० सह०संघ द्वारा 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की सिफारिशों पर प्रस्तुति
04:20 अप.		लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला का समापन भाषण जलपान ग्रहण एवं प्रस्थान

Annexure – 1: Programme Schedule

Time	Function	Activity
Date 01st July 2023		
11:00 am	Inaugural Function	Arrival of Dignitaries and Guest
11:02 am		Stage Performance of Short Skit "Dharti Kahe Pukarke"
11:10 am		Felicitation of the Hon'ble Prime Minister by Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State for Cooperation, other dignitaries Shri Amit Shah, Hon'ble Home and Cooperation Minister and Shri Dileep Sanghani, President, NCUI
11:15 am		Welcome speech by Shri Dileep Sanghani, President, NCUI
11:20 am		Address by Hon'ble Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah
11:25 am		E-launching of NCUI-Haat & LMS Portal by Hon'ble Prime Minister 1. e-commerce website for Cooperative Marketing 2. Cooperative Extension and Advisory Services – LMS Portal
11:26 am		Film on Cooperatives - Atmanirbhar Bharat 'Sahakar Se Samridhi' ka Sankalp
11:31 am		Inaugural Address by Hon'ble Prime Minister of India
2:00 pm - 2:30 pm	Technical Session- 1	Conducive Cooperative Legislation and Policy Reforms
4:00 pm - 5:30 pm	Technical Session- 2	Cross Sectoral Collaborations for Strengthening Cooperative Movement
4:00 pm - 5:30 pm	Technical Session- 3	Strengthening Cooperative Education, Training and Research
Date 02nd July 2023		
10:00 am - 11:30 am	Technical Session -4	Ease of Doing Business for Competitive Cooperative Business Enterprises
10:00 am - 11:30am	Technical Session -5	Innovation & Technology for Cooperative Governance
12:00 noon - 01:30 pm	Technical Session -6	Promoting Gender Equality and Social Inclusion through Cooperatives
12:00 noon - 01:30 pm	Technical Session -7	Importance of Cooperative Credit System in Indian Economy
03:00 pm	Valedictory Function	Arrival of Dignitaries and Guest
03:05 pm		Address by Shri Dileep Sanghani, President, NCUI
03:20 pm		Felicitation of Guests and other dignitaries by Shri Dileep Sanghani, President, NCUI
03:25 pm		Address by Dr. Chandrapal Singh Yadav, President ICA-AP & Chairman KRIBHCO
03:35 pm		Address by Dr.Bijender Singh, Chairman, NAFED
03:45 pm		Address by Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Union Minister for Animal Husbandry, Fisheries and Dairying
04:00 pm		Presentation on the Recommendations of 17th Indian Cooperative Congress by Dr. Sudhir Mahajan, Chief Executive, NCUI
04:20 pm		Valedictory address by Shri Om Birla, Hon'ble Speaker of Lok Sabha High Tea and departure

अनुलग्नक - 2: मॉडरेटरों और प्रतिवेदकों की सूची

अनुक्रमांक	तकनीकी सत्र	मॉडरेटर की सूची	प्रतिवेदकों की सूची
1	तकनीकी सत्र - 1	श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी	श्री सुरेश बाबू एस., अनुसंधान अधिकारी
		श्रीमती इंदरप्रीत कौर, सहा. निदेशक	श्री यशांक कल्याणी, अनुसंधान अधिकारी
			सुश्री वैशाली गोस्वामी, अनुसंधान सहायक
2	तकनीकी सत्र - 2	श्री सुमित सिंह, सलाहकार	सुश्री श्रुति एस.कुलकर्णी, अनुसंधान अधिकारी
		श्री पंकज गुप्ता, सहायक निदेशक	श्री नवीन कुमार सिंह, अनुसंधान अधिकारी
			सुश्री आरुषि कौल, अनुसंधान सहायक
3	तकनीकी सत्र - 3	डॉ. सागर के. वाडकर, सलाहकार	सुत्री श्रीजा सिन्हा, अनुसंधान अधिकारी
		श्री अनुराग, सहायक निदेशक	सुत्री भानु अरोड़ा, अनुसंधान अधिकारी
			सुश्री वैशाली गोस्वामी, अनुसंधान सहायक
4	तकनीकी सत्र - 4	डॉ. नवीन आनंद, सलाहकार (सहकार), एएफसी इंडिया लिमिटेड	सुश्री श्रुति एस. कुलकर्णी, अनुसंधान अधिकारी
		श्री अनंत दुबे, उप निदेशक	श्री नवीन कुमार सिंह, अनुसंधान अधिकारी
			सुश्री वैशाली गोस्वामी, अनुसंधान सहायक
5	तकनीकी सत्र - 5	श्रीमती संध्या कपूर, निदेशक	सुश्री श्रीजा सिन्हा, अनुसंधान अधिकारी
		श्रीमती वीना सचदेवा, उप निदेशक	सुश्री भानु अरोड़ा, अनुसंधान अधिकारी
			सुश्री आरुषि कौल, अनुसंधान सहायक
6	तकनीकी सत्र - 6	श्री बिनोद आनंद, महासचिव सीएनआरआई	श्री सुरेश बाबू एस., अनुसंधान अधिकारी
		श्रीमती दीप्ति यादव, सहायक निदेशक	श्री यशांक कल्याणी, अनुसंधान अधिकारी
			सुश्री वैशाली गोस्वामी, अनुसंधान सहायक
7	तकनीकी सत्र - 7	श्री सुभाष गुप्ता, सलाहकार	सुश्री श्रुति एस. कुलकर्णी, अनुसंधान अधिकारी
		श्री प्रियांक सिंह, सहायक निदेशक	श्री नवीन कुमार सिंह, अनुसंधान अधिकारी
			सुश्री आरुषि कौल, अनुसंधान सहायक

Annexure - 2: List of Moderators and Rapporteurs

Sr. No	Technical Session	List of ModeratorsList of Moderators	List of Rapporteurs
1.	Technical Session-1	Smt. Savitri Singh, Deputy Chief Executive	Shri. Suresh Babu S., Research Officer
		Smt. Inderpreet Kaur, Assistant Director	Shri. Yashank Kalyani, Res. Officer
			Ms. Vaishali Goswami, Res. Assistant
2.	Technical Session-2	Shri Sumit Singh, Adviser	Ms. Shruti S. Kulkarni, Res. Office
		Shri Pankaj Gupta, Assistant Director	Shri. Naveen Kumar Singh, Res. Officer
			Ms. Arushi Kaul, Res. Assistant
3.	Technical Session-3	Dr. Sagar K. Wadkar, Adviser	Ms. Shrija Sinha, Res. Officer
		Shri Anurag, Assistant Director	Ms. Bhanu Arora, Res. Officer
			Ms. Vaishali Goswami, Res. Assistant
4.	Technical Session-4	Dr. Naveen Anand, Consultant (Cooperation), AFC India Ltd.	Ms. Shruti S. Kulkarni, Res. Officer
		Shri Anant Dubey, Dy. Director	Shri. Naveen Kumar Singh, Res. Officer
			Ms. Vaishali Goswami, Res. Assistant
5.	Technical Session-5	Smt. Sandhya Kapoor, Director	Ms. Shrija Sinha, Res. Officer
		Smt. Veena Sachdeva, Dy. Director	Ms. Bhanu Arora, Res. Officer
			Ms. Arushi Kaul, Res. Assistant
6.	Technical Session-6	Shri Binod Anand, Secretary General CNRI	Shri Suresh Babu S., Res. Officer
		Smt. Deepti Yadav, Assistant Director	Shri. Yashank Kalyani, Res. Officer
			Ms. Vaishali Goswami, Res. assistant
7.	Technical Session-7	Shri Subhash Gupta, Adviser	Ms. Shruti S. Kulkarni, Res. Officer
		Shri Priyank Singh, Assistant Director	Shri. Naveen Kumar Singh, Res. Officer
			Ms. Arushi Kaul, Res. Assistant